



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY,

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY



सं० 47]
No. 47]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 1, 1988/फाल्गुन 11, 1909
NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 1, 1988/PHALGUNA 11, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि वह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as
a separate compilation

वित्त मंत्रालय
(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 मार्च, 1988

सं. 15 (35)—बी(डी)/87:—निम्नलिखित सर्व साधारण
की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाता है:—

बजट 1988-89

वित्त मंत्री

श्री नारायणदत्त तिवारी

का भाषण

29 फरवरी, 1988

भाग क

महोदय,

मैं वर्ष 1988-89 का बजट प्रस्तुत करता हूँ।

2. वर्ष 1987-88 की आर्थिक समीक्षा कुछ दिन पहले
सदन के सम्मुख प्रस्तुत की गई थी और उसमें भारतीय
अर्थव्यवस्था की पिछले वर्ष की प्रवृत्तियों का विस्तृत लेखा-
जोखा दिया गया है। इस वर्ष आर्थिक कार्य-निष्पादन और
प्रबन्ध पर सूखे और बाढ़ों की प्राकृतिक विपदाओं का असर
छाया रहा। इस वर्ष का सूखा इस शताब्दी के सबसे भयंकर
सूखों में से एक था, जबकि देश के 35 मौसम वैज्ञानिक
उप-प्रभागों में से 21 उप-प्रभागों में मानसून के महीनों में
अल्प अथवा अत्यल्प वर्षा हुई। अधिकतर पूर्वी राज्यों में
समस्या अल्प-वृष्टि की नहीं, बल्कि अति-वृष्टि की थी, जिसके
परिणामस्वरूप विनाशकारी बाढ़ें आईं। इससे भी खराब बात
यह थी कि सूखे और बाढ़ों के इस वर्ष से पहले के लगातार
तीन वर्षों में भी वर्षा कम हुई थी।

3. अत्यन्त गंभीर दबावों और कठिनाइयों के बावजूद,
अर्थव्यवस्था ने उल्लेखनीय लचीलापन प्रदर्शित किया है।
ऐसा दो अनुकूल कारणों से हो सका है। पहला यह कि

पिछले वर्षों में हमारी अर्थव्यवस्था का जो निरन्तर विकास और विविधीकरण हुआ है उससे अस्थायी आघातों को सहन करने की क्षमता पैदा हुई है। दूसरे, सरकार ने सूखे के कारण समाज पर पड़ने वाले आर्थिक बोझ व अन्य दवावों को हटका करने के लिए व्यापक पैमाने पर और ठीक समय पर कदम उठाए हैं।

4. सरकार ने खाद्यान्नों के संकट-रोधक भंडार बनाने की जिस नीति का अनुसरण किया उसके फलस्वरूप हमें भारी मात्रा में खाद्यान्नों का भंडार निर्मित करने में सफलता मिली और 1 जुलाई, 1987 को यह भंडार 2.3 करोड़ मीट्रिक टन का था। इस भंडार की सहायता से समूचे देश में, विशेष रूप से सूखा-प्रभावित क्षेत्रों में, खाद्यान्नों की पर्याप्त सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए व्यापक और सतत प्रयत्न किए गए। सूखे का सामना करने के अन्य महत्वपूर्ण सरकारी कार्यक्रमों में ये कार्यक्रम भी शामिल हैं : राहत प्रदान करने और रोजगार का सृजन करने वाले कार्यों का व्यापक विस्तार, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाना, पेय जल, चारे और बिजली-पूर्ति की कमी को पूरा करने के लिए विशेष प्रयास, खरीफ के मौसम में वैकल्पिक फसलें उगाने और रबी-उत्पादन को बढ़ाने की कार्य-योजनाएं, पशुओं की रक्षा के उपाय और खाद्य तेलों तथा दानों जैसी आवश्यक वस्तुओं का बड़े पैमाने पर आयात। पूर्ति संबंधी इन उपायों को सुविचारित राजकोषीय और मौद्रिक नीतियों से सुदृढ़ बनाया गया ताकि सरकारी निवेश कार्यक्रम में कटौती किए बिना, राहत कार्यों पर होने वाले खर्च के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराए जा सकें।

5. इन सतत प्रयत्नों के फलस्वरूप, आर्थिक कार्य-निष्पादन के निर्देशक बिन्दु, कुल मिला कर, भीषण सूखे के पिछले किसी भी वर्ष की तुलना में बेहतर रहे हैं। इस प्रकार, कृषि उत्पादन में कमी होने के बावजूद 1987-88 में सकल राष्ट्रीय उत्पादन में 1 से 2 प्रतिशत तक की वृद्धि होने की संभावना है, जबकि इसके विपरीत 1979-80 में 4.7 प्रतिशत की कमी हुई थी। उपलब्ध आंकड़ों से पता चलता है कि अप्रैल—नवम्बर 1987 के दौरान औद्योगिक उत्पादन में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 10.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसके विपरीत, 1979-80 के सूखे के वर्ष में औद्योगिक उत्पादन में 1.7 प्रतिशत की गिरावट आई थी। चालू वित्तीय वर्ष में महंगाई की समूची दर, थोक कीमतों के सूचकांक के अनुसार 6 फरवरी, 1988 को 9.8 प्रतिशत थी, जबकि इसकी तुलना में 1979-80 में यह दर 21 प्रतिशत से भी अधिक थी। आवश्यक वस्तुओं की कीमतों की प्रवृत्तियों पर केन्द्र और राज्यों के स्तर पर कड़ी नजर रखी जा रही है और मैं जिला स्तर पर भी इस हेतु नियंत्रण कक्ष स्थापित करने के लिए राज्य सरकारों को धन्यवाद देना चाहूंगा। हमें सभी स्तरों पर कीमतों पर लगातार निगरानी रखनी होगी ताकि मुद्रास्फीति पर नियंत्रण रखा जा सके।

6. सूखे और बाढ़ के कारण उत्पन्न दवावों से हमारी अर्थ-व्यवस्था की अन्तर्निहित मुद्दना और गाय ही कुछ समस्याओं का भी पता चला है। मानसून के लगातार असफल हो जाने पर भी, हमारी कृषि-व्यवस्था ने अपनी बुनियादी दृढ़ता का परिचय दिया है। हमें अपने किसानों पर गर्व है। पिछले वर्षों के दौरान अपने कठिन परिश्रम और दृढ़ संकल्प से उन्होंने पर्याप्त खाद्यान्न का उत्पादन किया जिससे कि हम खाद्यान्न का काफी भंडार बना सके। इससे हमें खाद्यान्न के बिना किसी घोर अभाव के तथा अपनी अर्थ-व्यवस्था को अधिक क्षति पहुंचाए बिना वर्तमान सूखे का सामना करने में बहुत मदद मिली।

7. वर्ष 1984-85 से लगातार चार वर्षों में औद्योगिक उत्पादन में 8 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि होगी। हमारे आधारभूत ढांचे का कार्यनिष्पादन संतोषजनक रहा है। ताप विद्युत के उत्पादन ने पन-विजली के उत्पादन में आई कमी को पूरा कर दिया है और कुल मिलाकर चालू वर्ष के पहले 9 महीनों में विद्युत के उत्पादन में 7.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। रेलवे में उत्पादकता में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। कोयले के उत्पादन में अप्रैल में दिसम्बर 1987 तक की अवधि में 10.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इन विभागों में सार्वजनिक क्षेत्र (पब्लिक सेक्टर) में हुई यह प्रगति काफी संतोष का विषय है और सरकार द्वारा शुरू की गई नीतियों के सफल कार्यान्वयन का द्योतक है। हमारे श्रमिकों के कठोर परिश्रम की वजह से ही यह संभव हो पाया है और राष्ट्र उनका आभारी है। सरकार सशक्त और गतिशील सार्वजनिक क्षेत्र (पब्लिक सेक्टर) की मजबूती को सर्वोच्च महत्व देती है।

8. निर्यात में पिछले दो वर्षों में भारी वृद्धि हुई है। वर्ष 1986-87 में 15 प्रतिशत की वृद्धि होने के बाद, चालू वर्ष के पहले नौ महीनों में निर्यात में पिछले वर्ष को इसी अवधि की तुलना में लगभग 25 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसी अवधि में आयात में 14 प्रतिशत से भी कम की वृद्धि हुई। व्यापार वाटे में पिछले दो वर्षों के दौरान कमी हो रही है।

9. तथापि, हमें कोई शिथिलता नहीं बरतनी चाहिए। भविष्य पर दृष्टि रखते हुए हमें आर्थिक मोर्चे पर सामने आई कुछ समस्याओं के समाधान के लिए निश्चयपूर्वक कार्य करना चाहिये। लगातार चार वर्षों से कम वर्षा होने के कारण, हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में काफी कठिनाइयां पैदा हुई हैं, कृषि उत्पादन घटा है और दिनाम की गति पर प्रभाव पड़ा है। इसलिए हमें सातवीं आयोगिता के शेष वर्षों में कृषि पर खाम तौर पर बल देना है।

10. कृषि के क्षेत्र में हमारा कार्य-निष्पादन बहुत अच्छा रहा है। किन्तु सूखे और बाढ़ों के फलस्वरूप कुछ ऐसे मुद्दे सामने आए हैं, जिन पर तत्काल ध्यान देने की जरूरत है।

प्रधान मंत्री ने यह निर्देश दिया है कि योजना आयोग द्वारा तुरन्त ही एक कार्य-योजना तैयार की जाए जिसके अन्तर्गत उन क्षेत्रों का निर्धारण किया जाए जहाँ और उपाय करने से उत्पादन में जल्द वृद्धि हो सकती है। 1987-88 में सूखाग्रस्त राज्यों में सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए 236 करोड़ रुपये का अतिरिक्त आवंटन किया गया है। अगले वर्ष कृषि और सिंचाई के संबंध में केन्द्र के आयोजना परिव्यय में 40 प्रतिशत की वृद्धि की जा रही है। यदि आवश्यक हुआ तो सरकार 1988-89 के समूचे आयोजना परिव्यय के अन्तर्गत पुनरावंटन करेगी और कृषि लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अधिक संसाधनों की व्यवस्था करेगी।

11. हमने औद्योगिक विकास के क्षेत्र में बहुत प्रगति की है जो निवेश और उत्पादन को प्रोत्साहित करने तथा प्रौद्योगिकीय (टैक्नोलॉजिकल) उन्नयन को बढ़ावा देने की सरकार की नीतियों की सफलता की परिचायक है। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यह गति बनी रहे। लागत और कीमतों को घटाए जाने की आवश्यकता है। भारतीय उद्योगों को और अधिक प्रतिस्पर्द्धी बनाया जाना चाहिए। उद्योग में रणगता एक बड़ी समस्या है। हमें रणगता का निदान करने के लिए और कदम उठाने होंगे। हमें कार्य-कुशलता का उन्नयन करना चाहिए, कामगारों को प्रशिक्षण देना चाहिए और प्रबंध में भी सुधार करना चाहिए। औद्योगिक विकास के लिए हमें अपने प्रचुर संसाधनों, जैसे कि लोगों के कौशल का भरपूर उपयोग करना चाहिए। रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए उद्योग का तेजी से विकास जरूरी है।

12. लघु, ग्राम और खादी उद्योगों का हमारे आर्थिक विकास में विशेष स्थान है। ये उद्योग स्थानीय रूप से उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करते हैं और छोटे कस्बों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में, जहाँ हमारी अधिकांश जनता रहती है, रोजगार के अवसर पैदा करने में महत्वपूर्ण योग देते हैं। पैंतीस वर्ष पहले इस सदन में बोलते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्र को भी संबोधित करते हुए यह कहा था :

“मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि हम इस देश में प्रमुख उद्योगों का विकास किए बगैर लोगों के जीवन स्तर में सुधार नहीं कर सकते, वस्तुतः मैं तो यहां तक कहूंगा कि हम उनके बगैर अपनी स्वतंत्रता भी कायम नहीं रख सकते लेकिन हमें सदा याद रखना चाहिए कि मात्र भारी उद्योगों के विकास से इस देश के लाखों लोगों की समस्या हल नहीं हो जाएगी। हमें ग्रामीण और कुटीर उद्योगों का बड़े पैमाने पर विकास करना होगा, और साथ ही यह भी सुनिश्चित करना होगा कि बड़े और छोटे उद्योगों का विकास करने के प्रयासों में हम मानवीय पहलू को न भूल जाएं।”

यही समग्र विचारधारा हमारा निरन्तर मार्गदर्शन कर रही है।

13. राजस्व में वृद्धि करने, कर अनुपालन में सुधार लाने व आर्थिक कानूनों को लागू करने के लिए सरकार बहुत से उपाय करती रही है। इनके अच्छे परिणाम निकले हैं और विगत तीन वर्षों के दौरान राजस्व में पर्याप्त संतोषजनक वृद्धि हुई है। तथापि, खर्च में तेजी से वृद्धि होने के कारण राजकोषीय स्थिति पर बहुत दबाव पड़ा है। हमें रक्षा, विकास, सामाजिक सेवाओं, राहत कार्यक्रमों और खाद्य तथा उर्वरक सप्लायी जैसी मदों पर अपरिहार्य बाध्यताओं के कारण अधिक खर्च करना पड़ रहा है। राष्ट्र को इस बढ़ते हुए खर्च को समस्या का गंभीरता से समाधान करना चाहिए।

14. जैसा कि पूर्वोक्तमान था, भुगतान-संतुलन की स्थिति को देखते हुए राष्ट्र के विदेशी-मुद्रा कोष पर अनेक कारणों से दबाव पड़ता रहा है। इनमें खाद्य तेलों और दालों का अधिक मात्रा में आयात, कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के आयात में वृद्धि, विदेशों में बढ़ती हुई संरक्षणवादी प्रवृत्तियों और सरकारी विकास सहायता के लिए प्रतिकूल वातावरण शामिल है। अन्तर्राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था में उथल-पुथल, मुद्राओं के विनिमय दरों में उतार चढ़ाव और विश्व व्यापार की धीमी प्रगति के कारण भी विकासशील देशों के लिए वातावरण पर बुरा प्रभाव पड़ा है। इन प्रतिकूल परिस्थितियों के प्रभाव का कम करने के लिए हमने निर्णय को बढ़ाते तथा प्रायास की वृद्धि को कम करने के लिए प्रभावकारी प्रयास किए। इन प्रयासों में और भी तेजी लानी होगी।

15. भारत ने ऋण-अवस्थ में विवेकपूर्ण नीति का पालन किया है और उन समस्याओं से बचने की कोशिश की है जो अनेक विकासशील देशों को पेश आ रही है। हम अपने भुगतान-संतुलन को दीर्घकालीन सक्षमता को सुनिश्चित करने के प्रति वचनबद्ध हैं।

16. हमारे सामने बहुत सी चुनौतियां हैं और हम कठिन परिश्रम, निराला तथा त्याग से ही एक आत्म निर्भर सुदृढ़ तथा मजबूत अर्थव्यवस्था का निर्माण कर सकते हैं। एक विभिन्न राजनैतिक कार्यकर्ता के नाते मुझे इस बात का अहसास है कि यही हमने प्राथमिकता प्राप्ति की है, फिर भी देशवासियों को स्थिति को सुधारने के लिए, विशेष रूप से ग्रामीण जनता को स्थिति को सुधारने के लिए, अभी बहुत काम करना बाकी है।

17. इन बातों के द्वारा मेरा यह प्रस्ताव है कि कुछ संसाधनों की सीमाओं के अन्दर, किसानों को लाभ पहुंचाने, लघु तथा ग्राम उद्योगों को प्रोत्साहित करने, गरीब लोगों को राहा प्रदान करने तथा और अधिक रोजगार का सृजन करने व देशवासियों के लिए स्वरोजगार के अवसरों की व्यवस्था करने के लिए बहुत से कदम उठाए जाएं। तदनुसार ऋणित ग्राम विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम जैसे गरीबी-विरोधी कार्यक्रमों को सुदृढ़ बनाने के अलावा,

सरकार ने खेती के लिए कृषि ऋण की उपलब्धि बढ़ाने, संस्थागत ढांचे को सुदृढ़ बनाने, समाज के कमजोर वर्गों, विशेष रूप से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों के लिए अधिक विकास व्यवस्था करने व ग्रामीण निर्धनों के लिए बेहतर आवास-व्यवस्था करने के लिए बहुत से कदम उठाने का निर्णय किया है। हालांकि इनमें से कुछ कार्यक्रमों के लिए अतिरिक्त परिषदों की व्यवस्था करना जरूरी है, लेकिन बहुत से मौजूदा कार्यक्रमों को नई दिशा देकर और उन्हें पुनर्गठित कर अपने इन उद्देश्यों को बेहतर ढंग से पूरा करने का मेरा प्रस्ताव है।

18. कृषि क्षेत्र में किए जाने वाले उपायों का निर्धारण करते समय हमने प्रधान मंत्री द्वारा दिए गए निम्नलिखित मार्ग निर्देशों को ध्यान में रखा है, जो उन्होंने अभी कुछ दिन पहले किसानों को संबोधित करते हुए दिए थे, अर्थात्:—

“कृषि को अगले दो-तीन सालों में एक जोरदार नया प्रोत्साहन दिया जाए जिसमें छोटे सीमान्त किसानों, भूमिहीन मजदूरों और ग्रामीण दस्ताकारों पर खास ध्यान दिया जाए। हमारी यह भी कोशिश हो कि ऐसी जो भी योजना देहात के विकास के लिए बने, वह देश के हर हलके के लिए ही नहीं बल्कि देहात में हर तबके के लिए भी बने। इससे पूरे समाज की ताकत बनेगी, पूरे समाज को इसका लाभ मिलेगा और पूरा समाज आगे बढ़ेगा।”

19. सूखे की वजह से हमारे किसानों की वित्तीय स्थिति पर प्रभाव पड़ा है। ऋणों की वापसी अदायगी के कार्यक्रम को पुनर्निर्धारित करने, अल्पकालीन ऋणों को सावधिक (टर्म लोन) ऋणों में परिवर्तित करने और कुछ मामलों में ब्याज की दरों में कमी करने जैसे बहुत से उपाय पहले ही किए जा चुके हैं। मुझे सदन को सूचित करते हुए प्रसन्नता है कि इस दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम के रूप में कृषि ऋण की लागत को कम करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक आज हिदायतें जारी कर रहा है। 7500 रुपये तक के सभी फसल ऋणों पर ब्याज की दर में 1-1/2 प्रतिशत से लेकर 2-1/2 प्रतिशत तक की कमी की जा रही है। अब 7500 रुपये तक के ऋणों पर ब्याज की दर 11.5 प्रतिशत और 12.5 प्रतिशत के वर्तमान स्तरों की तुलना में घटकर 10 प्रतिशत रह जाएगी। इसी प्रकार से 7500 रुपये से ऊपर और 15,000 रुपये तक के फसल ऋणों के संबंध में ब्याज की दर को, जो अब 12.5 प्रतिशत से 14 प्रतिशत तक है, कम करके 11.5 प्रतिशत कर दिया जाएगा। ब्याज की दरों में इस कटौती के फलस्वरूप सहकारी क्षेत्र, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा करोड़ों ऋण-प्राप्तकर्ता किसानों को लाभ पहुंचेगा और उन्हें चिर अपेक्षित राहत प्राप्त होगी।

20. कम लागत पर खेती के लिए उपलब्ध कुल ऋण की धनराशि को बढ़ाने के लिए, यह भी निर्णय किया गया है कि सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा देश की कृषि को सीधे दिए जाने वाले ऋण वित्त के लक्ष्य को बढ़ा कर, वर्ष 1988-89 के अन्त तक उनके कुल बकाया अग्रिमों के 17 प्रतिशत तक कर दिया जाए। इस प्रकार, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों द्वारा किए जाने वाले अतिरिक्त प्रयासों को जोड़ते हुए, 1988-89 में बैंकों द्वारा देश की कृषि को सीधे दिए जाने वाले ऋणों के लक्ष्य में 3,000 करोड़ रुपये से भी अधिक की वृद्धि हो जायेगी।

21. खेती की लागत में और कमी करने के लिए, सरकार सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों की उर्वरक कम्पनियों से यह कहेगी कि वे आगामी खरीफ और रबी की बुवाई के लिए खाद की अधिसूचित कीमतों पर 7.5 प्रतिशत की छूट दें। इसके फलस्वरूप यूरिया के एक बोरे की कीमत में लगभग आठ रुपये अस्सी पैसे की कमी हो जाएगी। कम्पनियां बेहतर भण्डार प्रबंध के जरिए इस छूट की लागत को वहन करने में समर्थ होगी। मुझे विश्वास है कि हमारे उद्यमी किसान इस छूट का फायदा उठाएंगे और कृषि उत्पादन को बढ़ाएंगे।

22. फसलों को क्षतिग्रस्त होने से रोकने और हमारे खेतों की उत्पादकता में वृद्धि करने में कीटनाशक और खर-पतवार नाशक दवाओं का समय पर उपयोग करने की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। उनकी लागत कम करने के उद्देश्य से, मैं बाद में अपने भाषण में चुनी हुई कीटनाशक/खर-पतवार नाशक दवाओं और साथ ही कुछ संबन्धित मध्यवर्ती वस्तुओं के आयात-शुल्क में कमी करने की घोषणा करूंगा। इसके साथ-साथ खेती के लिए महत्वपूर्ण समझी जाने वाली चुनी हुई कीटनाशक दवाओं को, नामांकित किए जाने वाले सहकारी संगठनों व राज्य सरकारों के प्रतिष्ठानों द्वारा मुक्त रूप से आयात किए जाने की अनुमति दी जाएगी। इससे यह सुनिश्चित होगा कि इन कीटनाशकों के मौजूदा निर्माता विक्री में एकाधिकारवादी तरीकों का अनुसरण न करें। इस उपाय से हमारे किसानों को सहायता मिलेगी।

23. भारतीय रिजर्व बैंक, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबाडे), भारतीय स्टेट बैंक और वाणिज्यिक बैंकों के परामर्श से मुझे ग्रामीण ऋणों से संबन्धित एक नई नीति की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है, जिसका उद्देश्य इस देश के प्रत्येक गांव की ऋण संबंधी आवश्यक जरूरतों को पूरा करना है। वाणिज्यिक बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की कुल मिलाकर 40,000 से अधिक शाखाएं देश के ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में स्थित हैं। देश के गांवों की संख्या 5,76,000 से ज्यादा है। प्रस्तावित व्यवस्था के अन्तर्गत देश के बैंकों की प्रत्येक शाखा को निर्धारित योजना के अनुसार 'सर्विस एरिया' के रूप में शाखा के

निकटवर्ती लगभग 15 से 25 गांवों को ऋण-कारोबार की सेवाएं प्रदान करनी होगी। प्रत्येक शाखा मुख्य रूप से अपने सेवा क्षेत्र की ऋण संबंधी उचित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जिम्मेदार होगी। यह देश-व्यापी व्यवस्था, जिसका संचालन पहले से ही चालू जिला लीड बैंक योजना के पर्यवेक्षण में किया जाएगा और जिसे ग्रामीण सहकारी समितियों के माध्यम से पूरक समर्थन प्रदान किया जाएगा, ग्रामीण जनता की ऋण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने में बहुत कारगर सिद्ध होगी।

24. सूखे से प्रभावित किसानों की सहायता करने के लिए हमने ऋणों को चुकाने के कार्यक्रम का पुनर्निर्धारण करके, सभी प्रासंगिक वसूलियों को स्थगित करके और व्याज दरों को घटाकर बहुत सी राहतें और रियायतें दी हैं। देश के किसानों और सहकारिता आन्दोलन की एक अरसे से यह मांग रही है कि सुनियोजित आधार पर राहत प्रदान करने के लिए अलग से एक 'राष्ट्रीय कृषि ऋण राहत कोष' की स्थापना की जाए। मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि अब एक ऐसा कोष स्थापित करने का निर्णय ले लिया गया है। इस कोष के लिए धन की व्यवस्था केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों द्वारा पारस्परिक परामर्श द्वारा की जाएगी। इस कोष से धन देने के मानदंड भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तैयार किए जाएंगे।

25. अन्य मामलों की चर्चा करने से पहले, मैं एक ऐसे विषय का उल्लेख करना चाहूंगा, जिसमें हम सबकी हार्दिक दिलचस्पी है। मैं महसूस करता हूं कि सहकारी ऋण-प्रणाली का, जिसने हमारी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के प्रारम्भिक वर्षों में हरावल दस्ते की भूमिका निभाई, वांछित विकास होना अभी शेष है। सहकारी समितियां किसानों तक पहुंचने का सर्वोत्तम साधन हैं। वे ग्रामीण स्तर पर स्वावलम्बन की प्रतीक भी हैं। मेरा विचार है कि हमें समूची सहकारी ऋण प्रणाली को नया जीवन प्रदान करने की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे इस मामले पर वैयक्तिक रूप से ध्यान दें और इस बारे में मुझे सुझाव भेजें कि सहकारिता आन्दोलन के विकास को बढ़ावा देने में भारतीय रिजर्व बैंक, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबाड) और राष्ट्रीयकृत बैंकों को क्या भूमिका निभानी चाहिए। मैं इस बारे में राज्य सरकारों को भी लिखूंगा, जिनकी इस क्षेत्र में प्रमुख जिम्मेदारी है।

26. ग्रामीण विद्युतीकरण के कार्यक्रम के परिणामस्वरूप बिजली के पम्प सेटों की सहायता से सिंचाई के लिए देश भर में भूमिगत जल का उपयोग किया जाने लगा है। लेकिन बहुतेरे गरीब किसान आम तौर पर पम्प सेट लगाने पर एक दफा आने वाली लागत उठाने में असमर्थ रहते हैं। सूखा प्रभावित क्षेत्रों में सीमान्त (मार्जिनल) किसानों को सहायता प्रदान करने के लिए 'जलधारा' नामक एक विशेष

कार्यक्रम चलाया जाएगा। इस स्कीम से उन्हें नाममात्र किराए/पट्टा प्रभारों पर सिंचाई के लिए पम्प सेटों के लाभ प्रदान किए जाएंगे। 1988-89 के दौरान इस योजना के लाभ लगभग ऐसे 50,000 किसान परिवारों को उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है।

27. हरिजन और आदिवासी परिवारों सहित गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले ग्रामीण परिवारों के जीवन स्तर को सुधारने के उद्देश्य से, मेरा उनके परिवारों को बिजली के एक पाइंट का कनेक्शन देने का 'कुटीर ज्योति' नामक एक व्यापक कार्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत एक पाइंट कनेक्शन पर अन्दरूनी तार और सर्विस कनेक्शन लगाने पर एक बार आने वाली लागत को पूरा कर दिया जाएगा। वर्ष 1988-89 में 5 लाख परिवारों को इस कार्यक्रम के अन्तर्गत बिजली देने का प्रस्ताव है। 'जलधारा' और 'कुटीर ज्योति' इन दोनों कार्यक्रमों की लागत को ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा राज्य बिजली बोर्डों को मिश्रित अनुदान और ऋण देकर पूरा किया जाएगा।

28. पर्वतीय क्षेत्रों (हिल एरियाज) में रहने वाले लोगों को मिट्टी के तेल और एल. पी. जी. की सप्लाई में परिवहन की ऊंची लागत का भार उठाना पड़ता है। आजकल उत्तर-पूर्वी राज्यों तथा जम्मू और कश्मीर को मिट्टी के तेल पर भाड़ा सम्बन्धी सब्सिडी दी जाती है। अब यह रियायत सभी पर्वतीय (हिल) क्षेत्रों को देने का फैसला किया गया है। इस प्रकार यह भी फैसला किया गया है कि सभी पहाड़ी क्षेत्रों में ग्राहकों को एल. पी. जी. सिलिण्डर उसी कीमत पर सप्लाई किए जाएंगे जिस पर मैदानों में उनके निकटतम स्थल के ग्राहकों को सप्लाई किए जाते हैं। इससे एक बड़ी सीमा तक, रोशनी और ईंधन के प्रयोजनों के लिए इस्तेमाल में लाए जाने वाले वन साधनों को सुरक्षित रखने में भी सहायता मिलेगी।

29. प्रधान मन्त्री ने पिछले वर्ष अपने वजट भाषण में आवास क्षेत्र की उच्च प्राथमिकता पर बल दिया था और इस निश्चय की घोषणा की थी कि 100 करोड़ रुपए की प्रारम्भिक रू. जी. से एक राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना की जाएगी। अपेक्षित कानून पारित कर दिया गया है, और बैंक शीघ्र ही काम करना शुरू कर देगा। ग्रामीण आवास निर्माण को विशेष गति प्रदान करने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक, कुछ वित्तीय संस्थाओं के साथ मिल कर, राष्ट्रीय आवास बैंक को 100 करोड़ रुपए का विशेष अतिरिक्त योगदान देगा। यह सारी अतिरिक्त राशि ग्रामीण आवास निर्माण को कई तरीकों से बढ़ावा देने के लिए इस्तेमाल की जाएगी, जिसमें आवश्यकता पड़ने पर, विशेष ग्रामीण आवास विकास से संबंधित वचत और ऋण संस्थाओं की स्थापना करना भी शामिल है।

30. इस संदर्भ में किसानों के लिए आवास निर्माण के वास्ते वित्त प्रदान करने के क्षेत्र में भूमि विकास बैंकों को भी योगदान हेतु अधिकृत करने का प्रस्ताव है। अधिकतर जिलों में

ये बैंक विद्यमान हैं, उनके सुदृढ़ शीर्ष बैंक भी कार्यरत हैं और ग्रामीण जनता के साथ उनका सीधा सम्पर्क है। ये आवास-वित्त के लिए संसाधन भी जुटा सके हैं। राज्य सरकारों से अनुरोध किया जाएगा कि ये भूमि विकास बैंकों को आवासन सम्बन्धी वित्तपोषण का काम हाथ में लेने की अनुमति प्रदान करने के लिए अपेक्षित कानून बनाएं।

31. 700 रुपए तक की मासिक आमदनी वाले छोटे और सीमान्तिक किसानों के लिए आवास और ग्रामीण विकास निगम (हुडको) द्वारा आवास का एक नया कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 'हुडको' मकान के निर्माण अथवा उसमें सुधार के लिए 7 प्रतिशत व्याज की कम दर पर विनिर्दिष्ट राशियों तक की सहायता देगा और यह राशि 22 वर्ष में चुकाई जा सकेगी। पुराने मकानों में सुधार करने के लिए भी सहायता दी जाएगी, उदाहरणार्थ घास-फूस को छतों को टाइलों वाली छतों में बदलने के लिए।

32. उत्प्रेक्षित आवास स्कीमों के अलावा, इस वर्ष हुडको द्वारा ग्रामीण आवासीय पर्यावरण सुधार स्कीम नामक एक नई स्कीम शुरू की जाएगी। ग्रामीण आवासीय के आधारभूत ढांचे, जैसे जल-निर्वाह, सफाई, आदि में सुधार करने के लिए 5,000 तक आवासीय बांधू गांवों में 2000 रुपए प्रति परिवार तक व्यय वाली परियोजनाओं के लिए सहायता दी जाएगी। इन कार्यक्रमों के वित्तपोषण में सहायता देने के लिए हुडको के इक्विटी आधार को समुचित रूप में सुदृढ़ बनाया जाएगा।

33. वाणिज्यिक बैंक भी ग्रामीण आवास के लिए सीधे तथा हुडको के माध्यम से सहायता प्रदान कर रहे हैं। वाणिज्यिक बैंकों की भूमिका का, जिनकी शाखाओं का व्यापक जाल ग्रामीण क्षेत्रों में फैला हुआ है, और अधिक विस्तार किया जाना चाहिए। गान्धीय सदस्यों को यह जानकारी प्रसन्नता होगी कि यह फैसला किया गया है कि वाणिज्यिक बैंक आवास क्षेत्रों के लिए आने वाले ऋणदान को बढ़ाकर सान्नीय आयोजना के अन्तर्गत 300 करोड़ रुपए के वार्षिक स्तर तक कर देंगे।

34. मकान-निर्माण के लिए कम लागत वाली स्थानीय सामग्री के इस्तेमाल की बहुत गुंजाइश है। हमारे वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने भी मकान-निर्माण की कम लागत वाली आवास प्रायोगिकी में काफी विशेषज्ञता विकसित की है। निर्माण अथवा 'निर्मित' केन्द्रों के एक राष्ट्रीय 'नेटवर्क' की स्थापना करने का फैसला किया गया है, जो लोगों की मकान-निर्माण के लिए सस्ती सामग्री और तकनीक सरलता से संयुचित व उपलब्ध करा सकेंगे। देश के प्रत्येक जिले में एक केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है। आगामी वर्ष में ऐसे 100 केन्द्र स्थापित किए जायेंगे।

35. जब ग्रामीण क्षेत्रों में अग्निकांड से गरीब परिवारों, भूमिहीन मजदूरों और दस्ताकारों की झोपड़ियों और सामान नष्ट हो जाता है तो उन्हें तत्कालीन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मुझे सदन को यह सूचित करते हुए प्रसन्न हो रही है कि उन्हें अग्नि बीमा सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक नयी योजना

शुरू करने का प्रस्ताव है। भारत सरकार प्रीमियम की समूची लागत वहन करेगी। इस योजना की भारतीय जनसंघारण बीमा निगम तथा इसकी चार सहायक कम्पनियों द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा। भारतीय संघारण बीमा निगम योजना के व्ययों को घोषणा अलग से करेगा।

36. मेरा प्रस्ताव समाज के अधिकतम कमजोर वर्गों के संबंध में सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लागू करने के लिए एक प्रमुख नया काम उठाने का भी है। भारतीय जीवन बीमा निगम, जिसने देश के एक छोर से दूसरे छोर तक बीमे की भावना का प्रसार करने में बहुत काम किया है, 100 करोड़ रुपए की राशि से एक अलग 'सामाजिक सुरक्षा कोष' की स्थापना करेगा। इसे सम्भव बनाने के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा देय आयकर में कुछ परिवर्तन किए जा रहे हैं। इस कोष का इस्तेमाल समाज के अधिकतम कमजोर वर्गों के लिए मस्ती दरों पर जीवन बीमा की स्कीमों के वित्तपोषण के लिए किया जाएगा। सदन मुझे सहमत होगा कि इस कोष के निर्माण से देश के श्रमजीवी वर्गों, जैसे भूमिहीन मजदूरों, हथकरघा बुनकरों, शिक्षा-बालकों, इलाक़ों आदि को, जो दिहाड़ी पर काम करते हैं अथवा को यश-कदा मजदूरी पर काम करते हैं को, बीमा सेवा प्रदान करने के लिए ठोस संभावना हो जाएगी। इन समूह बीमा स्कीमों के संबंध में पात्र बीमाकर्ताओं के 50 प्रतिशत प्रीमियम का मुगलन इस नव-निर्मित सामाजिक सुरक्षा कोष में से किया जाएगा और शेष 50 प्रतिशत प्रीमियम संबंधित बीमाकर्ता को अदा करना होगा।

37. निर्मित आमदनी वाले समूहों, जैसे प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों, सहकारी दुग्ध उत्पादकों और दुग्धानों तथा वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों के लिए भी समूह बीमा स्कीमों शुरू की जाएंगी। दस्ताकारों, दलितों, नाइयों, राजमिस्त्रियों और वक़्दियों तथा ऐसे ही अन्य समूहों के लाभ के लिए भी बीमा योजनाएं बनाई जाएंगी।

38. हालांकि एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत गरीब परिवारों को लाभ प्रदान किए जाते हैं, लेकिन परिवार के मुखिया का अचानक देहांत होने की स्थिति में इन परिवारों की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। परिवारों को और अधिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए, जीवन बीमा निगम द्वारा एक समूह बीमा स्कीम शुरू करने का प्रस्ताव है, जिसके अन्तर्गत 1-4-1988 से प्रत्येक वर्ष एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत आने वाले लगभग 30-40 लाख परिवारों को शामिल किया जाएगा। बीमे की राशि 3,000 रुपए होगी और दुर्घटनाग्रस्त मृत्यु होने पर दुगुना लाभ मिलेगा।

39. अब मैं विशिष्ट रूप से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लाभ के लिए कुछ उपाय करने के प्रस्ताव करना चाहता हूँ। राज्य स्तर के कई अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वित्त/विकास निगम, अनुसूचित

जातियों/अनुसूचित जनजातियों की विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने में अच्छा काम कर रहे हैं। मैं अब एक राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम की स्थापना करने का प्रस्ताव करता हूँ। यह निगम रोजगार का सृजन करने की ऐसी स्कीमों को तैयार करने और ऐसे प्रायोगिक कार्यक्रमों की वित्त-व्यवस्था करने में उत्प्रेरक की भूमिका निभाएगा, जिन्हें राज्य स्तर के निगमों और इस क्षेत्र में कार्यरत अन्य अभिकरणों द्वारा हाथ में लिया जा सकता है। यह निगम अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों को वित्तीय सहायता की उपलब्धता में वृद्धि करने के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के साथ मिलकर काम करेगा। इसका उद्देश्य मौजूदा संस्थानों जैसा ही काम करने के स्थान पर नए विचार कार्यान्वित, प्रयोग करना और कार्य संवर्धन करना होगा। मैं अगले वर्ष के बजट में इस निगम के लिए 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था कर रहा हूँ।

40. माननीय सदस्यों को यह जानकर खुशी होगी कि हमारा प्रस्ताव है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अनन्य लाभ के लिए धनराशियों के आवंटन की प्रतिशतता को 10 से बढ़ाकर 20 करके राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अन्तर्गत 10 लाख कुंओं की एक परियोजना शुरू की जाए। यह उचित ही है कि स्वतन्त्रता-प्राप्ति की चाली-सवीं वर्षगांठ के वर्ष में हम कुंओं के निर्माण का एक ऐसा व्यापक कार्यक्रम शुरू करें, जिनसे अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लाखों छोटे और सीमान्तिक किसानों को लाभ पहुंचेगा।

41. अब मैं विकेंद्रीकृत क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए कुछ उपायों की घोषणा करना चाहूंगा। हथकरघा उद्योग लगभग 100 लाख बुनकरों व अन्य व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करता है। कपास तथा अन्य सूतों/धागों की उंची कीमतों के कारण यह महत्वपूर्ण क्षेत्र प्रभावित हुआ है। मेरा प्रस्ताव जनता कपड़े पर सब्सिडी को 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर से बढ़ाकर 2.75 रुपये प्रति वर्ग मीटर करने का है। ऐसा करने से 40 करोड़ रुपये की राहत मिलेगी। मैं बाद में अपने भाषण में कुछ उपायों की घोषणा करूंगा जिनके फलस्वरूप सूत की कुछ किस्मों की लागत कम होने से हथकरघा क्षेत्र को लाभ होगा। सरकार का यह भी प्रस्ताव है कि हथकरघा क्षेत्र के लिए जनता कपड़े के मौजूदा 5000 लाख मीटर प्रतिवर्ष के लक्ष्य को बढ़ाकर आगामी वर्ष के लिए 6000 लाख मीटर कर दिया जाए। आजकल खादी के लिए 10 प्रतिशत की मानक छूट दी जा रही है। मेरा प्रस्ताव है कि कम्बलियों और कम्बलियों पर भी यह छूट दी जाए।

42. अति-लघु क्षेत्र सहित लघु क्षेत्र के उद्योगों की लम्बे समय से यह मांग रही है कि उनके वास्ते एक अलग शीर्ष बैंक होना चाहिए। माननीय सदस्यों को यह जानकर

खुशी होगी कि अब एक "भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक" की स्थापना करने का निर्णय लिया गया है। यह नया बैंक भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का एक 'सबसिडियरी' बैंक होगा। इस नए बैंक की इक्विटी पूंजी 250 करोड़ रुपये की होगी और इसका अपना अलग निदेशक मंडल होगा, जिसमें लघु उद्योग क्षेत्र के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। यह नया बैंक मई, 1986 में स्थापित लघु उद्योग विकास निधि और अति लघु और लघु क्षेत्र की परियोजनाओं को इक्विटी सहर्षन प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय इक्विटी निधि का भी प्रशासन करेगा।

43. नई लघु इकाइयों को कार्यचालन पूंजी (बैंकिंग कैपिटल) प्राप्त करने में प्रायः अनेक समस्याओं और विलम्ब का सामना करना पड़ता है। इस कठिनाई को दूर करने के उद्देश्य से यह निर्णय किया गया है कि ऐसी नई अति लघु तथा लघु इकाइयों को, जिनकी परियोजना लागत 5 लाख रुपये से अधिक न हो, 2.5 लाख रुपये तक की कार्यचालन पूंजी सम्बन्धी आवश्यकताओं की व्यवस्था एक ही बैंक अथवा संस्थान द्वारा की जाएगी। इस योजना के व्यौरों की घोषणा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा शीघ्र ही की जाएगी।

44. आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए स्वस्थ पूंजीगत (कैपिटल गुड्स) मशीन निर्माण क्षेत्र एक पूर्वावश्यकता है। पिछले वर्ष, बजट प्रस्तुत करते समय प्रधान मंत्री ने मशीन निर्माण उद्योगों को फिर से सक्रिय बनाने के लिए कुछ उपायों की घोषणा की थी। बाद में अपने भाषण में, मैं कुछ उपायों की घोषणा करूंगा जिनसे कागज, मीमेंट और वस्त्र जैसे उद्योगों को अधिक सक्रिय बनाने की प्रक्रिया और आगे बढ़ेगी। इन उपायों से मांग में वृद्धि होगी और लागतों में कमी आएगी तथा कार्यकुशलता बढ़ेगी।

45. पूंजी बाजार, उद्योगों के लिए बचत जुटाने का एक महत्वपूर्ण साधन है और सरकार ने इसे मजबूत बनाने के लिए कई उपाय किए हैं। पिछले वर्ष प्रधान मंत्री ने स्टॉक एक्सचेंजों के नियमन और विकास के लिए एक पृथक बोर्ड स्थापित करने के निर्णय की घोषणा की थी। इस सम्बन्ध में आवश्यक विधान तैयार किया जा रहा है और आशा है कि बोर्ड शीघ्र ही कार्य आरम्भ कर देगा। सांख्यिकी निधियां स्थापित करने, स्टॉक एक्सचेंजों के व्यवस्थित कार्य-संचालन के लिए आधारभूत नियम निर्धारित करने, उनके बुनियादी ढांचे को सुधारने, शेयरों के ट्रांसफर को सुविधाजनक बनाने और बाजार में प्रवेश करने वाली कंपनियों पर बेहतर अनुशासन लागू करने के लिए भी कदम उठाए गए हैं। मैं बाद में अपने भाषण में कुछ और उपायों की घोषणा करूंगा, जिनसे नए उद्योगों में निवेश को बढ़ाया मिलेगा तथा और अधिक रोजगार का सृजन होगा और आर्थिक कार्य-कलापों का विस्तार होगा।

46. हमारे यहां वैज्ञानिकों और तकनीकी ज्ञान रखने वालों की बहुत बड़ी संख्या है। फिर भी पन्निहित जोखिम के कारण युवा और नए उद्यमियों को इक्विटी (शेयर) पूंजी

जुटाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस समस्या की भावी पूंजीगत लाभ की प्रत्याशा से, उद्यम-पूँजी (वेंचर-केपिटल) कम्पनियों अथवा निधियों को नई कम्पनियों में पूँजी-निवेश करने की अनुमति देकर हल किया जा सकता है। किन्तु इस समय, ऐसी कम्पनियाँ, पूंजीगत लाभ पर गैर-निगमित इकाइयों को उपलब्ध रियायतें प्राप्त करने की हकदार नहीं हैं। इस समस्या को दूर करने के लिए एक योजना बनाने का निर्णय किया गया है, जिसके अन्तर्गत स्वीकृत उद्यम पूँजी कम्पनियों/निधियों को नई कम्पनियों में निवेश करने के योग्य बनाया जाएगा और उन्हें पूंजीगत लाभ पर वही रियायत दी जाएगी जो कि गैर-निगमित इकाइयों को उपलब्ध है। इस अमल में लाने के लिए आवश्यक वैधानिक उपाय किए जाएंगे।

47. इस समय नए औद्योगिक उपक्रमों के इक्विटी शेयरों में किए जाने वाले निवेश के बारे में कर सम्बन्धी रियायतें उपलब्ध होती हैं। नई कम्पनियों की संभावनाओं के बारे में पर्याप्त जानकारी न होने के कारण छोटे निवेश-कर्ताओं का इन रियायतों का लाभ उठाने में सामान्यतः कठिनाई अनुभव होती है। यह फैसला किया गया है कि नए औद्योगिक उपक्रमों के इक्विटी शेयरों में प्रत्यक्ष निवेश पर अब जो रियायतें उपलब्ध हैं, वे सांझी (म्यूचुअल) निधियों के विशेष यूनितों में निवेश पर भी उपलब्ध होंगी, जहाँ निवेशकों को नई परियोजनाओं में निवेश करने के लिए अलग रखा जाता है। इससे नई कम्पनियों का अधिक आसानी से पूँजी जुटाने में सहायता मिलेगी।

48. लाभान्तरों से होने वाली आय के बारे में आयकर अधिनियम की धारा 80D के अन्तर्गत 3,000 रुपये तक की विशेष छूट देने का भी मेरा प्रस्ताव है। यह छूट कुछ प्रकार की आयनियों के बारे में, जिनमें 7,000 रुपये तक के लाभान्तर और भारतीय यूनित ट्रस्ट में किए गए निवेश तथा कुछ अन्य विनिर्दिष्ट निवेशों, जिनको मैं बित्त विधायक में समाविष्ट कर रहा हूँ, से होने वाली 3,000 रुपये की अतिरिक्त आय भी शामिल है, उपलब्ध मौजूदा रियायतों के अलावा होगी।

49. अन्तर्राष्ट्रीय विनिमय दरों में तेजी से उतार-वढ़ाव से निर्यातकर्ताओं और साथ ही भारतीय उद्योग के लिए समस्याएँ उत्पन्न हो रही हैं। अलग-अलग परियोजनाओं को विनिमय दर में उतार-चढ़ाव से कुछ संरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से विनीय संस्थाएँ एक नई योजना शुरू करेंगी जिसके अनुसार ऐसी परियोजनाओं के प्रवर्तक अपने विदेशी मुद्रा के ऋणों को रुपयों में विनिर्दिष्ट कर सकते हैं। ऐसे ऋणों पर व्याज की दर परिवर्तनीय होगी और उसमें विनिमय प्रीमियम भी सम्मिलित होगा। इस स्कीम का ब्याँरा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा अलग से घोषित किया जाएगा।

50. हमारी सरकार की यह नीति रही है कि उद्योग-प्रबंध में श्रमिकों की सहभागिता को बढ़ावा दिया जाए। श्रमिकों के साथ विचारविमर्श करके और प्रबंध में उनका सहयोग प्राप्त करके ही हम अपने समग्र कार्य-निष्पादन में सुधार ला सकते हैं, उत्पादकता बढ़ा सकते हैं और औद्योगिक रुग्णता को रोक सकते हैं। सरकार ऐसी सहभागिता को सुविधाजनक बनाने के लिए पहले ही एक स्कीम की घोषणा कर चुकी है। मुझे सदन को यह सूचित करते हुए खशी हो रहा है कि श्रमिकों की सहभागिता के लिए स्कीम लागू करने के लिए कम्पनियों द्वारा किए जाने वाले सारे खर्च के सम्बन्ध में आयकर से पूरी छूट दी जाएगी। सरकार ने एक और स्कीम भी लागू की है, जिसके अनुसार पूँजी निर्माणों का 5 प्रतिशत भाग कर्मचारियों के लिए आरक्षित होगा। श्रमिकों द्वारा अपनी कम्पनियों में शेयर खरीदने को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से बैंकों को इस प्रयोजन के लिए उदारतापूर्वक ऋण देने के लिए कहा जा रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक शीघ्र ही इस सम्बन्ध में आवश्यक अनुदेश जारी करेगा।

51. श्रमजीवी पत्रकारों ने अपने बौद्धिक परिश्रम से देश की सेवा में भारी योगदान किया है और ऐसे सुझाव प्राप्त हुए हैं कि इन पत्रकारों के लिए पेंशन की एक उपयुक्त योजना की व्यवस्था करने के लिए संसद के विचारार्थ एक विशेषक पुरस्थापित किया जाए। सरकार इस दिशा में सभी-संविधियों से परामर्श करके मुनासिब कदम उठाएगी।

52. सरकार विदेशों में बसे भारतीय राष्ट्रियों के साथ आर्थिक और सांस्कृतिक सम्बन्धों को मजबूत बनाने को बहुत महत्व देती है। अनिवासी भारतीयों को राजकोपीय रियायतों सहित बहुत सी सुविधाएँ दी गई हैं, ताकि उन्हें निवेश करने में सुविधा हो। प्राप्त अभ्यावेदनों को देखते हुए, सरकार ने अब प्रतिवासी भारतीयों के लिए गैर-प्रत्यावर्तनीय आधार पर विदेशी मुद्राओं के बांडों/जमा पत्रों की एक नई स्कीम शुरू करने का निर्णय किया है। इन बांडों/जमा पत्रों की परिपक्वता अवधि 7 वर्षों की होगी और इनके व्याज की दर अन्य प्रत्यावर्तनीय विदेशी मुद्रा अनिवासी जमाओं पर मिलने वाले व्याज की दर से अधिक होगी। ये बांड/जमा पत्र आय कर, धन कर और दान कर से मुक्त होंगे।

53. हमारे देश में अनिवासी भारतीयों द्वारा किए जाने वाले निवेश और जमाओं के बारे में राजकोपीय व्यवस्था बड़ी उदार बना दी गई है। सरकार का इरादा राजकोपीय स्थिरता बनाए रखने का है। कर प्रणाली में ऐसे कोई परिवर्तन नहीं किए जाएंगे, जिनसे अनिवासी भारतीयों द्वारा पहले से किए गए निवेश पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़े।

54. अनिवासी भारतीयों ने बहुत से वैज्ञानिक, आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में जो सफलता प्राप्त की है, वह हमारे लिए अत्यन्त सन्तोष का विषय है। हम उनके साथ निरन्तर अपने सम्बन्ध बनाए रखना चाहते हैं।

55. अल्प वचत संग्रह को बढ़ावा देने के लिए, मेरा कुछ उदाय शुरू करने का प्रस्ताव है। मैं विशेष रूप से उन ग्रामीण वचनों को जुटाने के लिए उत्प्रेक हूँ जिनको अभी उपयोग में नहीं लाया गया है। बिना कर रियायत वाली, लेकिन जमा के 2-1/2 वर्ष बाद भुनाने की सुविधा वाली एक नई स्कीम शुरू की जा रही है। अपेक्षाकृत अधिक लम्बी अवधियों के लिए व्याज की दर में उत्तरोत्तर वृद्धि होनी जाएगी। इसमें जमा की गई राशि साढ़े चार वर्ष पश्चात् दुगुनी हो जाएगी। इस जमा-पत्र से नए निवेश आकर्षित होंगे, क्योंकि इसे जब भी धन की जरूरत होगी तभी भुनाया जा सकता है। इस जमा पत्र को 'किमान विकास पत्र' कहा जाएगा।

56. पिछले वर्ष प्रधान मंत्री द्वारा निवल वचत (नेट सेविंग्स) मिष्ठान्त पर आधारित एक नई वचत योजना की घोषणा की गई थी। इस योजना के अन्तर्गत, जमा की जाने वाली 20,000 रुपये तक की अधिकतम राशि के 50 प्रतिशत भाग तक की रकम आकर अधिनियम की धारा 80 गगक के अन्तर्गत कटौती योग्य मानी जाती है। तथापि उस वर्ष में जिसमें निरासी की जाए, आहरित राशि का 50 प्रतिशत भाग कराधान योग्य आय में जोड़ा जाता है। इसमें जमा की गई राशि पर 9 प्रतिशत व्याज दिया जाता था। व्याज की इस दर को बढ़ाकर 11 प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया है। व्याज की यह नई दर वर्तमान जमा राशियों पर भी पिछले वर्ष 1 अप्रैल से ही लागू मानी जाएगी। इसके अलावा जमा करते समय कटौती की दर 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 100 प्रतिशत कर दी जाएगी और आहरण करते समय कर के अध्वधीन राशि में भी तदनु रूप वृद्धि कर दी जाएगी। अगले वित्तीय वर्ष से जमा करने योग्य राशि को भी बढ़ाकर 30,000 रुपये प्रतिवर्ष किया जा रहा है।

57. पहली मार्च, 1988 से बेचे जाने वाले इंदिरा विकास पत्रों के अन्तर्गत राशि को दुगुना करने की अवधि भी घटाकर पांच वर्ष कर दी जाएगी।

58. राहत पत्रों की बिक्री को 29 फरवरी, 1988 के बाद भी जारी रखने का प्रस्ताव है। राहत पत्रों को जारी रखने के कारण, पूंजी निवेश बांडों की बिक्री 1 अप्रैल, 1988 से बन्द करने का प्रस्ताव है।

59. महोदय, मैं इस अवसर का लाभ हमारे समाज के कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए और विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अधिक अवसरों का निर्माण करने और हमारी अर्थ-व्यवस्था के उत्पादक आधार को सुदृढ़ बनाने के लिए कुछ उपायों की घोषणा करने के लिए उठाया है। मुझे आशा है कि इन उपायों से हमारी जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने में योगदान मिलेगा।

60. अब मैं 1987-88 के संशोधित अनुमानों और 1988-89 के बजट अनुमानों की ओर आता हूँ।

संशोधित अनुमान 1987-88

61. वर्ष 1987-88 के बजट में कुल व्यय के संशोधित अनुमान 66161 करोड़ रुपये के हैं, जबकि मूल बजट अनुमान 62942 करोड़ रुपये के थे। जैसे ही सूखे की स्थिति की गम्भीरता स्पष्ट हुई, सरकार का सबसे पहला कार्य यह सुनिश्चित करना था, कि राज्य सरकारों को पर्याप्त साधन उपलब्ध हों ताकि वे राहत कार्य शुरू कर सकें और सूखे से उत्पन्न कठिनाइयों को दूर करने के उपाय कर सकें। राज्यों में केन्द्रीय दल भेजे गए और सूखे तथा बाढ़ों से प्रभावित राज्यों के लिए व्यय की उच्चतम सीमाओं के बारे में रिकार्ड समय में घोषणाएं की गईं। सूखे, बाढ़, और अन्य दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में केन्द्रीय बजट से लगभग 2,000 करोड़ रुपये का व्यय होने का अनुमान है। इसमें माजिन राशि में केन्द्र का हिस्सा, सूखे के लिए अग्रिम आयोजना सहायता, बाढ़ों और ओलावृष्टि के लिए आयोजना-भिन्न सहायता, सूखा-प्रभावित क्षेत्रों में कम दरों पर खाद्यान्नों की आपूर्ति, कम मूल्यों पर बीजों की आपूर्ति, पेयजल के लिए रिगों की व्यवस्था और 'त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति' के लिए सहायता शामिल है।

62. व्यय में कुछ अन्य अनिवार्य वृद्धियां हुई हैं। स्वदेशी उर्वरकों पर दी जाने वाली सब्सिडी की राशि 300 करोड़ रुपये अधिक होगी। खाद्यान्नों संबंधी सब्सिडी की राशि भी 200 करोड़ रुपये अधिक होगी। मुझे यकीन है कि माननीय सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि चालू वर्ष में विद्यमान परिस्थितियों में ये वृद्धियां पूरी तरह से औचित्यपूर्ण हैं। सरकारी कर्मचारियों, विशेषतः रक्षा सेवा कर्मिकों के पेंशन सम्बन्धी लाभों को उदार बनाए जाने के कारण चालू वर्ष में पेंशन बिल में 374 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी होने की संभावना है। सरकारी क्षेत्र के कुछ उपक्रमों को सब्सिडी, ऋणों को बट्टे खाते डालने, आदि के रूप में जो वित्तीय राहतें प्रदान की गई हैं, उनसे 417 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय होने की संभावना है। व्याज प्रभारों के भी मूल बजट व्यवस्था की तुलना में 800 करोड़ रुपये अधिक होने का अनुमान है। अन्य घट-बढ़ को हिसाब में लेने पर चालू वर्ष में कुल आयोजना-भिन्न व्यय 39,265 करोड़ रुपये की मूल बजट व्यवस्था से 1,971 करोड़ रुपये अधिक होने का अनुमान है।

63. राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता की राशि 1,127 करोड़ रुपये अधिक होने की संभावना है, जिसका मुख्य कारण सूखे से प्रभावित राज्यों को अपेक्षाकृत अधिक अग्रिम योजना सहायता दिया जाना है। अनुमान है कि केन्द्रीय आयोजना के लिए बजटीय सहायता की राशि 121 करोड़ रुपये अधिक होगी। यह कृषि, ग्रामीण विकास, उर्वरक, कृषि वित्तीय संस्थाओं, पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना के लिए सब्सिडी, आदि जैसे क्षेत्रों में हुई वृद्धि का, जो कतिपय अन्य क्षेत्रों में हुई वचत से प्रतिसन्तुलित हो गई है, निवल परिणाम है।

64. आयोजना और आयोजना-भिन्न दोनों को इकट्ठा लेने पर, व्यय में 3,219 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है। सरकार द्वारा वर्ष के दौरान किए गए कई उपायों के परिणाम-स्वरूप मितव्ययिता की भावना पैदा हुई है और व्यय को, विशेषकर निम्न प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में, काबू में रखा गया है।

65. सकल कर राजस्व में, मुख्यतः आय और निगम करो तथा सीमा शुल्कों के अन्तर्गत 1,028 करोड़ रुपए की अधिक प्राप्तियां होने का अनुमान है। करों में राज्यों के हिस्से में 392 करोड़ रुपए की वृद्धि होगी। कर-भिन्न प्राप्तियां 2,201 करोड़ रुपए अधिक होगी। इनमें से कर-भिन्न राजस्व प्राप्तियों के अन्तर्गत 765 करोड़ रुपए और पूंजी प्राप्तियों में 1,436 करोड़ रुपए की वृद्धि होने की संभावना है। पूंजी प्राप्तियों में होने वाली वृद्धि में 700 करोड़ रुपए बाजार ऋणों के रूप में होंगे।

66. व्यय और प्राप्तियों में होने वाली घट-बढ़ को हिसाब में लेने पर, चालू वर्ष की समाप्ति पर कुल मिलाकर 6080 करोड़ रुपए का घाटा होने की संभावना है। इस वर्ष बजट पर जो बहुत अधिक दबाव पड़े हैं उनके बावजूद, बजट का यह घाटा, 5,688 करोड़ रुपए के मूल अनुमान के बिल्कुल करीब है।

बजट अनुमान 1988-89

67. माननीय सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि वर्ष 1988-89 के बजट अनुमान बड़ी कठिन परिस्थिति में प्रस्तुत किए जा रहे हैं। हमें यह सुनिश्चित करना है कि बजट पर दबावों के बावजूद सरकारी निवेशों में कोई कमी नहीं होनी चाहिए क्योंकि इसका आर्थिक गतिविधियों और रोजगार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। तदनुसार, अगले वर्ष का बजट तैयार करने में इस बात को सर्वाधिक प्राथमिकता दी गई है कि आयोजना निवेश की गति धनी रहे।

68. वर्ष 1988-89 की केन्द्रीय आयोजना के लिए 28,715 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित की गई है जबकि चालू वर्ष के लिए अनुमानित परिव्यय 24,622 करोड़ रुपए का है, जिसका अर्थ है 16.6 प्रतिशत की वृद्धि। 25,701 करोड़ रुपए के संशोधित केन्द्रीय आयोजना परिव्यय की तुलना में भी अगले वर्ष का परिव्यय 11.7 प्रतिशत वृद्धि का द्योतक है। अगले वर्ष की केन्द्रीय आयोजना का वित्तपोषण इस प्रकार होगा 16,000 करोड़ रुपए बजटीय संसाधनों में और 12,715 करोड़ रुपए सरकारी उपक्रमों के आन्तरिक तथा बजट-बाह्य संसाधनों से। 1988-89 के लिए प्रस्तावित परिव्यय से हम वास्तविक दृष्टि से चार वर्षों में सातवीं आयोजना परिव्यय के 86 प्रतिशत से अधिक भाग का उपयोग कर लेंगे।

69. इसके अलावा, अगले वर्ष के केन्द्रीय बजट में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की आयोजनाओं की महायता हेतु 9,714 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। इस प्रकार अगले वर्ष के बजट में कुल आयोजना व्यय 25,714 करोड़ रुपए का है, जबकि चालू वर्ष के संशोधित अनुमानों में यह राशि 24,925 करोड़ रुपए की है।

70. मुझे सदन को यह जानकारी देने हुए खुशी हो रही है कि 1987-88 में केन्द्र से राज्यों को कुल 24,870 करोड़ रुपए के अन्तरण हुए, जिनमें करों में उनका हिस्सा भी शामिल है। वर्ष 1988-89 में 26,348 करोड़ रुपए का अन्तरण होने का अनुमान है, अर्थात् 1,478 करोड़ रुपए का अधिक अन्तरण होगा।

71. कई राज्यों ने लिखा है कि सूखे से उनकी नकदी सम्बन्धी स्थिति पर प्रभाव पड़ा है और उन्होंने अर्थोपाय सीमाओं में कुछ ढील दिए जाने का अनुरोध किया है। माननीय सदस्यों को यह जानकर हर्ष होगा कि भारतीय रिजर्व बैंक कल से अक्टूबर, 1986 के पहले विद्यमान अर्थोपाय सीमा की तुलना में 40 प्रतिशत की वृद्धि कर रहा है। इसमें वर्ष की विभिन्न अवधियों के लिए अक्टूबर, 1986 में 30 प्रतिशत और 20 प्रतिशत की वृद्धि की गई थी।

72. जैसा कि पहले बताया गया है कृषि और सहकारिता तथा जल संसाधन विभागों के परिव्यय में चालू वर्ष के परिव्यय की तुलना में 40 प्रतिशत की वृद्धि करने का निर्णय किया गया है। मैं, 1988-89 में उर्वरक परियोजनाओं के लिए 671 करोड़ रुपए की व्यवस्था करने का भी प्रस्ताव करता हूं। आशा है कि चालू वर्ष के दौरान चार नए उर्वरक संयंत्रों में दो सरकारी क्षेत्र में और दो गैर-सरकारी क्षेत्र में उत्पादन शुरू हो जाएगा। इस वर्ष उर्वरक उत्पादन के 71 लाख मीट्रिक टन के स्तर तक पहुंच जाने का अनुमान है, जिसका अर्थ है सातवीं आयोजना के प्रारम्भ में हो रहे उत्पादन की तुलना में लगभग 40 प्रतिशत की वृद्धि।

73. प्रमुख गरीबी-विरोधी कार्यक्रम, यथा एकीकृत ग्राम विकास कार्यक्रम (आई० आर० डी० पी०), राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (एन० आर० ई० पी०) तथा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम (आर० एल० ई० जी० पी०) रोजगार के अवसर बढ़ाने तथा गरीबी की रेखा से नीचे रहने वालों के लिए आमदनी के अवसर बढ़ाने के प्रमुख साधनों के रूप में जारी रहेंगे। अब तक एकीकृत ग्राम विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत कुल 8,413 करोड़ रुपए के निवेश के साथ लगभग 254 लाख परिवारों की मदद की गई है। इनमें से 40 प्रतिशत लाभप्राप्तकर्ता अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों से सम्बन्धित हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अन्तर्गत 1986-87 में कुल 7,006 लाख कार्य-दिवसों का सृजन हुआ, जो 5,115 लाख कार्य-दिवसों के लक्ष्य की तुलना में काफी अधिक था। आशा है कि इस वर्ष भी लक्ष्य पार हो जाएगा।

74. ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का सृजन करने में ये कार्यक्रम अत्यन्त सफल रहे हैं। इन कार्यक्रमों का विस्तार करने और इनका पुनर्गठन करने के सम्बन्ध में सुझाव प्राप्त हुए हैं। कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रमों, यथा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम और मरुस्थल विकास कार्यक्रम तथा अन्य विभिन्न गरीबी-विरोधी कार्यक्रमों को मिला देने का भी सुझाव दिया गया है ताकि उपलब्ध संसाधनों का और अधिक प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सके, जिससे गांवों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए रोजगार और परिसम्पत्तियों के निर्माण के दोनों उद्देश्य की पूर्ति हो सके। कार्यचालन स्तर पर इनमें लचीलापन लाने की भी जरूरत है। इन सुझावों के प्रकाश में आगामी वर्ष में इन रोजगार कार्यक्रमों की बारीकी से समीक्षा करने का प्रस्ताव है, ताकि एक व्यापक कार्यक्रम शुरू करने की संभावना की जांच की जा सके।

75. ग्रामीण जल पूर्ति को उच्च प्राथमिकता बराबर दी जा रही है। गांवों में पेय जल तथा सम्बद्ध जल प्रबन्ध के लिए प्रौद्योगिकी मिशन के काम को जोरदार ढंग से आगे बढ़ाया जा रहा है। वर्ष 1988-89 में मेरा प्रस्ताव ग्रामीण विकास विभाग के लिए 2,200 करोड़ रुपये की व्यवस्था करने का है, जिसमें ग्रामीण जल पूर्ति और स्वच्छता के लिए 430 करोड़ रुपये की राशि शामिल है। जैसा कि माननीय सदस्यों को जानकारी है, जल पूर्ति पर परिरक्ष्य, राज्य क्षेत्र में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के परिरक्ष्य के अलावा है।

76. जनजातीय लोगों के लिए कल्याण कार्यक्रम उनकी संस्कृति और परम्परा के सम्मान व सद्भावना और उनकी सामाजिक, मनोवैज्ञानिक तथा आर्थिक समस्याओं की जानकारी पर आधारित होने चाहिए। जनजातीय लोगों तथा जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए जनजातीय उप-आयोजना एक प्रमुख साधन है। जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं, जनजातीय उप-आयोजनाओं की वित्त-व्यवस्था राज्य सरकारों, विशेष केन्द्रीय सहायता, केन्द्र-प्रायोजित कार्यक्रमों तथा वित्तीय संस्थाओं द्वारा की जाती है। वर्ष 1988-89 के लिए जनजातीय उप-आयोजना के वास्ते विशेष केन्द्रीय सहायता की राशि 185 करोड़ रुपये है। अनुसूचित जातियों के लिए, व्यावसायिक गतिशीलता और आर्थिक मजबूती प्रदान करने के प्रमुख उद्देश्य से विशेष संघटक आयोजनाएं तैयार की जा रही हैं। चालू वर्ष में इन कार्यक्रमों से अनुसूचित जातियों के 20 लाख परिवारों के लाभान्वित होने की आशा है। 1988-89 के लिए विशेष संघटक आयोजनाओं के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता के रूप में 180 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

77. हमारे मानव संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण संसाधन है। इस समय विकसित की जाने वाली मानवशक्ति की गुणवत्ता भविष्य में आर्थिक और सामाजिक प्रगति की गति और दिशा निर्धारित करने में निर्णायक होगी। संसद

में और संसद से बाहर व्यापक रूप से विचार-विमर्श के बाद 1986 में नई शिक्षा नीति लागू की गई थी। इस उद्देश्य से कि नई नीति की शुरुआत अच्छे ढंग से हो, पिछले वर्ष बजट प्रस्तुत करते समय प्रधान मन्त्री ने शिक्षा के लिए आवंटन को 1986-87 के 352 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 800 करोड़ रुपये कर दिया था। अनुमान है कि वास्तविक व्यय 700 करोड़ रुपये होगा। अगले वर्ष की आयोजना में 800 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। आयोजना-भिन्न व्यवस्था को मिलाकर, शिक्षा विभाग के लिए वर्ष 1988-89 में कुल आवंटन 1,550 करोड़ रुपये का होगा, जबकि इसकी तुलना में 1987-88 के संशोधित अनुमानों में 1,185 करोड़ रुपये की व्यवस्था है।

78. जनता के स्वास्थ्य के स्तर में सुधार करना मानव संसाधनों के विकास का एक अत्यावश्यक अंग है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थापना करने, प्रमुख संचारी और गैर-संचारी रोगों के नियंत्रण के कार्यक्रम शुरू करने, चिकित्सा और परा-चिकित्सा शिक्षा और प्रशिक्षण की सुविधाओं में वृद्धि करने तथा परिवार कल्याण, माताओं और बाल स्वास्थ्य, प्रतिरक्षण, और संबंधित सेवाओं की व्यवस्था करने पर बल दिया जा रहा है। राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुमानतः 40 लाख कुष्ठ रोगियों में से 22 लाख रोगियों को बहुऔषध उपचार प्रदान किया गया। व्यापक प्रतिरक्षण कार्यक्रम को 120 और जिलों में लागू किया जा रहा है जबकि 182 जिलों में यह पहले से लागू है। सूखाग्रस्त राज्यों के लिए आपात-कालीन स्वास्थ्य योजनाएं तैयार की गई हैं। मेरा वर्ष 1988-89 के लिए चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों के लिए 228 करोड़ रुपये का और परिवार कल्याण कार्यक्रमों के लिए 600 करोड़ रुपये का परिरक्ष्य रखने का प्रस्ताव है।

79. सरकार ने कामकाजी महिलाओं की स्थिति में सुधार करने के अनेक उपाय शुरू किए हैं। इनमें कौशल के स्तर को उन्नत उठाने और आर्थिक विकास, कामकाजी महिलाओं के लिए, समर्थनकारी सेवाओं और कठिन परिस्थितियों में ग्रस्त महिलाओं के लिए आश्रय-स्थलों और उनके पुनर्वास के कार्यक्रम शामिल हैं। बच्चों के लिए एकीकृत बाल विकास सेवा का राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम चल रहा है। इन एकीकृत बाल विकास सेवा कार्यक्रमों का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य शेषकालीन मृत्यु की दर, रोग और कुपोषण को कम करना है। मुझे माननीय सदस्यों को यह जानकारी देते हुए खुशी हो रही है कि देश के सबसे अधिक पिछड़े ग्रामीण क्षेत्रों, जनजातीय क्षेत्रों और शहरी गन्दी बस्तियों के लिए 1,738 एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजनाओं की मंजूरी दी गई है। हम सातवीं पंचवर्षीय

योजना की शेष अवधि में ऐसे अधिकांश जनजातीय खंडों जहाँ अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों की संख्या 30 प्रतिशत से अधिक हो, और बड़े शहरों की गन्दी बस्तियों में यह कार्यक्रम शुरू कर देंगे। मैं अगले वर्ष महिला और बाल विकास विभाग के लिए 235 करोड़ रुपए का परिव्यय रखने का प्रस्ताव करता हूँ। हमें अपने युवाओं पर गर्व है। हमें विश्वास है कि उनके मजबूत हाथों में हमारी परम्परा और देश का भविष्य सुरक्षित है। युवा और खेलकूद क्रियकलापों के लिए, चालू वर्ष के मुकाबले आगामी वर्ष में 13 प्रतिशत की वृद्धि करके, पर्याप्त व्यवस्था की गई है।

80. ऊर्जा, परिवहन और संचार, अर्थ-व्यवस्था का आधारभूत ढांचा है। इन क्षेत्रों के लिए कुल 16,588 करोड़ रुपए का आवंटन किया जा रहा है। यह परिव्यय चालू वर्ष के स्तर से लगभग 25 प्रतिशत अधिक है और 1988-89 के कुल आयोजना परिव्यय के लगभग 58 प्रतिशत के बराबर है।

81. सातवीं आयोजना की अवधि में बिजली के उत्पादन में 9 से 10 प्रतिशत तक की वार्षिक दर से वृद्धि हो रही है। यद्यपि इस वर्ष सूखे के कारण जल-विद्युत् उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था, लेकिन चालू वर्ष के पहले 9 महीनों में पिछले वर्ष की तदनु रूप अवधि की तुलना में ताप विद्युत् के उत्पादन में 16 प्रतिशत की वृद्धि हुई। ताप विद्युत् संयंत्रों के संयंत्र भार अनुपात में और सुधार हुआ है और उसके 55 प्रतिशत तक पहुंचने की संभावना है जो कि पिछले 10 वर्षों का उच्चतम स्तर है। मैं विद्युत् क्षेत्र के लिए 3,963 करोड़ रुपए के परिव्यय की व्यवस्था कर रहा हूँ जो चालू वर्ष के परिव्यय से 32 प्रतिशत से भी अधिक है।

82. कोयला हमारे देश में पारम्परिक ऊर्जा का प्राथमिक और सबसे बड़ा स्रोत है। मैं वर्ष 1988-89 में इस क्षेत्र के लिए 30 प्रतिशत वृद्धि करके 1,733 करोड़ रुपए की व्यवस्था कर रहा हूँ। अनुमान है कि चालू वर्ष में कोयले का उत्पादन 1,820 लाख मी. टन का होगा, जबकि पिछले वर्ष 1,660 लाख मी. टन उत्पादन हुआ था।

83. जैसा कि माननीय सदस्यों को मालूम है, इस दशक में हमारे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस क्षेत्र ने असाधारण प्रगति की है। तेल की अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों ने जो पल्टा खाया है, उससे इस बात को बल मिलता है कि हाइड्रो-कार्बन स्रोतों को ढूँढ़ने और उनका इस्तेमाल करने की तत्काल आवश्यकता है। कृष्णा-गोदावरी के अपतटीय क्षेत्र और कावेरी बेसिन के भुवनगिरि क्षेत्र में इस वर्ष जो महत्वपूर्ण भंडार खोजे गए हैं, वे तेल-अन्वेषण के क्षेत्र में हमारे द्वारा किए गए भारी निवेश के सुपरिणाम हैं। इस वर्ष एच. बी. जे. पाइपलाइन के हजीरा से बिजयपुर

तक के 642 किलोमीटर लम्बे पहले भाग का काम भी पूरा हुआ। कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन की गति को बनाए रखने के लिए, मेरा 3,395 करोड़ रुपए के परिव्यय की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है।

84. संचार के क्षेत्र में टेलीमेटिक्स विकास केन्द्र ने जो काम किया है, उसके बारे में अपने गर्व की भावना को मैं सदन के साथ बांटना चाहता हूँ। अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग प्रणाली, सी-डेट का विकास करके, टेलीमेटिक्स विकास केन्द्र ने यह प्रदर्शित कर दिया है कि अपनी वैज्ञानिक प्रतिभा के उपयुक्त संगठन और आयोजन द्वारा हम क्या प्राप्त कर सकते हैं। मैं दूर-संचार विभाग के लिए वर्ष 1988-89 के लिए 1,873 करोड़ रुपए आवंटित कर रहा हूँ, जो चालू वर्ष के परिव्यय से 44 प्रतिशत अधिक है।

85. सरकार इस बात को स्वीकार करती है कि राष्ट्र के आर्थिक विकास के लिए हमारी वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय योग्यताओं का विकास एक पूर्वावश्यकता है। इसे ध्यान में रखते हुए, मेरा वैज्ञानिक विभागों के परिव्यय में चालू वर्ष के स्तर से लगभग 20 प्रतिशत वृद्धि करने का प्रस्ताव है। हम अपने वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकी-विदों की उपलब्धियों पर उचित रूप से गर्व कर सकते हैं। यद्यपि वर्ष के दौरान कई उल्लेखनीय घटनाएँ हुई हैं, तथापि, मैं उनमें से एक का विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूँगा। 26 अगस्त 1987 को प्रधान मंत्री ने माननीय सदस्यों को सूचना दी थी कि भारत वह पहला आवेदनकर्ता है, जिसे अन्तर्राष्ट्रीय समुद्र-तल प्राधिकरण सम्बन्धी तैयारी आयोग द्वारा मध्य हिन्द महासागर में एक खान-स्थल आवंटित किया गया है। यह हमारी वैज्ञानिक क्षमता के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। 1,50,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के इस खान-स्थल में बहुधात्विक नोड्यूलों का विपुल भंडार है।

86. अर्थ व्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में बहुत से अन्य प्रोत्साहन देने की परिकल्पना की गई है। लेकिन मैं आयोजनागत कार्यक्रमों की विस्तृत समीक्षा करके सदन का बहुमूल्य समय नहीं लेना चाहता। पूरा ब्योरा बजट दस्तावेजों में उपलब्ध है।

87. रक्षा के लिए, चालू वर्ष के 12,000 करोड़ रुपए की तुलना में, 13,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। हमारी सशस्त्र सेनाओं ने अनावश्यक उत्तेजनाओं की परिस्थिति में देश की रक्षा करने का काम प्रशंसाजनक रूप से किया है। हमारे जवान राष्ट्र का बल हैं। हम उनके प्रयासों को उपयुक्त समर्थन प्रदान करने के वास्ते अपेक्षित व्यवस्था करते रहेंगे। खाद्यान्नों और उर्वरकों सम्बन्धी आर्थिक सहायता के लिए, चालू वर्ष के 4,410 करोड़ रुपए की तुलना में, 5,300 करोड़ रुपए रखे गए हैं। अनुमान है कि अगले वर्ष व्याज-प्रभारों की राशि 14,100 करोड़ रुपए

को होगा, जबकि चालू वर्ष में यह 11,450 करोड़ रुपए की है। निर्यात संवर्धन और विपणन विकास के लिए 1,991 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। अन्य वृद्धियों का सम्बन्ध विश्वविद्यालयों और कालेजों के अध्यापकों के वेतनमानों में संशोधन के लिए राज्यों को दिए जाने वाले अनुदानों, विदेशी सरकारों को दिए जाने वाले अनुदानों और ऋणों, पुलिस बलों को सुदृढ़ बनाने और तेल उद्योग विकास बोर्ड को 100 करोड़ रुपए की अदायगी करने से है। अगले वर्ष सरकारी कर्मचारियों को देय होने वाली महंगाई भत्ते की अतिरिक्त किस्तों के लिए 800 करोड़ की एकमुश्त व्यवस्था की गई है। मैं माननीय सदस्यों को आश्चर्य करना चाहूंगा कि मैंने आयोजना-भित्त व्यय को न्यूनतम रखा है। इस प्रकार वर्ष 1988-89 में आयोजना-भित्त व्यय 47,896 करोड़ रुपए का होगा, जबकि चालू वर्ष का संशोधित अनुमान 41,236 करोड़ रुपए का है।

88. जहां तक प्राप्तियों का सम्बन्ध है, कराधान की मौजूदा दरों पर 41,985 करोड़ रुपए का मकूल कर राजस्व प्राप्त होने का अनुमान है। राज्यों और स्थानीय निकायों को करों में उनके हिस्से की 10,682 करोड़ रुपए की अदायगी करने के बाद, अगले वर्ष केन्द्रीय सरकार को 31,303 करोड़ रुपए का निवल राजस्व प्राप्त होने का अनुमान है। बाजार ऋणों से 7,000 करोड़ रुपए अर्थात् चालू वर्ष के स्तर के बराबर प्राप्तियां होने का अनुमान लगाया गया है। वापसी-अदायगियों की राशि को घटाकर, 3,734 करोड़ रुपए की विदेशी सहायता प्राप्त होने का अनुमान है, जबकि चालू वर्ष में 3,184 करोड़ रुपए की प्राप्ति का अनुमान है। अन्य प्राप्तियों और खर्चों में होने वाली घट-बढ़ को हिसाब में लेने पर, कराधान की मौजूदा दरों पर अगले वर्ष के बजट में 8,120 करोड़ रुपए के घाटे का अनुमान है।

भाग ख

89. अब मैं अपने राजस्व प्रस्तावों को प्रस्तुत करता हूं। प्रत्येक बजट के जरिए व्यय के वित्तपोषण के लिए कुछ संसाधन जुटाने होते हैं और मैं भी ऐसा करने के अपने कर्तव्य से विमुख नहीं हूंगा। लेकिन मेरा विश्वास है कि यदि अधिक नहीं तो यह भी उतना ही जरूरी है कि राजकोषीय नीति का इस्तेमाल व्यापक आर्थिक और सामाजिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किया जाए और इसके साथ-साथ, जहां उचित हो वहां राहत प्रदान की जाए। मुझे यकीन है कि माननीय सदस्य देखेंगे कि मैं जो प्रस्ताव करने जा रहा हूं और अपने भाषण के भाग "क" में मैंने जिन कुछ जनवादी कदमों का उल्लेख किया है, उनके बीच एक सुदृढ़ परस्पर संबंध है।

90. इस सदन को मालूम ही है कि वर्ष 1987-88 के सूखे के गंभीर प्रभावों में निपटने के लिए, स्थिति की आवश्यकताओं को देखते हुए सरकार ने 50,000 रुपये से ऊपर की कर योग्य आय वाले व्यक्तियों के लिए आयकर

पर 5 प्रतिशत का अधिभार लगाने, वर्ष 1988-89 के कर-निर्धारण वर्ष के लिए धन कर पर 10 प्रतिशत का अधिभार लगाने और उर्वरकों, विद्युत-उपस्कर, जीवन रक्षक औषधियों और चिकित्सा-उपस्कर आदि जैसी आवश्यक वस्तुओं को छोड़कर आयातित वस्तुओं पर सहायक सीमा-शुल्क के रूप में 5 प्रतिशत का अधिभार लगाने का निर्णय किया था। समय पर की गई इस कार्यवाही से देश को यथा केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों को सूखे से उत्पन्न अत्यन्त कठिन स्थिति की आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता मिली। इस अधिभार का आवश्यक वस्तुओं पर कोई असर नहीं हुआ।

91. सूखे और प्राकृतिक विपत्तियों के निरन्तर हानिकार प्रभावों को देखते हुए, मैं इन अधिभारों को एक और वर्ष के लिए जारी रखने का प्रस्ताव करता हूं। इसके अलावा बुनियादी उत्पाद-शुल्कों के 1/20 की दर से विशेष उत्पाद-शुल्क के जरिए अधिभार लगाने का प्रस्ताव है। इस अधिभार का सामान्यतः कम प्रभाव पड़ेगा। उदाहरण के लिए, जिन मासलों में बुनियादी शुल्क 5 प्रतिशत मूल्यानुसार है, वहां इसकी दर एक प्रतिशत की केवल एक-चौथाई अर्थात् 0.25 प्रतिशत और जहां बुनियादी शुल्क 20 प्रतिशत है, वहां इसकी दर एक प्रतिशत होगी।

92. जिन आवश्यक वस्तुओं और अन्य प्राथमिकता प्राप्त वस्तुओं को इस समय उत्पाद-शुल्क से छूट प्राप्त है, उन्हें अधिभार से छूट प्राप्त होती रहेगी। मैं आप उपभोग की कुछ अन्य जरूरी वस्तुओं, जैसे चीनी, दियासनाइयों, सूती कपड़ों, वनस्पति, परिष्कृत वनस्पति तेल, चाय, काफी और मिट्टी के तेल को भी इस अतिरिक्त शुल्क से छूट दे रहा हूं।

प्रत्यक्ष कर

93. माननीय सदस्यों को याद होगा कि अगस्त 1986 में प्रत्यक्ष कर कानूनों के बारे में एक विचार-पत्र संसद में प्रस्तुत किया गया था। विशेषज्ञों और जनता के साथ और आगे विचार-विमर्श तथा सलाह-मशवरे के बाद, सरकार ने प्रत्यक्ष कर विधियां (संशोधन) विधेयक, 1987 प्रस्तुत किया था, जो पिछले सत्र में पारित किया गया था। इसके बाद से विशेषज्ञों, संबन्धित एसोसिएशनों, वाणिज्य मंडलों और अन्य करदाताओं से इस अधिनियमों के कुछ उपबन्धों के बारे में बहुत से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। इन अभ्यावेदनों में, अन्य बातों के साथ-साथ मुख्य रूप से निम्नलिखित मुद्दे उठाए गए हैं:

- (1) सांझीदारी वाली फर्मों के कर निर्धारण की प्रस्तावित प्रणाली विशेष रूप से कम आय वाली सांझीदारी की फर्मों के लिए बड़ी कठोर है, क्योंकि अब ऐसी फर्मों पर, कतिपय कठौतियों के अध्य-धीन, अधिकतम सीमान्त दर से कराधान किया जाएगा। फर्मों के कराधान से संबंधित कुछ अन्य उपबन्धों के बारे में भी कतिपय अन्य स्पष्टीकरण मांगे गए हैं।

- (2) कतिपय प्राप्तियों की कर योग्यता के बारे में वास्तविक संदेह के मामले में 30 प्रतिशत की एक समान दर से अतिरिक्त कर लगाना बहुत अनुचित होगा, और अतिरिक्त कर लगाए जाने के विरुद्ध भी अरील की अनुमति होनी चाहिए।
- (3) पूर्ण न्यायां, (चैरिटेबिल ट्रस्ट), स्वयंसेवी संस्थाओं और वैज्ञानिक अनुसंधान करने वाली संस्थाओं, आदि से संबन्धित उपबन्धों के परिणामस्वरूप अनचाही कठिनाइयाँ हो सकती हैं, विशेषतः इन संस्थाओं की निधियों में किए जाने वाले अंशदातों के साथ किए जाने वाले व्यवहार के संबंध में।
- (4) नए अधिनियम में केवल राय में परिवर्तन के आधार पर कर-निर्धारण को फिर से खोलने के बारे में निर्वाह छूट दी गई है।

94. इस अधिनियम के बहुत से सकारात्मक पहलू हैं, जिनसे कानून के सरलीकरण द्वारा करदाताओं को सहायता मिलेगी, लेकिन इसके कुछ उपबन्धों के खिलाफ दिए गए अभ्यवेदनों को ध्यान में रखते हुए इन पर पुनर्विचार करने का गुंजाइश है। किसी लोकतांत्रिक समाज में सरकार को हमेशा लोगों की राय से आने आना परिचित रखना चाहिए और युक्तिसंगत सुझावों के प्रति पर्याप्त लचीला रवैया अपनाना चाहिये। सरकार बजट सत्र में एक और संशोधन विधेयक प्रस्तुत करेगी, जिसके द्वारा वास्तविक शिक्षावर्तों का समाधान संभव हो सकेगा। विधेयक के प्रस्तुत किए जाने के बाद, सरकार को ऐसे अन्य सभी सुझावों पर विचार करने में प्रसन्नता होगी, जो माननीय सदस्यों द्वारा दिए जाएंगे।

95. प्रत्यक्ष कर प्रणाली में एक उपयुक्त हद तक स्थिरता होना, विषयगत उत्पन्न करने और बचतों तथा निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए वांछनीय है। इसलिए मेरा वैयक्तिक और निगम करों के दर-ढाँचे में परिवर्तन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

96. लेकिन निश्चित आय वाले वर्गों द्वारा उठाए जा रहे बोझ में कुछ कमी करने की बात में बल है। इसलिए मैं मानक कटौती की दर को बेतन-आय के 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 33-1/3 प्रतिशत करने और उसकी उच्चतम सीमा को 10,000 रुपए से बढ़ाकर 12,000 रुपए करने का प्रस्ताव करता हूँ। इस कदम से लगभग दस लाख कर-दाताओं को लाभ पहुँचेगा।

97. माननीय सदस्यों को याद होगा कि मार्च, 1983 से सम्पदा शुल्क समाप्त कर दिया गया था। इसका मुख्य कारण यह था कि सम्पदा शुल्क सम्बन्धी कानून बड़ा पेचीदा था और उसके परिणामस्वरूप अनेक करदाताओं को भारी दुखद परिस्थितियों में, प्रक्रिया सम्बन्धी कठिनाइयाँ होती थीं, और राजस्व के रूप में नगण्य प्राप्ति होती थी। लेकिन,

विरासत के जरिए धन का जो अन्तरण होता है, उस पर सामाजिक न्याय के आधार पर कर लगाने का पक्ष बड़ा प्रबल है, विशेष रूप से उन मामलों में जहाँ सम्बन्धित सम्पत्ति काफी अधिक हो। यह मामला कुछ समय से सरकार के विचाराधीन था और सरकार ने धन के अन्तरण (ट्रांसफर) पर कर लगाने का फैसला किया है, जो धन-कर के सभी दाताओं पर लागू होगा। यह कर उन परिणामों पर लागू होगा, जिन पर धन-कर लागू होता है। परिसम्पत्तियों के मूल्यांकन का तरीका भी वही होगा, जो धन-कर के मामले में अपनाया जाता है। इसका प्रशासन भी धन-कर अधिकारियों द्वारा किया जाएगा। धन अन्तरण कर की दर धन-कर की मौजूदा लागू दरों का लगभग पाँच गुना होगी। इस नए कर में उन कठोरताओं और प्रक्रियात्मक जटिलताओं से बचा जाएगा, जो पुराने सम्पदा शुल्क अधिनियम के प्रचालन की विशेषताएँ थीं। जैसाकि मैंने कहा है, यह केवल धन-कर के निश्चितियों पर लागू होगा और साधारण करदाताओं को प्रभावित नहीं करेगा। इस सम्बन्ध में इस सत्र में एक प्रयोग विधान प्रस्तुत किया जाएगा।

98. प्रत्यक्ष करों के बारे में मेरे अन्य प्रस्तावों का जोर निर्यात-संवर्धन और विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिए दिए जाने वाले प्रोत्साहनों को सुदृढ़ बनाने, धन को प्रोत्साहित करने और पूंजी बजार को बढ़ावा देने पर है।

99. निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए, मैं निर्यात से होने वाले 100 प्रतिशत मुनाफों को आय-कर से छूट देने के वास्ते, निर्यात-लाभों के लिए धारा 80 जजग के अन्तर्गत दी जाने वाली मौजूदा कर-रियायत में वृद्धि करने का प्रस्ताव करता हूँ। व्यापारिक अथवा निर्यात-गृहों की मार्फत निर्यात करने वाले समर्थनकारी विनिर्माताओं को भी ये लाभ प्रदान करने का प्रस्ताव है। पंचवर्षीय कर-छूटी, जो इस समय मुक्त व्यापार क्षेत्रों में स्थित इकाइयों को उपलब्ध है, 100 प्रतिशत निर्यात-प्रधान इकाइयों को भी दी जा रही है। खड़, काफी और इलायची बागानों में पौधों के पुनरोपण और बागानों के नवीकरण के लिए दी जाने वाली सब्सिडियों को भी आय-कर से छूट देने का प्रस्ताव है।

100. मकानों के निर्माण और खरीद के लिए उपलब्ध दीर्घकालिक वित्त व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए, मैं ऐसे वित्त की व्यवस्था करने वाली कम्पनियों से प्राप्त व्याज और लाभांश-आय के संबंध में धारा 80ड के अन्तर्गत मौजूदा रियायत में वृद्धि करने का प्रस्ताव करता हूँ। इस समय ऐसी आय को 7,000 रुपए की सामान्य छूट सीमा के अन्तर्गत शामिल किया जाता है। प्रस्ताव है कि ऐसी आय को भी धारा 80ड के अधीन भारतीय यूनिट ट्रस्ट के लिए निर्धारित 3,000 रुपए की अलग सीमा के अन्तर्गत छूट का पात्र बना दिया जाए।

101. कर अपवर्चन विरोधी उपाय के रूप में, मैं शराब और वन-संवर्द्धा जैसे कतिपय व्यापार करने वाले व्यक्तियों की आय का निर्धारण उनके द्वारा वस्तुओं की खरीद किए जाते समय अदा की जाने वाली राशि की एक उपयुक्त रूप से निर्धारित प्रतिशतता के अनुसार किए जाने की व्यवस्था करने का प्रस्ताव करता हूँ। यह कर स्रोत पर एकत्र किया जाएगा।

102. किसी धारक कम्पनी द्वारा अपनी पूर्णतः स्वामित्वाधीन सहायक कम्पनी को अथवा पूर्णतः स्वामित्वाधीन सहायक कम्पनी द्वारा अपनी धारक कम्पनी को किए जाने वाले पूंजीगत परिसम्पत्ति के अन्तरण से होने वाली आय पर, उस प्रत्येक मामले में, जहां पूंजीगत परिसम्पत्ति को अन्तरण के समय विक्री-योग्य माल के रूप में इस्तेमाल किया जाए मैं 'पूंजीगत अभिलाभ' शीर्ष के अन्तर्गत कर लगाने का प्रस्ताव करता हूँ।

103. माननीय सदस्यों को याद होगा कि अपने भाषण के भाग 'क' में, मैंने जीवन बीमा निगम द्वारा अदा किए जाने वाले आय-कर में किए जा रहे कुछ परिवर्तनों का और पूंजी बाजार को बढ़ावा देने के कुछ राजकोषीय उपायों का पहले ही उल्लेख किया है। वित्त विधेयक में प्रत्यक्ष करों के बारे में कुछ अन्य मामूली प्रस्ताव भी हैं।

104. इन प्रस्तावों के कुल परिणामस्वरूप राजस्व में 201 करोड़ रुपए की कमी होगी, जो आय कर और धन-कर पर अधिभार को जारी रखने के मेरे प्रस्ताव से, जिससे 270 करोड़ रुपए का लाभ होगा, प्रतिसन्तुलित हो जाएगी, इस प्रकार, राजस्व में 69 करोड़ रुपए की निवल वृद्धि होगी।

अप्रत्यक्ष कर

105. महोदय, अब मैं अप्रत्यक्ष करों से सम्बन्धित प्रस्तावों की ओर आता हूँ। मेरा प्रयास यह सुनिश्चित करना रहा है कि पिछले वर्ष के बजट में अप्रत्यक्ष करों के क्षेत्र को जो बुनियादी दिशा प्रदान की गई थी, उसे आगे बढ़ाया जाए। इस बारे में कृषि और खेती के क्षेत्रों, ग्रामीण रोजगार, निर्यात, स्वास्थ्य और चिकित्सा, आवास और निर्माण सम्बन्धी क्रियाकलापों, निर्यात, प्रौद्योगिकी के उन्नयन और सीमेंट, कपड़ा, इलेक्ट्रानिकी, कागज और प्लास्टिक जैसे चुने हुए उद्योगों को बढ़ावा देने के प्रस्ताव हैं। आम आदमी के लिए कुछ महत्वपूर्ण राहतें भी हैं।

कृषि और अन्य सम्बद्ध क्षेत्र

106. अपने भाषण के भाग "क" में, मैंने किसानों के लाभ के लिए कुछ उपायों की घोषणा की है, जिनमें व्याज की दरों में कमी करना और उर्वरकों जैसी निविष्टियों की लागत में कमी करना भी शामिल है। अब मैं कृषि और कृषि-आधारित क्रियाकलापों के संवर्धन के लिए कई राजकोषीय राहतों का प्रस्ताव करता हूँ।

107. मोनोब्लाक पम्प सैट और सबमर्सिबल पम्प सैट सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण है। मैं इन पम्प सैटों में इस्तेमाल की जाने वाली बिजली की मोटरों को उत्पादन-शुल्क से छूट दे रहा हूँ।

108. किसानों को आने वाली लागत को कम करने के लिए मेरा प्रस्ताव कीटनाशक औषधों संबंधी बहुत सी मध्यवर्ती वस्तुओं को उत्पाद-शुल्क से पूर्णतः छूट देने का है। मेरा यह भी प्रस्ताव है कि बहुत सी कीटनाशक औषधों और उनसे सम्बन्धित मध्यवर्ती वस्तुओं के सम्बन्ध में सीमा-शुल्क को 105 प्रतिशत और 147 प्रतिशत के मौजूदा स्तरों से घटाकर 70 प्रतिशत और 60 प्रतिशत मूल्यानुसार कर दिया जाए। इससे स्वदेशी उत्पादन की लागत और अन्तिम कीमतों में कमी आएगी।

109. कृषि, बागवानी, मुर्गीपालन और मधुमक्खी पालन के क्षेत्रों में आधुनिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए मैं इन क्षेत्रों में काम आने वाली मशीनों, जैसे स्प्रींकलर सिस्टमों, चारा मिक्सरों, अंकुरण उपकरणों, अंडा कैंडलरों, आदि को उत्पाद-शुल्क से पूर्ण छूट देने की व्यवस्था कर रहा हूँ।

110. कृषि उत्पादों के विपणन के लिए प्रशीतन भंडारों (कोल्ड स्टोरेज) का बहुत महत्व है। मैं प्रशीतन भंडारों के संयंत्रों की स्थापना में काम आने वाले हिस्सों और सहायक वस्तुओं पर लगने वाले उत्पाद शुल्क को 40 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत मूल्यानुसार करने का प्रस्ताव करता हूँ।

111. जैसा कि सदन को ज्ञात है, सरकार ने पशुओं और भैंसों की नस्ल में सुधार के जरिए दूध के उत्पादन में वृद्धि करने का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम शुरू किया है। तदनुसार, इस कार्यक्रम के लिए आवश्यक कतिपय महत्वपूर्ण उपकरणों, हार्मोनों और औषधियों को 25 प्रतिशत मूल्यानुसार का सीमाशुल्क से मुक्त किया जा रहा है।

खाद्य प्रसंस्करण और पैकेजबंदी

112. खाद्य प्रसंस्करण (प्रोसेसिंग) और पैकेजबंदी उद्योग के विकास से कृषि उत्पादों के मूल्य-वर्धन और किसानों की आमदनी को बढ़ाने में भारी सहायता मिल सकती है। प्रधान मंत्री द्वारा इस उद्योग के विकास के लिए पिछले वर्ष घोषित कुछ उपायों के अनुक्रम में, खाद्य प्रसंस्करण (प्रोसेसिंग) और पैकेजबंदी उद्योग की 34 विनिर्दिष्ट मदों के सम्बन्ध में सीमा-शुल्क को 55 प्रतिशत से घटा कर 35 प्रतिशत मूल्यानुसार करने का प्रस्ताव है। मैं सब्जियों, फलों, गिरियों और पौदों के अन्य भागों से तैयार वस्तुओं जैसे जाम, फलों का रस, आदि पर उत्पाद शुल्क को 10 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत मूल्यानुसार करने का भी प्रस्ताव करता हूँ। सब्जियों और फलों से तैयार जो चीजें जैसे जाम, जेली, फलों का रस, चटनी, केचप और अचार,

आदि ग्रामीण क्षेत्रों में पंजीकृत सहकारी समितियों, खादी और ग्रामोद्योग आयोग और राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्डों द्वारा बनाई जाएंगी, उन्हें उत्पाद-शुल्कों से पूर्णतः छूट देने का प्रस्ताव है।

113. मैं एल्यूमिनियम की पत्तियों पर उत्पाद-शुल्क को 25 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत मूल्यानुसार करने का प्रस्ताव करता हूँ। इससे प्रसंस्कृत खाद्यों, औषधों, मसालों, आदि की अधिक स्वास्थ्यकर और वैज्ञानिक पैकेजबन्दी करने में सहायता मिलेगी।

ग्रामीण रोजगार

114. खेत से बाहर का स्व-रोजगार ग्रामीण क्षेत्रों में आय को बढ़ाने का एक प्रमुख साधन है। वैयक्तिक रूप में, एक लघु उद्यमकर्ता, जिसकी टिके रहने की सामर्थ्य कम होती है, बाजार की प्रतिकूल शक्तियों से प्रभावित हो जाता है। उसकी सफलता सहकारी उद्यमों में निहित है। इसलिए, मैं ग्रामीण क्षेत्रों में स्व-रोजगार के सृजन की विशेष स्कीम के लिए व्यवस्था कर रहा हूँ। प्रस्तावित स्कीम के अन्तर्गत, विनिर्दिष्ट उत्पाद, यथा रेडियो, कैसेट प्लेयर और टेप रिकार्डर, संयुक्त रूप से रेडियो, टेप रिकार्डरों, वोल्टेज स्टेबिलाइजरों और 75 रुपए प्रति जोड़े से अनधिक कीमत वाले जूते और अन्य वस्तुएँ उत्पाद-शुल्क से पूरी तरह से मुक्त होंगी, यदि उनका निर्माण ग्रामीण क्षेत्रों में पंजीकृत सहकारी समितियों, जिनमें स्वतः नियोजित महिलाओं की सहकारी समितियाँ अथवा ग्रामीण क्षेत्रों में महिला और बाल विकास की स्कीम के अन्तर्गत बनी सहकारी समितियाँ भी शामिल हैं, अथवा खादी और ग्रामोद्योग आयोग अथवा राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्डों द्वारा किया जाएगा।

115. जैसा कि माननीय सदस्यों को विदित हैं, बड़इयों, फिटरों, इलेक्ट्रिशियनों, नलसाजों आदि के रूप में लोगों की बहुत बड़ी संख्या स्वरोजगार में लगी हुई है। उनके परिश्रमी हाथों को और शक्ति प्रदान करने तथा उनकी उत्पादकता व कमाई बढ़ाने के दोहरे उद्देश्यों से, मेरा प्रस्ताव कुछ दस्ती औजारों जैसे रेतियों, पेचकसों, चिमटों (प्लायर), आदि के मामले में उत्पाद-शुल्क को 20 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत मूल्यानुसार करने का है।

116. बेहतर लेखापालन को बढ़ावा देने और व्यापारियों, शहरी दुकानदारों, छोटे व्यवसायियों, थोक विक्रेताओं और छोटे कारखानेदारों को दिन की समाप्ति पर हिसाब-किताब करने के नीरस काम से छुटकारा दिलाने के लिए, मैं 10,000 रुपए या उससे कम के निर्धारण-योग्य मूल्य के छोटे इलेक्ट्रानिक नकदी रजिस्ट्रों पर उत्पादन शुल्क को 20 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूँ।

उपभोक्ता वस्तुएँ

117. मैं जानता हूँ कि आम उपभोक्ताओं पर कुछ कीमतों में वृद्धि का प्रभाव पड़ा है। मैं उन्हें उन सीमाओं के अन्दर, जिनमें मुझे काम करना पड़ रहा है, कुछ राहत प्रदान करना चाहता हूँ।

118. मेरा प्रस्ताव, सामान्य रूप से इस्तेमाल किए जाने वाले नहाने के साबुन की बहुत सी किस्मों के संबंध में मूल्यानुसार 15 प्रतिशत की रियायती दर पर उत्पाद शुल्क लागू करने के प्रयोजनार्थ ऊपरी मूल्य सीमा को 25,000 रुपए से बढ़ाकर 30,000 रुपए करने का है। मेरा प्रस्ताव, ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी समितियों तथा खादी और ग्रामोद्योग क्षेत्र द्वारा विनिर्मित कपड़े धोने के साबुन तथा कार्बो-लिक साबुनों को उत्पाद शुल्क से पूर्णतः मुक्त करने का भी है।

119. अभी तक 60 वाट तक के बिजली के बल्ब उत्पाद शुल्क से मुक्त हैं। घरों, सड़कों, कार्य-स्थलों आदि पर ज्यादा रोशनी की व्यवस्था करने के उद्देश्य से मेरा प्रस्ताव 60 वाट से अधिक के बिजली के बल्बों के संबंध में उत्पाद शुल्क को 1.50 रुपए प्रति बल्ब से कम करके 1.00 रुपया प्रति बल्ब करने का है।

120. बच्चों के बीच अधिक शिक्षा और खुशी पैदा करने के एक उपाय के रूप में मेरा प्रस्ताव, टाय स्कूटरों, टाय पेडल कारों, गुड़ियों, टाय संगीत वाद्यों, स्केल माडलों, मनोरंजनात्मक माडलों आदि जसे खिलौनों तथा सस्ते पेंसिल शार्पनरों को उत्पाद शुल्क से पूर्णतः मुक्त करने का है।

121. घरेलू नीरसता को कम करने के उद्देश्य से मेरा प्रस्ताव फ्राइंग पेन से सासपेन जैसे बिजली के कुछ घरेलू उपकरणों को उत्पाद शुल्क से पूर्णतः मुक्त करने का है। इसी प्रकार, मैं बिजली की केतलियों, वाटर वायलरों, टोस्टरों और आटोमैटिक आयरनों को भी छूट दे रहा हूँ। मैं स्टेनलेस स्टील के बर्तनों को भी उत्पाद शुल्क से पूर्णतः मुक्त कर रहा हूँ।

122. तस्करी-विरोधी उपाय के एक और उपाय के रूप में तथा समय के प्रति और अधिक जागरूकता की भावना पैदा करने तथा स्कूल जाने वाले बच्चों, कालेजों के छात्रों, कार्यालय जाने वालों, सामान्य जनता और यदि मैं कहूँ तो हमारे जैसे राजनीतिज्ञों के बीच भी अधिक समयपालन की भावना जाग्रत करने के लिए मेरा प्रस्ताव दीवार घड़ियों तथा क्वार्टज घड़ियों और उनके पुर्जों पर उत्पाद शुल्क को 15 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत मूल्यानुसार करने का है। मैं बाद में अपने भाषण में स्वदेशी घड़ी उद्योग के लिए कुछ राहतों की घोषणा करूँगा।

123. कांच के बर्तनों के मामले में, मेरा प्रस्ताव, स्व-चालित प्रक्रिया द्वारा विनिर्मित जगों, कपों, प्लेटों, बाउलों आदि जैसे आम इस्तेमाल के भोजन-पात्रों की बहुत सी मर्दों के संबंध में उत्पाद-शुल्क को 40 प्रतिशत से कम करके 25 प्रतिशत मूल्यानुसार करने तथा अर्ध-स्वचालित/माउथ ब्लोन प्रक्रियाओं द्वारा विनिर्मित मर्दों पर उत्पाद-शुल्क को घटाकर 20 प्रतिशत मूल्यानुसार करने का है।

124. मेरा प्रस्ताव सभी बाल फिल्मों तथा उन सभी फिल्मों को उत्पाद शुल्क से मुक्त करने का भी है जो अन्तराष्ट्रीय फिल्म समारोहों के भारतीय पैनरमा खण्ड के लिए चुनी जाती हैं।

125. यशस्वी और श्रद्धालु स्त्रियों के युगों पुराने प्रतीकों, जैसे कि सिन्दूर, काजल, आल्टा और महावर को कर-मुक्त करने के लिए सरकार के वार्षिक बजट से बेहतर कोई शुभ अवसर नहीं हो सकता और इसलिए मैं उन्हें तत्काल उत्पाद शुल्क से पूर्णतः मुक्त करने का प्रस्ताव करता हूँ।

स्वास्थ्य और चिकित्सा

126. हमारा उद्देश्य सभी देशवासियों को सस्ती और कुशल चिकित्सा प्रदान करना है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जरूरी दवाइयों की कम कीमतों पर उपलब्धता सुनिश्चित की जानी है। इसलिए मेरा इरादा उत्पाद टैरिफ को यथा संभव, नए औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1987 के अनुरूप बनाने का है। मेरा प्रस्ताव, औषध मूल्य नियंत्रण आदेश की श्रेणी I में विनिर्दिष्ट थोक औषधियों तथा फार्मूलेशनों को उत्पाद शुल्क से पूर्ण रूप से छूट प्रदान करने का है। इन औषधियों के लिए मध्यवर्ती मर्दों भी उत्पाद शुल्क से पूर्णतः मुक्त होगी। सदन को याद होगा कि श्रेणी I में विनिर्दिष्ट औषधियों की क्षय रोग, कुष्ठ रोग, मलेरिया, फिलेरिया उन्मूलन कार्यक्रमों तथा अन्वेषण और रोह रोग के नियंत्रण वाले कार्यक्रमों तथा निर्जलीकरण को रोकने जैसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के लिए जरूरत होती है।

127. औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश की श्रेणी II में विनिर्दिष्ट औषधियों पर आधारित एकल संघटक वाले फार्मूलेशनों के लिए 10 प्रतिशत मूल्यानुसार उत्पाद शुल्क की रियायती दर निर्धारित की जा रही है। मेरा प्रस्ताव, विशिष्ट हृदयौषधि, क्षयरोग-विरोधी, मलेरिया-विरोधी, कुष्ठरोग विरोधी और मधुमेह विरोधी औषधियों के संबंध में मौजूदा उत्पाद शुल्क संबंधी छूटों को जारी रखने का भी है। दो कैसर-विरोधी औषधियों तथा एक महत्वपूर्ण जीवन रक्षक औषधि को भी मुक्त औषधियों की सूची में शामिल करने का प्रस्ताव है। तथापि, मेरा प्रस्ताव, उन विनिर्दिष्ट फार्मूलेशनों के संबंध में सीमा शुल्क से मौजूदा छूट को वापस

लेने का है, जिनके लिए पर्याप्त स्वदेशी क्षमता का निर्माण हो चुका है। आशा है कि इस राजकोषीय राहत से इन महत्वपूर्ण औषधियों के स्वदेशी उत्पादन और उपलब्धता को प्रोत्साहन मिलेगा।

128. मेरा, औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश की श्रेणी I में सम्मिलित थोक औषधियों को छोड़कर, अन्य थोक औषधियों पर 5 प्रतिशत मूल्यानुसार का मामूली उत्पाद शुल्क लगाने का प्रस्ताव है। इससे, विनिर्माता, औषध मध्यवर्तियों सहित सभी कर-योग्य निविष्टियों के संबंध में मोड-वाट क्रेडिट का लाभ उठा सकेंगे। मैं 235 विनिर्दिष्ट औषध मध्यवर्तियों पर भी आयात-शुल्क को 115 प्रतिशत से घटाकर 90 प्रतिशत मूल्यानुसार करने का प्रस्ताव करता हूँ।

129. चिकित्सा उपस्करों के सम्बद्ध क्षेत्र में सरकारी तथा सरकार द्वारा नियंत्रित अस्पतालों द्वारा, सीमाशुल्क मुक्त अस्पताल उपस्कर, उपकरण, औजार, जिनमें अतिरिक्त और सहायक पुर्जें भी शामिल हैं, आयात करने की प्रक्रिया को सरल बनाया जा रहा है। इसी प्रकार, 40 प्रतिशत मूल्यानुसार के रियायती शुल्क पर विनिर्दिष्ट परिष्कृत चिकित्सीय उपस्कर आयात करने की प्रक्रिया को भी दोष-रहित बनाया जा रहा है। अनिवासी भारतीयों द्वारा अपने विदेशी मुद्रा संसाधनों से किए गए ऐसे आयातों के संबंध में शुल्क और भी कम अर्थात् 20 प्रतिशत लगेगा। सरकार से सरकार को सहायता द्वारा वित्त पोषित होने पर ऐसे उपस्करों का आयात सीमा-शुल्क से मुक्त होगा।

130. मैं ऐसे विनिर्दिष्ट उपस्करों के अतिरिक्त पुर्जों पर भी 40 प्रतिशत मूल्यानुसार की रियायती दर लागू करने का प्रस्ताव करता हूँ। 40 प्रतिशत मूल्यानुसार की रियायती सीमा शुल्क दर वाली चिकित्सीय उपस्करों की सूची में 83 दन्त चिकित्सीय, नेत्र विज्ञान संबंधी, हृदयरोग संबंधी, स्त्री रोग संबंधी, सामान्य शल्य चिकित्सा संबंधी तथा अन्य चिकित्सीय उपस्करों को शामिल करके उसे विस्तृत किया जा रहा है। इन उपस्करों के संघटकों पर भी 80 प्रतिशत से लेकर 130 प्रतिशत तक की वर्तमान मूल्यानुसार दर के स्थान पर 40 प्रतिशत की दर से शुल्क लिया जाएगा ताकि इन उपस्करों के घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहन मिल सके।

131. मेरा प्रस्ताव स्वदेश में बननेवाले इन उपस्करों पर उत्पाद शुल्क को 15 प्रतिशत से कम करके 5 प्रतिशत मूल्यानुसार करने का है। एकसरे फिल्मों पर भी उत्पाद शुल्क को 15 प्रतिशत से कम करके 5 प्रतिशत मूल्यानुसार करने का प्रस्ताव है। कृत्रिम अंगों के विनिर्माण में उपयोग में लाई जाने वाली वर्गाकार और गोलाकार ट्यूबों, एल्यूमिनियम की छड़ों (एक्स्ट्रूशन) को उत्पादन-शुल्क से बिल्कुल मुक्त किया जा रहा है।

132. मुझे उम्मीद है कि देश भर के हमारे निष्ठावान डाक्टर अब अपने अस्पतालों और क्लिनिकों को कुछ और तेजी से आधुनिक बना सकेंगे और इसके फलस्वरूप रोगियों को बेहतर इलाज व देखभाल प्राप्त हो सकेगी।

आवास

133. जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया था, मकान-निर्माण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मकान निर्माण संबंधी सामग्री की लागत कम करना जरूरी है। इसलिए मेरा प्रस्ताव सीमेंट पर उत्पादन शुल्क को 225 रुपए प्रति मी० टन से कम करके 205 रु० प्रति मी० टन करने का है। कुछ प्रकार के सीमेंट के लिए उत्पाद शुल्क की मौजूदा विभेदक दरें भी जारी रहेंगी। कुछ श्रेणियों के सीमेंट यूनिटों के लिए शुल्क अनुपातों को भी घटाया जा रहा है।

134. पर्यावरण के संरक्षण और लकड़ी के स्थान पर धातु की मांग को बढ़ाने में मदद देने के लिए, एल्यूमिनियम से बनी दरवाजों की चौखटों, दरवाजों, खिड़कियों और उनके फ्रेमों पर उत्पाद शुल्क को 20 प्रतिशत से कम करके 15 प्रतिशत मूल्यानुसार किया जा रहा है। इसी प्रकार, एल्यूमिनियम की नालीदार चादरों पर उत्पाद शुल्क को 25 प्रतिशत से कम करके 15 प्रतिशत मूल्यानुसार किया जा रहा है। मेरा प्रस्ताव स्टील के दरवाजों, खिड़कियों और उनके फ्रेमों तथा दरवाजों की चौखटों पर उत्पाद-शुल्क को 15 प्रतिशत से कम करके 5 प्रतिशत मूल्यानुसार करने का है।

135. अब उपयुक्त समय है कि हम नए सिरे से सोचें और मकान बनाने के लिए गैर-परम्परागत सामग्री का इस्तेमाल करें, जो सस्ती और प्रयोजन मूलक सिद्ध होगी। ब्लाकों, स्लेबों, लिफ्टलों आदि पर, जो प्री-फैब्रिकेटेड भवनों के संरचनात्मक मध्यवर्ती और संघटक हैं, उत्पाद शुल्क को 12 प्रतिशत से कम करके 5 प्रतिशत मूल्यानुसार किया जा रहा है। इस प्रकार, फ्लाई ऐश ईंटों पर 5 प्रतिशत मूल्यानुसार की कम दर पर शुल्क लगेगा तथा लिफ्टों पर, जो सीमेंट का एक प्रतिस्थापन हैं, कोई शुल्क नहीं लगेगा।

136. अग्नि सम्बन्धी संकट को कम करने के लिए हमें अग्निशामकों के उपयोग को बढ़ावा देना चाहिए। इस बात को ध्यान में रखते हुए मेरा प्रस्ताव अग्निशामकों को उत्पाद शुल्क से मुक्त करने का है।

निर्यात

137. अत्यन्त प्रतियोगी अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में टिके रहने के लिए हमें अपने प्राकृतिक लाभों तथा उत्पादन प्रयासों के साथ-साथ पर्याप्त राजकोषीय व अन्य उपाय भी करने होंगे। इस संदर्भ में, मैं निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ और उपायों का प्रस्ताव करता हूँ।

138. निर्धारित निर्यात-प्रवण क्षेत्र के लिए मशीनरी की विनिर्दिष्ट मर्दों पर विगत में सीमा शुल्क की रियायती दरों की व्यवस्था थी। सिले-सिलाए वस्त्रों तथा होजरी क्षेत्र की आठ और मशीनों, चर्म उद्योग की 23 मशीनों, रत्न और आभूषण उद्योग के लिए चार और मशीनों तथा टेक्स-टाइल मशीनरी की तीन और मर्दों पर अब 35 प्रतिशत मूल्यानुसार की रियायती दर से शुल्क लगेगा। चाय, बाइसिकिल, रेशम तथा ऊनी उद्योगों के लिए मशीनरी की विनिर्दिष्ट मर्दों पर 35 प्रतिशत मूल्यानुसार रियायती सीमा-शुल्क लगेगा।

139. हाथी दांत और हाथीदांत के चूरे को सीमा शुल्क से बिल्कुल मुक्त किया जा रहा है। इससे हमारे जंगलों में अनधिकृत शिकार को कम करने में मदद मिलेगी और साथ ही हाथीदांत सम्बन्धी हस्तशिल्प के लिए, जो निर्यात प्रधान उद्योग है, पर्याप्त कच्चा माल उपलब्ध हो सकेगा।

140. वाणिज्यिक नमूनों के शुल्क-मुक्त आयात की मूल्य-सीमा को एक वर्ष में 1000 रुपए से बढ़ाकर 5,000 रुपए किया जा रहा है, और इंजीनियरी वस्तुओं के प्रोटो-टाइपों के शुल्क-मुक्त आयात की मूल्य सीमा को 1000 रुपए से बढ़ाकर 10,000 रुपए किया जा रहा है।

141. कारखानों में सीधे ही निर्यात की जाने वाली चाय के मामले में अब उत्पाद शुल्क की पूरी छूट प्राप्त होगी। व्यापारी निर्यातकों द्वारा अ-मिश्रित चाय के निर्यात पर उत्पाद-शुल्क में छूट प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल बनाया जा रहा है। हरी चाय को उत्पाद शुल्क से बिल्कुल मुक्त किया जा रहा है।

पूँजीगत वस्तुएं

142. आधुनिक औद्योगिक विश्व में, मशीनें बहुत जल्द पुरानी पड़ जाती हैं। यदि कोई प्रौद्योगिकी का निरन्तर उन्नयन नहीं करता, तो वह पिछड़ जाता है। पिछले वर्ष के बजट भाषण में प्रधान मंत्री द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसरण में मैंने अगस्त 1987 में प्रौद्योगिकी उन्नयन की एक स्कीम की घोषणा की थी, जिसके अन्तर्गत स्कीम में शामिल मशीनरी के विनिर्माण के लिए अपेक्षित पूँजीगत उपस्कर की विनिर्दिष्ट मर्दों के आयात के संबंध में 35 प्रतिशत मूल्यानुसार रोजकोषीय राहत प्रदान की गई थी, ऐसी मशीनरी के घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए, उनके उत्पादन के लिए आवश्यक चुनी हुई कच्ची सामग्री पर सीमा शुल्क को मौजूदा लगभग 100 प्रतिशत से लेकर 180 प्रतिशत तक के स्तर से घटाकर 55 प्रतिशत किया जा रहा है। इनमें विद्युत निर्माण के लिए विशिष्ट इंसुलेशन सामग्री, तांबे के कंडक्टर और विशेष विद्युतीय इस्पात शीट और प्रौद्योगिकी उन्नयन स्कीम में विनिर्दिष्ट चुनी हुई औद्योगिक मशीनरी के विनिर्माण के लिए विद्युतीय उपस्कर तथा क्लेड स्टील प्लेटें शामिल हैं। बायलर और प्रेशर वेसल

क्वालिटी स्टील प्लेटों, टरबाइन ब्लेड फ्लैट्स तथा मशीनरी के विनिर्माण के लिए आवश्यक स्टेनलेस स्टील प्लेटों पर सीमा-शुल्क को 90 प्रतिशत से घटाकर 55 प्रतिशत किया जा रहा है।

वैज्ञानिक उपस्कर और अतिरिक्त पुर्जें

143. वैज्ञानिकों द्वारा सदा यह मांग की जाती रही है कि अनुसंधान के लिए आवश्यक उपभोग्य वस्तुओं तथा आयातित उपस्कर के अतिरिक्त पुर्जों के संबंध में और राज-कोषीय रियायतें प्रदान की जानी चाहिए। वैज्ञानिक अनुसंधान के महत्व को ध्यान में रखते हुए, कर-रियायत संबंधी विद्यमान स्कीमों को उदार बनाया जा रहा है। प्रमाणीकरण प्रक्रियाओं को, जो इन वस्तुओं की निकासी के मामले में बाधक सिद्ध हो रही हैं, सरल बनाया जा रहा है।

144. कुछ विनिर्दिष्ट वैज्ञानिक उपकरणों तथा यंत्रों पर मौजूदा 15 प्रतिशत की दर के स्थान पर 5 प्रतिशत मूल्यानुसार उत्पाद शुल्क लगेगा।

वस्त्रोद्योग

145. भारत के औद्योगिक मानचित्र में वस्त्रोद्योग का अद्यतनीय स्थान है। यह उद्योग देश के लाखों लोगों को रोजगार देता है, मुख्य निर्यातक के रूप में आय का उपार्जन करता है और कृषि के क्षेत्र से सीधे जुड़ा हुआ है। पिछले कुछ समय से यह उद्योग व्यापक रूप से पीड़ित है और इसका विकास अस्त-व्यस्त रूप में हुआ है। कपास और सूत की उपलब्धता और कीमतों में भी काफी अस्थिरता बनी रही है। सूत की कीमतों के कारण हथकरघा बुनकरों पर भी प्रभाव पड़ा है। समग्र कठिनाइयों के कारण विद्युत चालित करघों की भी कुछ समस्याएं हैं। यद्यपि संश्लिष्ट यार्न के उत्पादन में, जिसका उपयोग मिश्रित फेब्रिकों के निर्माण के लिए किया जाता है, जिन्हें टिकाऊ होने के कारण जनसाधारण द्वारा बहुत पसंद किया जाता है, वृद्धि हुई है किन्तु ऐसे यार्न की कीमतें बहुत ऊंची रही हैं। तस्करी एक अन्य समस्या है, जिसका असर, सरकार द्वारा की गई कड़ी कार्रवाई के बावजूद भी, कुछ हद तक प्रतिकूल ही रहा है।

146. इन समस्याओं पर काबू पाने के उद्देश्य से वर्ष 1985 में सरकार ने एक नई टेक्सटाइल नीति की घोषणा की थी। इस नीति का मुख्य उद्देश्य मुनासिब कीमतों पर लोकप्रिय किस्मों के कपड़े के उत्पादन में वृद्धि करना है। इसी नीति के अनुसार सरकार ने बहुत से कदम उठाए हैं। इन कार्यवाहियों के अच्छे परिणाम निकले हैं, जो कि कपड़े के उत्पादन और उसकी उपलब्धता में होने वाली वृद्धि से स्पष्ट हैं। मैं अब वस्त्रोद्योग मंत्रालय द्वारा की जा रही कोशिशों को कुछ राजकोषीय समर्थन प्रदान करने

का प्रस्ताव करता हूँ। इस उद्योग का पुनरुद्धार करने से एक बार फिर यह उद्योग हमारी अर्थव्यवस्था में अपना सही स्थान प्राप्त कर सकता है। मेरे प्रस्ताव, जो नीचे दिये गये हैं, इस उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित शुल्क-ढांचे की व्यापक समीक्षा पर आधारित हैं, जिनका उद्देश्य कीमतों को कम करना, फेब्रिकों की मांग में वृद्धि करना और उत्पादन के आधार को बढ़ाना है।

147. वर्ष 1985 में, सरकार द्वारा अनुमोदित एक योजना के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट फेब्रिकों के विनिर्माण के लिए हथकरघा क्षेत्र को शुल्क-मुक्त पोलिएस्टर स्टेपल फाइबर उपलब्ध कराने के लिए एक योजना बनाई गई थी। मैं अब, वस्त्रोद्योग मंत्रालय द्वारा फेब्रिकों के पूर्ति-प्रबंध और वितरण के संबंध में घोषित की जाने वाली एक योजना के अन्तर्गत हथकरघों से विनिर्मित किए जाने वाले फेब्रिकों के लिए उपयोग में लाए जाने वाले पोलिएस्टर फिलामेंट यार्न पर उत्पाद-शुल्क में कमी करने का प्रस्ताव रखता हूँ। इसी प्रकार से विस्कोस फिलामेंट यार्न पर भी, उस दशा में जब कि इस यार्न को पंजीबद्ध हथकरघा सहकारी समितियों अथवा हथकरघा विकास के लिए स्थापित किसी मान्यताप्राप्त संगठन को सप्लाई किया जाए, विद्यमान शुल्क के 50 प्रतिशत के बराबर की दर से रियायती शुल्क लगेगा।

148. मैं, मान्यताप्राप्त स्वायत्त संसाधकों द्वारा हथकरघों से तैयार किए जाने वाले ऊनी फेब्रिकों को भी उत्पाद-शुल्क से छूट देने का प्रस्ताव करता हूँ। कतिपय विनिर्दिष्ट हथकरघा अभिकरणों द्वारा कच्चे ऊन के आयात को भी सीमा-शुल्क से मुक्त किया जा रहा है। एसिटेट फिलामेंट यार्न पर आयात-शुल्क को 60 प्रतिशत से घटाकर 45 प्रतिशत किया जा रहा है।

149. सूती यार्न की कीमतों को कम करने के प्रयोजन से, 35 काउंट से अधिक काउंट के सूती यार्न पर उत्पाद-शुल्क की मौजूदा दरों में 10 प्रतिशत कमी करने का प्रस्ताव है। पैंतीस से अधिक काउंट वाले सूती यार्न के उत्पाद-शुल्क में 3 पैसा प्रति काउंट के हिसाब से कमी की जा रही है। इसका अर्थ यह होगा कि यार्न के काउंट के हिसाब से अधिक से अधिक 28.5 प्रतिशत तक की कमी हो जाएगी। हथकरघा के लिए हैंक यार्न पर पहले ही पूरी छूट है। जैसाकि मैंने उल्लेख किया था, हथकरघा बुनकरों को और राहत प्रदान करने के लिए जनता कपड़े पर दी जाने वाली सब्सिडी में 75 पैसे प्रति वर्गमीटर की वृद्धि करके उसे 2 रुपए से 2 रुपए 75 पैसे किया जा रहा है।

150. इस तथ्य पर विचार करते हुए कि सूत के स्थान पर विस्कोस स्टेपल फाइबर का आसानी से उपयोग किया जा सकेगा, मैं ऐसे विस्कोस स्टेपल फाइबर पर, जिसकी निकासी सूत के साथ सम्मिश्रित किए जाने के लिए कर दी गई हो, उत्पाद-शुल्क को 7 रुपए प्रति किलोग्राम के मौजूदा स्तर से घटाकर 5 रुपए प्रति किलोग्राम कर देने

का प्रस्ताव करता हूँ। इसी के साथ-साथ मैं अन्य प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाए जाने वाले विस्कोस स्टेपल फाइबर पर शुल्क को बढ़ाकर 8 रुपए प्रति किलोग्राम करने का प्रस्ताव रखता हूँ ताकि सूत के साथ मिश्रित किए जाने के लिए पहले से अधिक मात्रा में विस्कोस स्टेपल फाइबर का उपयोग होने लगे।

151. राष्ट्रीय वस्त्रोद्योग निगम पहले से ही एक विशेष योजना के अन्तर्गत सस्ते फेब्रिकों का विनिर्माण कर रहा है, जिन्हें के लिए उत्पाद-शुल्क से मुक्त पोलिएस्टर स्टेपल फाइबर मुहैया किया जाता है। मैं इस आशय की व्यवस्था करने का प्रस्ताव रखता हूँ कि शुल्क क्रेडिट योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय वस्त्रोद्योग निगम को फेब्रिकों का विनिर्माण करने के लिए पोलिएस्टर फिलामेंट यार्न 10 रुपए प्रति किलोग्राम की रियायती शुल्क दर पर उपलब्ध करा दिया जाए। संबद्ध व्यौरे को घोषणा अलग से की जाएगी।

152. वस्त्रोद्योग नीति के अनुरूप बड़े हुए घरेलू उत्पादन को संतुष्ट करने के उद्देश्य से मैं हाथ से बने तंतु और यार्न पर राजकोषीय उदग्रहणों में कमी किए जाने का प्रस्ताव करता हूँ। इस कार्रवाई से पावरलूम क्षेत्र भी जो कि इस समय क्षमता के निम्नस्तरीय उपयोग की समस्याओं और फलतः बेरोजगारी की समस्याओं का सामना कर रहा है, फिर से सज्जत और सक्षम हो जाएगा। पोलिएस्टर स्टेपल फाइबर पर शुल्क को 25 रुपए प्रति किलोग्राम से घटाकर 15 रुपए प्रति किलोग्राम और पोलिएस्टर फिलामेंट यार्न पर शुल्क को 83.75 रुपए प्रति किलोग्राम से घटाकर 53.75 रुपए प्रति किलोग्राम किया जा रहा है। इसके साथ-साथ अधिक उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा घरेलू-उत्पादकों पर कुछ दबाव डालने के उद्देश्य से, ताकि वे उत्पाद शुल्क में कटौती को पूर्णतः उपभोक्ताओं तक पहुंचाएं इन मदों के आयात-शुल्कों में भी लगभग 25 प्रतिशत की कमी की जा रही है।

153. नाइल-फिलामेंट यार्न के उत्पाद-शुल्क को, 70 रुपए प्रति किलोग्राम से कम करके 40 रुपए प्रति किलोग्राम और एक्रिलिक फाइबर के शुल्क को 10 रुपए प्रति किलोग्राम से कम करके 8 रुपए प्रति किलोग्राम किया जा रहा है। इन मदों पर सीमा-शुल्क में भी समुचित कमी की जा रही है।

154. औद्योगिक प्रयोजनों, जैसे कि साइकिलों के टायरों और औद्योगिक फिल्टर फेब्रिकों के विनिर्माण के लिए उपयोग में लाए जाने वाले नाइलन फिलामेंट यार्न पर उत्पाद-शुल्क को 70 रुपए प्रति किलोग्राम से घटाकर 8.13 रुपए प्रति किलोग्राम करने का भी प्रस्ताव है। मछली पकड़ने के जालों के लिए इस्तेमाल होने वाले विनिर्दिष्ट डेनियर के नाइलन फिलामेंट यार्न पर इससे भी कम अर्थात् 4.55 रुपए प्रति किलोग्राम की रियायती दर से शुल्क लगेगा।

155. मैं कपड़ा मिलों के आधुनिकीकरण के लिए आवश्यक कतिपय विनिर्दिष्ट किस्म की वस्त्रोद्योग संबंधी मशीनरी पर लगने वाले उत्पाद-शुल्क को 15 प्रतिशत मूलानुसार से घटाकर 5 प्रतिशत मूलानुसार करने का प्रस्ताव करता हूँ। जैसा पहले कहा गया था, सिले-सिलाए वस्त्रों, होजरी और ऊनी उद्योगों के लिए उपयोगी कतिपय किस्म की विनिर्दिष्ट मशीनरी पर सीमा-शुल्क को घटाकर 35 प्रतिशत किया जा रहा है।

156. माननीय सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि इन व्यापक राजकोषीय उपायों से तथा इनके समर्थन में वस्त्रोद्योग मंत्रालय द्वारा किए गए अन्य उपायों से वस्त्रोद्योग को बढ़ावा मिलेगा और लाखों कामगारों का रोजगार भली-भांति सुरक्षित रखने में मदद मिलेगी। इन उपायों से राष्ट्रीय वस्त्रोद्योग निगम के कारखानों के कार्यचालन में भी सुधार होगा। मैं पूर्ण रूप से आशा करता हूँ और इतना ही नहीं बल्कि आग्रह करता हूँ कि इन तमाम राहतों के परिणामस्वरूप कीमतों में कमी आ जानी चाहिए।

157. इस अवसर पर मैं सभी उद्योगों के विनिर्माताओं (प्रबंधकों) से, जिनको मैंने उत्पाद-शुल्कों में रियायतें दी हैं, अनुरोध करना चाहूंगा कि वे भी उत्पाद शुल्क की इन समग्र राहतों का फायदा कीमतों में कमी करके उपभोक्ताओं तक पहुंचाएं। प्रशासनिक मंत्रालयों से भी इन वस्तुओं की कीमतों की प्रवृत्तियों पर कड़ी नजर रखने का अनुरोध किया जा रहा है। जहां कहीं भी इस बात का प्रमाण मिलेगा कि विनिर्माता उद्योग इन रियायतों का अनुचित लाभ उठा रहे हैं, वहां मैं इन रियायतों को वापस लेने में संकोच नहीं करूंगा।

इलेक्ट्रानिकी

158. इलेक्ट्रानिकी उद्योग के समग्र उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ समय से हम राजकोषीय उपायों को उपयोग में ला रहे हैं। सरकार की नीति के परिणामस्वरूप इस क्षेत्र में उल्लेखनीय विकास हुआ है और लाखों नौजवानों और महिलाओं को रोजगार मिला है। इस समय इलेक्ट्रानिकी उद्योग की मशीनरी की विनिर्दिष्ट मदों के संबंध में सीमा-शुल्क की 60 प्रतिशत अथवा 70 प्रतिशत मूलानुसार रियायती दरें लागू हैं। इन रियायतों की समीक्षा की गयी है। इस उद्योग को बढ़ावा देने के विचार से और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में होने वाली अद्यतन प्रगति को ध्यान में रखते हुए मैं इलेक्ट्रानिकी क्षेत्र के लिए मशीनरी की 280 मदों के संबंध में 60 प्रतिशत मूलानुसार के हिसाब से रियायती शुल्क की एक समान दर को ही लागू करने का प्रस्ताव करता हूँ।

159. इलेक्ट्रानिकी उद्योग में काम आने वाले मोल्डों, औजारों और सांचों के सीमा-शुल्क को 60 प्रतिशत से घटाकर 30 प्रतिशत मूलानुसार किया जा रहा है। इस उद्योग के

लिए उपयोगी कच्चे माल, अलग-अलग हिस्सों और संघटकों पर लगने वाले वर्गानुसार शुल्कों की व्याप्ति के क्षेत्र को भी बढ़ाया जा रहा है। अब पोलिकिस्टेलाइन सिलिकोन पर भी 80 प्रतिशत की मौजूदा दर के बजाय 35 प्रतिशत के हिसाब से कम शुल्क लगाया जायेगा।

160. स्वदेशी प्रौद्योगिकी के आधार पर संस्थापित ग्रामीण स्वचालन एक्सचेंजों के विनिर्माण में काम आने वाली मशीनरी और उपकरणों पर भी पहले से कम अर्थात् 30 प्रतिशत की दर से शुल्क लगेगा। दूरसंचार पारेषण, उपग्रह, संचार, स्विचिंग, तथांक (डाटा) संचारण केन्द्रों, दूरदर्शन पारेषण, स्टूडियो और ध्वनि प्रसारण क्षेत्रों में काम आने वाले बहुत से उपस्करों के संबंध में 100 प्रतिशत शुल्क की एक समान दर निर्धारित की जा रही है। इन उपस्करों के गैर-इलेक्ट्रानिकी संघटकों पर कम दर से, अर्थात् 80 प्रतिशत की दर से शुल्क लगेगा। उच्च प्रौद्योगिकी के उपयोग से तैयार होने वाली मदों, जैसे कि बड़े पैमाने के एकीकृत सर्किटों, माइक्रोप्रोसेसरों और अन्य माइक्रो-इलेक्ट्रानिकी मदों के उत्पादन को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से मशीनरी की 22 मदों के आयात पर 15 प्रतिशत मूल्यानुसार की दर पर शुल्क लगेगा।

161. इस समय कम्प्यूटरों, कम्प्यूटर सिस्टमों और पेरिफरलों पर अलग-अलग दरों से अर्थात् शून्य से 147.5 प्रतिशत तक की दरों से शुल्क लगाया जाता है। इस व्यवस्था को युक्तिसंगत बनाने के उद्देश्य से समस्त कम्प्यूटरों, कम्प्यूटर सिस्टमों, कम्प्यूटर पेरिफरल और उनके अतिरिक्त पुर्जों के लिए शुल्क की एक समान दर अर्थात् 80 प्रतिशत मूल्यानुसार निर्धारित की जा रही है, जिसमें प्रतिसंतुलनकारी शुल्क भी जोड़ दिया जायेगा। साफ्टवेयर पर सीमाशुल्क की विद्यमान दर, अर्थात् 60 प्रतिशत मूल्यानुसार की दर से शुल्क लगता रहेगा। प्रोत्साहन के उपाय के रूप में कम्प्यूटर साफ्टवेयर निर्यात संबंधी नीति के अंतर्गत, आयात किए जाने वाले संबद्ध कम्प्यूटर साफ्टवेयर और धारक फालतू पुर्जों की सहायता से साफ्टवेयर का विकास करने और व्यवस्थापन करने के संबंध में शुल्क की वही दर लागू होती जो हार्डवेयर के संबंध में लागू हैं। इस समय कम्प्यूटरीकृत अंक नियंत्रित सिस्टमों और उनके हिस्सों पर 80 प्रतिशत की दर से सीमाशुल्क लगाया जाता है। इसको घटाकर 55 प्रतिशत मूल्यानुसार किया जा रहा है। कम्प्यूटरीकृत अंक नियंत्रित सिस्टमों पर उत्पाद-शुल्क को कम करके 5 प्रतिशत मूल्यानुसार किया जा रहा है।

162. 36 सेंटीमीटर से बड़े आकार के स्क्रीन वाले रंगीन टी० वी० सेटों पर, जिनका कर-निर्धारण योग्य मूल्य 5,000 रुपए प्रति सेट से अधिक हो, अब 1750 रुपए की बजाए 2,000 रुपए का उत्पाद-शुल्क लगेगा। किन्तु 5000 रुपए से अनधिक मूल्य के ऐसे ही सेटों पर 1500 रुपए प्रति सेट के हिसाब से अर्थात् जिस हिसाब से अब शुल्क लगाया

जाता है, उसी हिसाब से शुल्क लगाया जाता रहेगा। श्रृंखला-चुम्बकीय टेपों पर उत्पाद-शुल्क की दर को बढ़ाकर 4 रुपए प्रति वर्गमीटर किया जा रहा है। ब्लैक आडिओ कैसटों को शुल्क से मुक्त किया जा रहा है। कम्प्यूटर साफ्टवेयर पर लगने वाले उत्पाद-शुल्क को 25 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत मूल्यानुसार किया जा रहा है।

163. कतिपय अन्य उद्योगों को भी अग्रेतर विकास के लिए प्रोत्साहनों की आवश्यकता है। मेरे प्रस्ताव अब ऐसे कई एक उद्योगों से संबंधित हैं।

प्लास्टिक

164. सदन को स्मरण होगा कि प्लास्टिक की विभिन्न सामग्रियों, जैसे एल० डी० पी० ई०, एच० डी० पी० ई०, पी० वी० सी०, और पोली-प्रोपिलीन, पर सीमा-शुल्कों में सितम्बर, 1987 में कमी की गई थी जबकि इन सामग्रियों के अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में भारी वृद्धि हो गई थी। उसके बाद से इनके अंतर्राष्ट्रीय मूल्य और भी ऊंचे हो गए हैं और अब सीमा शुल्कों में और ज्यादा कमी करने की आवश्यकता है। इसलिए मैं प्रस्ताव करता हूं कि एल० डी० पी० ई० पर बुनियादी सीमा-शुल्क को 3,000 रुपए मीट्रिक टन से घटाकर 2,000 रुपए प्रति मीट्रिक टन और एच० डी० पी० ई० पर 30 प्रतिशत से घटाकर 20 प्रतिशत मूल्यानुसार कर दिया जाए।

165. पी० वी० सी० पर लगने वाले सहायक सीमा शुल्क को मूल्यानुसार दरों से मात्रानुसार दरों में परिवर्तित करने का प्रस्ताव है और इस शुल्क को सर्पेशन वर्ग के पी० वी० सी० के मामले में घटाकर 2,000 रुपए प्रति मीट्रिक टन और पेस्ट वर्ग के मामले में घटाकर 4,000 रुपए प्रति मीट्रिक टन किया जा रहा है। पोलीप्रोपिलीन के मामले में सहायक शुल्क को 45 प्रतिशत से घटाकर 30 प्रतिशत मूल्यानुसार किया जा रहा है।

आटोमोटिव क्षेत्र

166. जहां तक आटोमोटिव क्षेत्र का संबंध है, मैं आटो सहायक उपकरण उद्योग द्वारा कुछ अतिरिक्त संघटकों के विनिर्माण के काम में लाए जाने वाले ऐसे हिस्सों के संबंध में जिनको ईंधन की कम खपत से चलने वाली मोटरगाड़ियों को सप्लाई किया जाता है 55 प्रतिशत की रियायती दर पर सीमाशुल्क जारी रखने का प्रस्ताव करता हूं। कम ईंधन की खपत करने वाली दुपहिया गाड़ियों और हल्की वाणिज्यिक गाड़ियों के अतिरिक्त संघटकों तथा विनिर्दिष्ट संघटकों के हिस्सों पर अब 55 प्रतिशत मूल्यानुसार की वर्तमान दर के मुकाबले कम दर के हिसाब से, अर्थात् 40 प्रतिशत मूल्यानुसार की दर से सीमा-शुल्क लगेगा। विभिन्न चरणों में बनने वाली 1000 सी० सी० तक की ईंधन की कम खपत करने वाली कारों के विनिर्माण के काम में आने वाले संघटकों के संबंध में 55 प्रतिशत मूल्यानुसार की रियायती दर पर

लगने वाला सीमा-शुल्क 1-3-1988 से 31-3-1990 तक की अग्रेतर अवधि तक जारी रखा जायेगा। तथापि, अनु-मोदित चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम के अन्तर्गत विनिर्मित 1000 सी० सी० से अधिक क्षमता के इंजन वाली और ईंधन की कम खपत करने वाली मोटर-कारों पर 25 प्रतिशत की मौजूदा दर के स्थान पर अब 30 प्रतिशत मूल्यानुसार की दर पर उत्पाद-शुल्क लगेगा।

167. मैं ऐसी तिपहिया आटोरिक्षाओं के ढांचों के संबंध में, जिन्हें बड़े-बड़े शहरों में आम जनता इस्तेमाल करती है, उत्पाद-शुल्क को प्रति ढांचे के हिसाब से 1000 रु० से घटाकर 500 रुपए प्रति ढांचा करने का प्रस्ताव करता हूँ।
वनस्पति तेल

168. वनस्पति तेलों के आयात की मात्रा को कम करने के लिए सरकार ने पूर्ववर्ती वर्षों में कुछ राजकोषीय उपाय इस उद्देश्य को सामने रख कर किए हैं कि खाद्य तेलों के स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा मिले। इन उपायों के परिणाम उत्साहवर्द्धक रहे हैं। पिछले दो वर्षों में किए गए उपायों की अनुवर्ती कार्रवाई के तौर पर मैं शोधित कुसुम्ब तेल (सफ़फलावर आयल) को उत्पाद-शुल्क से पूरी छूट देने का प्रस्ताव करता हूँ। वनस्पति के निर्माण के लिए काम में लाए जाने वाले विनौलों के विलायक निस्सारित तैलों के इस्तेमाल पर छूट की राशि को 3250 रुपए प्रति मीट्रिक टन से बढ़ाकर 4,000 रुपए प्रति मीट्रिक टन किया जा रहा है। वनस्पति के निर्माण के लिए ताड़ के स्वदेशी तेल के इस्तेमाल पर 3250 रुपए प्रति मीट्रिक टन की दर से छूट देने की व्यवस्था की जा रही है। अब विलायक निस्सारित सूरजमुखी के तेल और कुसुम्ब के तेलों पर, उनको वनस्पति के निर्माण के काम में इस्तेमाल किए जाने पर 3250 रुपए प्रति मीट्रिक टन की दर से छूट दी जाएगी। मैं साबुनों के निर्माण में चावल की भूसी के तेल के इस्तेमाल पर 320 रुपए प्रति मीट्रिक टन के हिसाब से दी जाने वाली छूट की दर को बढ़ाकर 640 रुपए प्रति मीट्रिक टन करने का प्रस्ताव भी कर रहा हूँ।

कागज और गत्ता

169. मैं कागज के छोटे कारखानों द्वारा विनिर्मित कागज और गत्ते के उत्पाद-शुल्क में प्रत्येक विद्यमान खण्ड के अन्तर्गत 100 रुपया प्रति मीट्रिक टन की कमी करने का प्रस्ताव करता हूँ। अनाज के भूसे, गन्ने के छिलके, घास-फूस और जूट के अपशिष्ट पदार्थ आदि जैसी कृषि अपशिष्ट सामग्रियों के इस्तेमाल से मिलीं द्वारा कागज और गत्ते का विनिर्माण करने पर इस समय भी 10 प्रतिशत मूल्यानुसार की अपेक्षाकृत कम दर के हिसाब से उत्पाद-शुल्क लगाया जाता है, जिसमें प्रति मीट्रिक टन के हिसाब से 800 रुपया और जोड़ दिया जाता है। मैं इस शुल्क को और कम करके 300 रुपया प्रति मीट्रिक टन करने का प्रस्ताव करता हूँ। कुछ एक कागज के नए कारखानों को उत्पाद-शुल्क में 50 प्रतिशत की 31-3-1988 तक उपलब्ध रियायत को अब 31-3-1990 तक बढ़ाया जा रहा है।

170. अखबारी कागज के विनिर्माण के लिए मशीनरी की विनिर्दिष्ट मदों के संबंध में 25 प्रतिशत मूल्यानुसार की रियायती दर पर सीमा-शुल्क लगाए जाने की व्यवस्था की जा रही है।

171. मैं पंजीकृत अखबारी प्रतिष्ठानों द्वारा जिल्द बांधने की मशीनरी और बहुरंजक शीटफेड आफसेट प्रिंटिंग मशीनों के आयात के संबंध में भी सीमाशुल्क की रियायती दरों की व्यवस्था करने का प्रस्ताव करता हूँ।

रोलिंग बेयरिंग उद्योग

172. रोलिंग बेयरिंग उद्योग की मशीनरी की 21 मदों के संबंध में 35 प्रतिशत मूल्यानुसार की रियायती दर पर सीमा-शुल्क लगाए जाने की व्यवस्था की जा रही है।

घड़ियां

173. घड़ियों का विनिर्माण करने वाले स्वदेशी उद्योग की ओर प्रोत्साहन प्रदान करने की दृष्टि से मैं घड़ीसाजी के काम में आने वाली कुछ मशीनों और परीक्षण के उपकरणों के संबंध में सीमाशुल्क दर को 55 प्रतिशत मूल्यानुसार से घटाकर 35 प्रतिशत मूल्यानुसार करने का इरादा रखता हूँ। घड़ीसाजी के काम में आने वाले कच्चे सामान की सूची को, जिस पर 25 प्रतिशत मूल्यानुसार की रियायती दर पर सीमा-शुल्क लगाया जाता है और ज्यादा बढ़ाया जा रहा है। इसके अलावा, मरे विस्तृत प्रस्तावों के अंतर्गत कतिपय विनिर्दिष्ट हिस्सों के संबंध में भी सामुच्चयिक आधार पर ठोस रियायतों की व्यवस्था की गई है।

कांच और कांच की वस्तुएं

174. मैं अर्द्ध-स्वचल क्षेत्र द्वारा विनिर्मित कांच और कांच की वस्तुओं के संबंध में 30 प्रतिशत मूल्यानुसार की रियायती दर पर उत्पाद-शुल्क को फिर से लगाने का प्रस्ताव भी करता हूँ।

ऊर्जा संरक्षण

175. हमारी औद्योगिक प्रणालियों के क्षेत्र में, हम में से बहुत से लोग ऊर्जा के संरक्षण और ऊर्जा के पुनरावर्ती उपयोग के महत्व के प्रति दिलचस्पी नहीं लेते हैं। ऊर्जा के संरक्षण की संकल्पना अभी इस देश में प्रारम्भिक अवस्था में है और हमें इस दिशा में अग्रसर होने के लिए कतिपय प्रोत्साहनों की व्यवस्था करनी होगी। तदनुसार, ऊर्जा संरक्षण करने वाले 15 विशिष्ट उपकरणों को 40 प्रतिशत मूल्यानुसार से अधिक दर पर आरोग्य सीमा-शुल्क से छूट दी जा रही है।

होटल

176. देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए होटलों की जरूरत के कुछ अतिरिक्त उपकरणों पर 90 प्रतिशत की रियायती दर से सीमा-शुल्क लगाए जाने की व्यवस्था की जा रही है।

युक्तिकरण के उपाय

177. अप्रत्यक्ष करों के संबंध में मने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं, उनमें उपायों को युक्तिसंगत बनाने के कतिपय उपाय भी सम्मिलित हैं :—

(क) उद्योग ने मोडवाट प्रणाली को लाभकारी पाया है। प्रारम्भिक चरण में पेश आई प्रक्रिया सम्बन्धी समस्याओं को लगभग हल कर लिया गया है। कुछ एक वस्तुओं के संबंध में, जिनमें सिथेटिक पोलीमर्स पर आधारित रंग-रोगन, ट्रेलर्स, फर्नीचर, फथेलिक एनहीड्राइड और कवचित वस्त्र शामिल हैं, उत्पाद-शुल्क की दरों को युक्तिसंगत बनाने का भी मेरा प्रस्ताव है।

(ख) वातानुकूलन और प्रशीतन उपकरणों तथा उनके हिस्सों से संबंधित लघु उद्योगों को उपलब्ध उत्पाद-शुल्क की दरियायतों की योजना में भी कुछ साधारण सा परिवर्तन किया जा रहा है ताकि 'मोडवाट' क्रेडिट का पूरा-पूरा उपयोग किया जा सके।

(ग) मैं लौह धातुओं और अलौह धातुओं तथा उनसे बनी वस्तुओं से संबंधित उत्पाद-शुल्क टैरिफ की संगति तत्संबन्धी एकीकृत प्रणाली के तदनुरूप अध्यायों में विहित व्यवस्था से स्थापित करने का प्रस्ताव करता हूँ जिससे वर्गीकरण संबंधी विवादों को कम करने में सहायता मिलेगी। लोहे और इस्पात तथा तांबे से संबंधित मदों के बारे में उत्पाद-शुल्क की टैरिफ दरों को संशोधित किया जा रहा है। विद्युत उत्पाद-शुल्क की प्रभावी दरें कमोवेश ज्यों की त्यों रखी जाएंगी। इस्पात की बिना मशीन की गढ़ाई, और गढ़ाई के बाद तैयार उत्पादों के संबंध में 550 रुपये प्रति मीट्रिक टन की दर से एक सारान आधार पर उत्पाद-शुल्क लगाया जा रहा है। विखंडित किए जाने के लिए आयातित जहाजों, समुद्री नौकाओं और अन्य प्लवमान निर्मितियों (फ्लोटिंग स्ट्रक्चर्स) के बुनियादी सीमा-शुल्कों को 1035 रुपये से घटाकर 750 रुपये प्रति एल०डी०टी० किया जा रहा है।

(घ) पेट्रोलियम उत्पादों के संबंध में उत्पाद-शुल्क की दरों को युक्तिसंगत बनाने और पूर्णकृत करने के लिए कुछ एक प्रस्ताव किए जा रहे हैं। इन प्रस्तावों से उल्लेखनीय रूप में कोई अधिक राजस्व का उपार्जन नहीं होगा।

(ङ) लघु उद्योग में ट्रीड रबड़ के विनिर्माताओं को उत्पाद-शुल्क में दरियायत प्राप्त करने की जो योजना उपलब्ध है उसे कर-अपवंचनरोधी उपाय के रूप में संशोधित किया जा रहा है।

(च) कर-अपवंचन की रोकथाम करने के लिए मैं पेय पदार्थों के विनिर्माण के लिए उपयोगी कतिपय मिश्रित अल्कोहल द्रव्यों के संबंध में बुनियादी सीमा-शुल्क की दर को बढ़ाकर 80 रुपये प्रति लीटर अथवा 270 प्रतिशत, जो भी ज्यादा हो, करने का प्रस्ताव करता हूँ।

(छ) गैल्वनीकृत इस्पाती चादरों, टिन प्लेटों और शीत पद्धति से बेलित इस्पाती चादरों के आयात के संबंध में कम राशि के बीजक बनाए जाने की कुछ रिपोर्टें मिली हैं। इस समस्या का समाधान करने के लिए उन वस्तुओं पर लगाए जाने वाले सीमा-शुल्क की दरों को मूल्यानुसार एवं मात्रा-नुसार शुल्क-दरों के स्थान पर मात्रानुसार दरों में परिवर्तित किया जा रहा है।

(ज) 7.5 मीट्रिक टन क्षमता तक के वातानुकूलन यंत्रों के संबंध में उत्पाद-शुल्क की मात्रानुसार दरों में भी संशोधन किया जा रहा है। 7.5 मीट्रिक टन से अधिक के वातानुकूलन यंत्रों के संबंध में भी, जो 15 मीट्रिक टन से ज्यादा क्षमता के नहीं हैं, मात्रानुसार दरों को निर्धारित किया जा रहा है।

(झ) कर-अपवंचन की रोकथाम करने के उपाय के रूप में पेस्ट वर्ग के पी० बी० सी० पर उत्पाद-शुल्क को 40 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत मूल्यानुसार किए जाने का प्रस्ताव है। रेजिन के संबंध में दिया जाने वाला शुल्क 'मोडवाट' क्रेडिट के रूप में उपलब्ध हो जाएगा। कवचित वस्तुओं पर शुल्क की प्रभावी दरों में भी उपयुक्त रूप से संशोधन किए जा रहे हैं।

(ञ) स्वदेशी उद्योग को प्रोत्साहन प्रदान करने के प्रयोजन से मैं सोडियम फारमेलिडहाइड, सल्फोक्सीलेट के संबंध में बुनियादी सीमा-शुल्क को 70 प्रतिशत से बढ़ाकर 110 प्रतिशत और सोडियम फेरा-सिनामाइड के संबंध में 70 प्रतिशत से बढ़ाकर 100 प्रतिशत और लोहे के चूरे के संबंध में 40 प्रतिशत से बढ़ाकर 70 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूँ। पाम नट और गिरी के बुनियादी सीमा-शुल्क को 60 प्रतिशत से बढ़ाकर 200 प्रतिशत मूल्यानुसार किए जाने का भी प्रस्ताव है।

बैधानिक परिवर्तन और साधारण महत्व के अन्य परिवर्तन

178. उपर्युक्त प्रस्तावों के अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क और सीमा-शुल्क टैरिफ में परिवर्तन करने के प्रयोजन से वित्त विधेयक में कतिपय संशोधन करने का प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया गया है। ये संशोधन बुनियादी तौर पर समर्थकारी कानूनी उपबंध हैं, जिनका राजस्व उपार्जन करने के लिए कोई अधिक महत्व नहीं है। इसके अलावा, मौजूदा अधिसूचनाओं को, जिनमें एक संशोधनकर्ता अधिसूचना की भूलक्षी

प्रभाव से प्रवृत्त करने वाली अधिसूचना भी शामिल है, बरकरार रखने, संशोधित या निरसित करने के लिए भी कुछ साधारण किस्म के प्रस्ताव किए गए हैं। मैं इस सम्मानित सभा का मूल्यवान समय बचाने के लिए इनके संबंध में ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। मैं सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 के कुछ उपबंधों में संशोधन करने की व्यवस्था भी कर रहा हूँ, जिसका ब्यौरा वित्त विधेयक में दिया गया है। केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 में भी कुछ संशोधन किए जाने का प्रस्ताव है ताकि विशेष महत्व की कतिपय वस्तुओं की परिभाषाओं में केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 के संदर्भ में तालमेल बिठाया जा सके।

179. पहली मार्च, 1988 से प्रवृत्त होने वाले सीमा-शुल्कों और उत्पाद-शुल्कों में परिवर्तन करने के उद्देश्य से जारी की जाने वाली अधिसूचनाओं की प्रतियाँ उचित समय में सभा पटल पर रख दी जाएगी।

तस्करी-विरोधी अभियान

180. वर्ष 1987 में तस्करी विरोधी प्रयासों के फल-स्वरूप 250 करोड़ रुपए मूल्य की निषिद्ध वस्तुओं को जब्त किया गया, जो कि अब तक की सबसे बड़ी जब्ती है। मैंने अपने अधिकारियों को तस्करी, कर-अपवंचन और काले धन के विरुद्ध अभियान को और तेज करने के अनुरोध दे दिए हैं। मैं राज्य सरकारों से सक्रिय सहयोग प्राप्त करने के लिए भी अनुरोध करूँगा क्योंकि राज्य सरकारों की सहायता से ही हम इस बड़े काम में सफल हो सकते हैं। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूरा-पूरा विश्वास है कि राज्य सरकारें भी जक्षाखोरी, कालाबाजारी, तस्करी और चोरी-छिपे लाई गई वस्तुओं की बिक्री की रोकथाम करने के लिए सक्रिय कदम उठाएंगी।

राजस्व प्रभाव

181. मेरे प्रस्तावों में शामिल अलग अलग मदों के सम्बन्ध में होने वाली वृद्धि और कमी का ब्यौरा वित्त विधेयक के व्याख्यात्मक ज्ञापन में दिया गया है। कुल मिला कर, सीमा-शुल्कों और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्कों के सम्बन्ध में मेरे प्रस्तावों के परिणामस्वरूप सीमा-शुल्कों से 515.75 करोड़ रुपए और उत्पाद-शुल्कों से 749.17 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होने की संभावना है। सीमा-शुल्कों के अन्तर्गत कुल मिला कर 209.44 करोड़ और उत्पाद-शुल्कों के अन्तर्गत 509.79 करोड़ रुपए की रियायतें और राहतें प्रदान की गई हैं। इस प्रकार, सीमा-शुल्कों से 306.31 करोड़ रुपए और उत्पाद-शुल्कों से 239.38 करोड़ रुपए का निवल अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा। उत्पाद-शुल्कों में केन्द्र का हिस्सा 117.23 करोड़ रुपए और राज्यों का हिस्सा 122.15 करोड़ रुपए का होगा। 545.69 करोड़ रुपए की कुल निवल अतिरिक्त प्राप्ति में केन्द्र का हिस्सा 423.54 करोड़ रुपए और राज्यों का हिस्सा 122.15 करोड़ रुपए का होगा।

182. प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में प्रस्तावित परिवर्तनों तथा कुछ ही दिन पहले डाक दरों में की गई वृद्धियों से होने वाली अतिरिक्त आमदनी को हिसाब में लेने के बाद अगले वर्ष के अन्त में 7,484 करोड़ रुपए का घाटा रहने का अनुमान है। सरकार व्यय पर कड़ी निगरानी रखने, राजस्व का अधिक से अधिक संग्रह करने और बजटीय घाटे को बढ़ने से रोकने के अपने इरादे को फिर दोहराती है।

183. अध्यक्ष महोदय, बजट प्रस्तावों को तैयार करते समय अधिक रोजगार के सृजन, कृषि को प्रोत्साहन, गरीब वर्ग की सहायता और पूँजी निवेश और विकास की आवश्यकता मेरे मार्गदर्शी सिद्धान्त रहे हैं। भारत ने स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद जो सफलताएँ प्राप्त की हैं, वे हमारे प्यारे देश की सारी जनता के अथक परिश्रम का परिणाम है। इनके लिए देश का अकेला कोई एक भाग, एक प्रदेश या अंचल अथवा कोई अकेला वर्ग समूचा श्रेय नहीं ले सकता। हमारी जनता के प्रत्येक वर्ग ने अर्थव्यवस्था के निर्माण में योगदान किया है। हमारे लोकतंत्र के सर्वोच्च मंच के रूप में राष्ट्र की संसद ने भी अमूल्य अंशदान दिया है। अपनी पूर्ण विनम्रता के साथ आपके माध्यम से मैं इस अवसर पर संसद के सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करूँगा कि वे कृपया सर्वमान्य लक्ष्यों को प्राप्त करने की एक राष्ट्र-सम्मत कार्यनीति विकसित करने के लिए बजट पर होने वाले इस वर्ष के वाद-विवाद को एक रचनात्मक और सहभागितापूर्ण प्रयास का रूप दें।

184. तो, आइए, हम सब इकट्ठे मिलकर जो कुछ कर पाए हैं, उस पर गर्व करें और जो कोई कमियाँ या त्रुटियाँ रह गई हैं तो उन्हें हम मिल कर दूर भी करें। आइए, हम सब मिल कर भारत के आर्थिक विकास के प्रेरणादायक अभियान में भाग लें और इस लक्ष्य को समस्त भारतीय जनता की सामूहिक भ्रातृत्वपूर्ण साझेदारी का रूप दे कर पूरा करें। जैसा कि हमारे प्रधान मंत्री, श्री राजीव गांधी, ने कुछ महीने पहले कहा था:

“हमारा समाजवाद हमारा अपना ही है। यह कोई विदेशी प्रत्यारोपण (या थोपन) नहीं है। यह किसी अन्य विचारधारा के साँचे में ढला हुआ नहीं है। इसकी जड़ें हमारे अपने इतिहास, हमारी संस्कृति, हमारी अपनी वास्तविकताओं में हैं। गांधी जी ने हमसे दरिद्र नारायण की सेवा करने और प्रत्येक व्यक्ति की आँखों से अश्रुओं को पोंछने का आह्वान किया था। हमारे समाजवाद का यही नैतिक दायित्व है।”

185. इस बजट द्वारा यही यत्किंचित् संदेश देने का विनम्र प्रयास किया गया है। महोदय, मैं अब यह बजट सदन को समर्पित करता हूँ।

के०एस० शास्त्री, अपर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st March, 1988

No. 15(35)-B(D)/87.--The following is published for general information of the public :—

BUDGET 1988-89

Speech of

SHRI NARAYAN DATT TIWARI

Minister of Finance

29th February, 1988

PART A

Sir,

I rise to present the Budget for the year 1988-89.

2. The Economic Survey for 1987-88 was placed before the House a few days and contains a detailed review of trends in the Indian economy over the past year. Economic performance and management during the year have been dominated by natural calamities of drought and floods. The drought this year has been one of the worst in this century, with 21 out of 35 meteorological sub-divisions receiving deficient or scanty rainfall during the monsoon months. In most of the Eastern states the problem was not too little but, rather, too much rainfall, leading to devastating floods. What is worse, this year of drought and floods followed three successive years of poor monsoon.

3. Despite the very severe strains and distress, the economy has demonstrated remarkable resilience. It has done so far too good reasons. First, sustained development and diversification of our economy, over the years, has created a capacity to withstand temporary shocks. Second, Government has responded with timely interventions across a wide front to contain the economic and social costs of the drought.

4. The buffer stock policy pursued by the Government enabled us to build large food stocks, which stood at 23 million tonnes on 1st July, 1987. With the help of these stocks, a massive and sustained effort was launched to ensure adequate supply of foodgrains throughout the country, particularly in drought affected areas. Other important Government programmes to combat the drought included massive expansion of relief and employment generating works, strengthening of the public distribution system, special efforts to compensate for shortages of drinking water, fodder and power supply, action plans to grow contingency crops in the kharif season and to boost rabi production, measures for livestock protection and large scale imports of essential commodities such as edible oils and pulses. These supply measures were buttressed by careful fiscal and monetary policies to make available adequate resources for relief expenditures, without cutting back on the public investment programme.

5. Thanks to these sustained efforts the overall indicators of economic performance have been better than in any previous year of severe drought. Thus, despite the decline in agricultural production, GNP growth in 1987-88 is expected to be in the range of 1 to 2 per cent, in contrast to a decline of 4.7 per cent in 1979-80. Available data show that industrial production in April--November 1987 rose by 10.2 per cent over the corresponding period of the previous year. In contrast, in the drought year 1979-80, there was an absolute decline of 1.7% in industrial production. The overall rate of inflation in the current financial year, as measured by the Wholesale Price Index, stood at 9.8 per cent as on February 6, 1988 as compared with inflation in excess of 21 per cent recorded in 1979-80. Price movements in respect of essential commodities are being monitored closely at Central and State levels and I would like to thank State Governments for setting up control rooms at the district level also. We have to keep continuous vigilance on the price front at all levels, so that inflation is kept under control.

6. The strains imposed by the drought and floods have highlighted some of the underlying strengths as well as problem areas of our economy. In the face of successive monsoon failures, our agriculture has demonstrated its basic strength. We are proud of our farmers. By their hard work and unflinching determination through the years, they produced enough to enable us to build substantial food stocks. This helped us to withstand the impact of the current drought without acute food scarcity and widespread economic dislocation.

7. Industrial production will show an increase of more than 8 per cent for four successive years since 1984-85. The infrastructure has performed well. Generation of thermal power has made up the deficiency in generation of hydel power and, overall, there was a growth of 7.6 per cent in power generation in the first nine months of the current year. Productivity in the Railways has shown significant improvement. Coal production has increased by 10.2 per cent in April-December, 1987. The improvement shown by the public sector in these areas is a matter of considerable satisfaction, and bears testimony to the successful implementation of policies initiated by this Government. Our workers have worked hard to make this possible, and the nation is grateful to them. Government attaches the highest importance to building a strong and vibrant public sector.

8. Exports have recorded strong growth over the last two years. After growing by over 15 per cent in 1986-87, exports rose by nearly 25 per cent in the first nine months of the current year as compared to the corresponding period of the previous year. Over the same period, the growth of imports was less than 14 per cent. The trade deficit has been declining over the past two years.

9. However, we must not be complacent. As we look ahead, we must move, decisively to overcome some of the problems that have emerged on the economic scene. The four successive years of poor monsoons have caused considerable hardships in our

rural areas, reduced agricultural output, and affected the momentum of growth. We, therefore, have to give a major thrust to agriculture in the remaining years of the Seventh Plan.

10. We have done well in agriculture. But the drought and floods have highlighted certain areas which require our urgent attention. The Prime Minister has directed that an Action Plan should be formulated quickly by the Planning Commission, which would identify the areas where further measures can lead to early gains in production. In 1987-88, an additional allocation of Rs. 236 crores has been made for completion of irrigation projects in drought affected States. In the coming year, Plan outlays for Centre in respect of agriculture and irrigation are being increased by 40 per cent. If necessary, the Government will make re-allocations within the overall Plan outlay for 1988-89 and provide more resources for achieving agricultural targets.

11. We have seen rapid growth in industry, reflecting the success of Government policies in stimulating investment and production, and promoting technological upgradation. We must ensure that this momentum is maintained. Costs and prices need to be reduced. Indian Industry must be made more competitive. Sickness in industry has been a major problem. We have to take further steps to combat sickness. We must also upgrade skills, train workers and improve management. Industrial development must make the best use of our most abundant resource, namely, the skills of our people. Rapid growth of industry is essential for generating employment opportunities.

12. Small, village and khadi industries have a special place in our economic development. These industries make use of locally available resources and are instrumental in creating job opportunities in smaller towns and rural area where the bulk of our people live. Speaking in this house, thirty five years ago, Pandit Jawahar Lal Nehru had told the nation, and I quote,

"I have no doubt that we cannot raise the people's level of existence without the development of major industries in this country; in fact, I will go further and say that we cannot even remain a free country without them. But we must always remember that the development of heavy industry does not by itself solve the problem of the millions in this country. We have to develop the village and cottage industry in a big way, at the same time making sure that in trying to develop industry, big and small, we do not forget the human factor."

This overall approach continues to guide us.

13. Government has been taking several measures to increase revenue, improve tax compliance and enforce economic laws. These have yielded dividends and growth of revenue in the past three years has been quite satisfactory. The faster growth of expenditure has, however, exerted substantial pressures on the fiscal situation. We face unavoidable compulsions of higher expenditure, for example, on defence, development, social services, relief programmes and food

and fertilizer subsidies. As a nation, we must deal earnestly with the problem of mounting expenditure.

14. As anticipated, the balance of payments situation has been under strain because of several factors. These include higher imports of edible oils and pulses, increase in imports of crude oil and petroleum products, increasing protectionist tendencies abroad, and unfavourable climate for official development assistance. The environment for developing countries has also been badly affected by upheavals in the international economy, volatility of exchange rates, and slow growth of world trade. In order to reduce the impact of these unfavourable developments, we took vigorous measures to increase exports and reduce the growth of imports. These measures would need to be further strengthened.

15. India has followed a prudent policy in debt management and has avoided problems of the kind faced by several other developing countries. We remain committed to ensuring long-term viability in our balance of payments.

16. The challenges before us are many and it is only through hard work, thrift and sacrifice that we can build a self-reliant, strong and socialist economy. As a humble political worker, I am, conscious that while we have made tremendous progress, there is a great deal that remains to be done to improve the condition of our people, particularly in rural areas.

17. Within the limitation imposed by our overall resource situation, I propose to take a number of steps to benefit farmers, promote small and village industries provide relief to the poor, protect and create more jobs and generate self employment opportunities for our people. In addition to augmenting the antipoverty programmes, such as IRDP, NREP and RLEGP, Government has decided to initiate a number of measures to increase the flow of agricultural credit, strengthen the institutional framework, enhance social security to the weaker and vulnerable sections of the society, particularly Scheduled Castes and Scheduled Tribes, and promote better housing for the rural poor. While some of these programmes call for additional outlays, it is proposed to redirect and redirect several of the existing programmes and institutions to serve our social objectives better.

18. In working out the package of measures for agriculture, we have kept in view the guidelines given by the Prime Minister when he addressed the kisans the other day :

"कृषि को अगले दो-तीन सालों में प्रोत्साहन दिया जाए, जिसमें छोटे और सीमांत किसानों, भूमिहीन मजदूरों और ग्रामीण दस्तकारों पर खास ध्यान दिया जाए। हमारी यह भी कोशिश हो कि ऐसी जो भी योजना देहात के विकास के लिए बने वह देश के हर हलके के लिए ही नहीं बल्कि देहात में हर तबके के लिए भी बने। इससे पूरे समाज की ताकत बनेगी, पूरे समाज को इसका लाभ मिलेगा और पूरा समाज आगे बढ़ेगा।"

(In the next two-three years we must give a strong thrust to agriculture. Special attention must be given to small and marginal farmers, landless labourers and village artisans. It shall also be our endeavour that our schemes for rural development benefit not only all the regions of the country but also all the sections of the society. This will strengthen and benefit the entire community and help us march forward.)

19. The financial condition of our farming community has been affected by the drought. A number of measures have already been taken such as rescheduling of loans, conversion of short term loans into term loans and lowering of rate of interest in some cases. As an important step forward, I am happy to inform the House that today the Reserve Bank of India is issuing instructions to bring down the cost of agricultural credit. The rate of interest on crop loans upto Rs. 7,500 is being reduced by one and half per cent to two and half per cent. The interest rate will, henceforth, be reduced to 10 per cent for loans upto Rs. 7,500 from the prevailing levels of 11.5 per cent and 12.5 per cent. Similarly, for crop loans above Rs. 7,500 and upto Rs. 15,000, interest rate will be reduced to 11.5 per cent from 12.5 per cent to 14 per cent. This reduction in interest rates will benefit crores of agricultural borrowers from cooperative sector, Regional Rural Banks and commercial banks, and provide much needed relief to them.

20. In order to increase the flow of credit at reduced cost, it has also been decided that the target for direct finance to agriculture by public sector banks should be raised to 17 per cent of their total outstanding advances by the end of 1988-89. Together with added efforts by regional rural banks and cooperative banks, the target for availability of direct credit by banks to agriculture will increase by over Rs. 3,000 crores in 1988-89.

21. In order to further reduce the cost of inputs, Government is asking the fertilizer companies, in both public and private sectors, to give a discount of 7.5 per cent over notified prices for coming Kharif and Rabi sowings. This will reduce the price of a bag of urea by around eight rupees and eighty paise. The companies should be able to absorb the cost of this discount through better inventory management. I am sure our enterprising farmers will take advantage of this discount and increase agricultural production.

22. Timely use of pesticides and weedicides has an important role in preventing crop damage and improving productivity on our farms. In order to lower their cost, I will be announcing later in my speech, reduction in import duties on selected pesticides/weedicides as well as intermediates. At the same time, selected pesticide items, considered important for agriculture, will be allowed to be imported freely by designated state and cooperative agencies. This will ensure that the existing manufacturers do not indulge in monopolistic practices. This measure will help our farmers.

23. In consultation with the Reserve Bank of India, NABARD, the State Bank of India and the

Commercial banks, I am happy to announce a new strategy on rural credit designed to serve every village of the country. The commercial banks and the Regional Rural Banks together have over 40,000 branches in the rural and semi urban areas of the country. The number of villages exceeds five lakhs and seventy six thousand. Under the proposed dispensation, each bank branch in the country will have a designated service area of about 15 to 25 villages, as required, in the neighbourhood of the branch. The branch will be primarily responsible for meeting the appropriate credit needs of its service area. This country-wide arrangement, supervised by the District Lead Bank Scheme already operational, and further supplemented by the rural cooperatives, will go a long way to serve the credit needs of the village community.

24. To help farmers affected by drought, we have given a number of reliefs and concessions by way of rescheduling of loans, postponement of all recoveries, and reduction in interest rates. It has been a long standing demand of farmers and the cooperative movement that a separate National Agricultural Credit Relief Fund should be established to provide relief on a systematic basis. I am happy to announce that it has now been decided to set up such a Fund. The corpus of the Fund will be provided by the Central and State Governments on an agreed basis. The criteria for releasing money from the Fund will be worked out by the Reserve Bank of India.

25. Before I turn to other matters, I would like to refer to a subject which has been close to our hearts. I have a feeling that the cooperative credit system, which played such a pioneering role in the early years of our Independence, has not grown as fast as it could have. Cooperatives are the best instruments for reaching our farmers; they are also a symbol of self-reliance at the village level. I believe that we must now devote special attention to revitalising the entire cooperative sector. I would invite the Hon'ble Members to give this matter their personal attention and also request them to send me suggestions regarding the role that the Reserve Bank of India, NABARD and the nationalised banking sector, should play in promoting the growth of the co-operative movement. I shall also be writing to State Governments, who have a major responsibility in this area.

26. The programme of rural electrification has enabled countrywide utilisation of ground water for irrigation with the help of electric pump sets. However, some of the poorer farmers have often been unable to afford the one time cost of pump set installation. A special programme to be called JALDHARA will be launched to assist marginal farmers in drought prone areas. The scheme will provide them the benefits of pump sets for irrigation on nominal rental/lease charges. It is proposed that during 1988-89 the benefits of this scheme will be provided to about fifty thousand farming families.

27. To improve the quality of life of rural families below the poverty line, including Harijan and Adivasi families, I propose a massive programme to be called KUTIRJYOTI for extending single point light

connections to households of their families. The programme will meet the one time cost of internal wiring and service connection charges. In 1988-89, five lakh households are proposed to be covered by this programme. The cost of both the JALDHARA and KUTIRJYOTI will be met through a combination of grants and loans to the State Electricity Boards by the Rural Electrification Corporation.

28. People living in hill areas have to bear the burden of higher transport costs in the supply of kerosene and LPG. Today, freight subsidy is given on kerosene to North Eastern States and Jammu & Kashmir. It has now been decided to extend this concession to all hill areas. Similarly, it has been decided that LPG cylinders would be supplied to the customers in all hill areas at the same price as for the customers in the nearest point in the plains. This will also, to a large extent, help in conserving the forest resources used for purposes of light and fuel.

29. In his budget speech last year, the Prime Minister emphasized the high priority of the housing sector and had announced the decision to set up a National Housing Bank with an initial capital of Rs. 100 crores. Necessary legislation has been passed, and the Bank will become operational shortly. In order to give a special thrust to rural housing, the Reserve Bank of India, along with some financial institutions, will make a special additional contribution of Rs. 100 crores to the National Housing Bank. This entire additional amount will be used for promotion of rural housing in several ways, including setting up of specialised rural housing savings and loan institutions, if necessary.

30. In this context, it is also proposed to extend the role of the Land Development Banks to cover the field of housing finance for farmers. These banks exist in most districts, have strong apex bodies and deal directly with the rural population. They can also mobilise resources for housing finance. The State Governments will be requested to carry out necessary legislative measures to permit Land Development Banks to undertake housing finance.

31. A new programme of housing for small and marginal farmers with monthly income of upto Rs. 700, is being launched by Housing and Urban Development Corporation. Under this programme, HUDCO will provide assistance, upto specified amounts, at low rate of 7 per cent interest repayable in 22 years for building or improving a house. Assistance will also be given for improvement of old homes, for example, change of roof from thatch to tile.

32. A new scheme, called the "Village Abadi Environmental Improvement Scheme" will be launched by HUDCO this year. Projects involving expenditure upto Rs. 2,000 per family in villages with population not exceeding 5,000, for improving rural abadi infrastructure like drainage, sanitation etc., will be supported. The equity base of HUDCO will be suitably strengthened to help finance these programmes.

33. Commercial Banks have also been providing help for rural housing, both directly as well as

through HUDCO. With their vast branch network in rural areas, their role should be further enhanced. Hon'ble Members will be happy to know that, it has been decided that commercial banks will increase their lending for the housing sector to an annual level of Rs. 300 crores by the end of the Seventh Plan.

34. There is great scope for using local low-cost materials in housing. Our scientists and engineers have also developed considerable expertise in low-cost housing technology. It has been decided to set up a national network of Nirman or Nirmithi Kendras which will provide easy access to low-cost housing materials and techniques. It is proposed to set up one Kendra in each district. In the coming year, 100 Kendras will be set up.

35. Landless labourers, artisans and other very poor families in rural areas face acute financial distress when their huts and belongings are destroyed by fire. I am glad to inform the House that it is proposed to launch a new scheme to provide fire insurance protection to them. The Government of India will bear the entire premium cost. The scheme will be implemented by the General Insurance Corporation of India and its four subsidiaries. The GIC will separately announce the details of the scheme.

36. I also propose to take a major new initiative for extending the system of social security to the weaker sections of our society. The Life Insurance Corporation of India, which has done so much to spread insurance culture throughout the length and breadth of our country, will be setting up a separate "Social Security Fund" with a corpus of Rs. 100 crores. Certain changes are being made in the Income tax payable by the Life Insurance Corporation of India to make this possible. The Fund will be used for financing life insurance schemes for weaker and vulnerable sections of the population at subsidised rates. The House will agree with me that the creation of such a fund will provide a solid foundation for extending insurance cover to the toiling sections of our society, for example, landless labourers handloom workers, rickshawpullers, drivers etc. who work on daily wages or whose employment is casual. In respect of these group insurance schemes, 50 per cent of the premium will be adjusted from the newly created Social Security Fund, the balance 50 per cent of the premium being payable by the beneficiaries concerned.

37. Group insurance schemes will also be introduced for groups with regular incomes like primary school teachers, cooperative milk producers, and workers in shops and commercial establishments. Schemes will also be formulated for the benefit of artisans, tailors, barbers, masons, carpenters and other similar groups.

38. While IRDP extends benefits to the families of the poor, these families face hardship in the event of sudden death of the head of the family. To give greater security to the family, a group insurance scheme of the LIC is proposed to be introduced to cover around 3 to 4 million families under IRDP assistance every year with effect from 1st April, 1988. The insurance cover will be Rs. 3,000, with double benefit in case of accidental death.

39. I would now like to propose some measures specifically for the benefit of Scheduled Castes and Scheduled Tribes. Many State-level Scheduled Castes and Scheduled Tribes Finance/Development Corporations are doing a good job in looking after the special requirements of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. I now propose setting up a National Scheduled Castes and Scheduled Tribes Finance and Development Corporation. This Corporation will play a catalytic role in developing schemes for employment generation and financing pilot programmes which can then be taken up by the State level Corporations and other agencies active in this field. This Corporation will also work with nationalised banks and NABARD in improving the flow of financial assistance to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. The objective would be to innovate, experiment and promote rather than replicate the work of the existing agencies. I am making a provision of Rs. 50 crores in the next year's budget for this Corporation.

40. Hon'ble Members will be happy to know that we propose to initiate a project for one million wells under the National Rural Employment Programme and Rural Landless Employment Guarantee Programme by raising the percentage of allocation of funds for the exclusive benefit of Scheduled Castes and Scheduled Tribes from 10 per cent to 20 per cent. It is fitting that in the year of Fortieth Anniversary of Independence, we initiate this massive programme of construction of wells which will benefit millions of small and marginal farmers belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

41. I would now like to announce some measures for promotion of employment opportunities in the decentralised sector. The handloom sector provides employment to about 10 million weavers and others. This important sector has been affected by high prices of cotton and other yarns. I propose to increase the subsidy on Janata cloth from Rs. 2 per sq. metre to Rs. 2.75 per sq. metre. The impact of this relief will be Rs. 40 crores. Later, in my speech, I shall be announcing a package of measures which will benefit the handloom sector by reducing the cost of certain types of yarns. At present, a standard rebate of 10 per cent is being provided for Khadi. I propose to extend this rebate to Kambais and Kambais. Government also proposes to increase the target for Janata cloth for handloom from the present 500 million metres a year to 600 million metres in the coming year.

42. It has been a long standing demand of the tiny and small industries that there should be a separate apex bank for them. Hon'ble Members will be happy to know that it has now been decided to establish a Small Industries Development Bank of India. The new bank will be a subsidiary of the Industrial Development Bank of India. The equity of the new bank will be Rs. 250 crores, and it will have its own separate Board of Directors, including representatives from the small scale sector. The new Bank will also administer both the Small Industries Development Fund established in May, 1986 and the National Equity Fund for providing equity support to projects in tiny and small scale sector.

43. New small scale units often experience problems and delays in securing working capital finance. In order to overcome this difficulty, it has been decided that requirements of working capital upto Rs. 2.5 lakhs for new tiny and small scale units, whose project cost does not exceed Rs. 5 lakhs, will be provided through a single window. Thus, both term loans and working capital will be made available by the same bank or institution. The details of this scheme will be announced by Industrial Development Bank of India shortly.

44. A healthy capital goods sector is a pre-requisite for self-reliance. Last year, while presenting the Budget, the Prime Minister announced a package of measures to revitalise the machine building industries. Later in my speech, I shall be announcing certain measures which will carry this process further for revitalising industries such as paper, cement, and textiles. These measures will help to stimulate demand, lower costs and improve efficiency.

45. The Capital market is an important source for mobilisation of savings for industry and Government has taken several steps to strengthen it. Last year, the Prime Minister announced the decision to set up a separate Board for the regulation and development of the Stock Exchanges. Necessary legislation in this regard is under preparation and the Board is expected to become operational soon. Measures have also been taken to set up Mutual Funds, lay down ground rules for orderly operations of the Stock Exchanges, improve their infrastructure, facilitate share transfers and enforce better discipline on companies entering the market. Later in my speech, I shall be announcing certain further measures which will help to boost investment in new industries and generate more employment and economic activity.

46. We have one of the largest pools of scientific and technical manpower. Yet, many of our young and new entrepreneurs find it difficult to raise equity capital because of the risk involved. This problem can be solved by allowing Venture Capital Companies or Funds to invest in new companies in anticipation of future capital gains. However, such companies at present are not eligible for the concessional treatment of capital gains available to non-corporate entities. In order to overcome this problem, it has been decided to formulate a scheme under which approved Venture Capital Companies/Funds will be enabled to invest in new companies and be eligible for the concessional treatment of capital gains available to non-corporate entities. Necessary legislative measures will be taken to bring this into effect.

47. At present, a tax concession is available for investment in the equity shares of new industrial undertakings. Small investors generally find it difficult to take advantage of these concessions because of absence of sufficient information about the prospects of new companies. It has been decided that concession now available for direct investment in equity shares of new industrial undertakings will also be available for investment in special units of mutual funds where the resources are earmarked for investment in new projects. This will help new companies to raise capital more easily.

48. I also propose to provide a separate exemption upto Rs. 3,000 for income from dividends under Section 80L of the Income tax Act. This will be in addition to the existing concessions available for certain types of incomes, including dividends upto Rs. 7,000 and a further Rs. 3,000 for income from investments in Unit Trust of India and certain other specified investments which I am including in the Finance Bill.

49. Sharp fluctuations in international exchange rates have posed problems for exporters as well as for Indian industry. In order to provide some protection to individual projects from exchange rate fluctuations, financial institutions will introduce a new scheme whereby promoters of such projects can have their foreign currency loans designated in rupees. The interest rate on such loans will be variable and will include an exchange premium. The details of the scheme will be announced by the Industrial Development Bank of India separately.

50. It has been the policy of this Government to encourage workers' participation in management in industry. It is only through interaction and involvement of workers in management that we can improve the overall performance, increase productivity, and prevent sickness. Government has already announced a scheme to facilitate such participation. I am happy to inform the House that complete exemption from Income tax will be given in respect of all expenditure incurred by companies in connection with introducing schemes for workers' participation. Government has also introduced a scheme whereby 5 per cent of the capital issues are reserved for employees. In order to facilitate purchase of shares by workers in their own companies, banks are being asked to provide loans liberally for this purpose. Reserve Bank of India will be issuing necessary instructions shortly.

51. Working journalists have contributed a lot to the country by their intellectual toil, and suggestions have been received that a Bill should be considered by the Parliament to provide a reasonable pension scheme for them. Government will be taking appropriate steps in this direction after consulting all concerned.

52. Government attaches considerable importance to strengthening economic and cultural ties with Indian nationals settled abroad. A number of facilities, including fiscal concessions, have been extended to Non-Resident Indians for facilitating investments. In response to representations received, Government have now decided to introduce a new scheme of Foreign Currency denominated Bonds/Deposit Certificates for Non-Resident Indians on a non-repatriable basis. The maturity period of these Bonds/Deposit Certificates will be 7 years and these will carry an interest rate higher than that applicable to the repatriable foreign currency non-Resident deposits. These Bonds/Deposits will be free from Income-tax Wealth tax and Gift tax.

53. The fiscal regime for investments and deposits by Non-Resident Indians in our country has been made quite liberal. It is the Government's intention to maintain fiscal stability. No changes will be made in the tax treatment which might adversely

affect investments already made by Non-Resident Indians.

54. The success of Non-Resident Indians in many fields of scientific, economic and cultural endeavour has been a matter of great satisfaction to us. We cherish our continued association with them.

55. I also propose to introduce certain measures for boosting small savings collections. I am particularly keen to mobilise untapped rural savings. A new scheme without tax concession, but with flexibility of encashment after two and half years of deposit, is being introduced. The rate of interest will progressively increase for longer durations. The deposit will double in value after five and half years. This instrument will attract new investments as it can be encashed as and when funds are needed. The instrument will be called KISAN VIKAS PATRA.

56. Last year a new savings scheme based on the net savings principle, was announced by the Prime Minister. Under this scheme, 50 per cent of deposits upto a maximum of Rs. 20,000 are eligible for deduction under Section 80CCA of Income tax Act. However, in the year of withdrawal, 50 per cent of the amount withdrawn is added to the taxable income. The interest rate on deposits was 9 per cent. It has been decided to raise the interest rate to 11 per cent. The new rate will be applicable to existing deposits also with effect from 1st April of last year. Further, the rate of deduction at the time of deposit will be raised from 50 per cent to 100 per cent with corresponding increase in the amount subject to tax at the time of withdrawal. The amount eligible for deposit is also being increased to Rs. 30,000 per annum with effect from next financial year.

57. The doubling period of Indira Vikas Patra sold from 1st March, 1988 will be reduced to five years.

58. It is also proposed to continue the sale of Rahat Patra beyond 29th February, 1988. With the continuance of Rahat Patra, sale of Capital Investment Bonds is proposed to be discontinued from 1st April, 1988.

59. Sir, I have taken this opportunity to announce certain measures for the welfare of the weaker and vulnerable sections of our society, for generating greater employment opportunities, particularly in the rural areas and for strengthening our productive base. I am sure these measures will contribute to fulfilling the aspirations of our people.

60. Let me now turn to the Revised Estimates for 1987-88 and Budget Estimates for 1988-89.

Revised Estimates 1987-88

61. The Revised Estimates of total expenditure in the Budget for 1987-88 are placed at Rs. 66161 crores against Rs. 62942 crores in the Budget Estimates. As the gravity of the drought became clear, the first task of the Government was to ensure that sufficient resources were available with State Governments in order to start relief works and take

other measures for alleviating the distress caused by the drought. Central Teams were despatched to States and decisions announced in record time in respect of ceilings of expenditure for States affected by drought and floods. Expenditure from the Central Budget on account of drought, floods and other natural calamities is now estimated at nearly Rs. 2,000 crores. This includes Centre's share of margin money, advance Plan assistance for drought, non-Plan assistance for floods and hailstorm, supply of subsidised foodgrains in drought affected areas, subsidised supply of seeds, provision of rigs for drinking water and assistance for Accelerated Rural Water Supply Programme.

62. There have been certain other inevitable increases in expenditure. The subsidy on indigenous fertilizers will go up by Rs. 300 crores. Food subsidy will also be Rs. 200 crores higher. I am sure Hon'ble Members will agree with me that, under the circumstances prevailing in the current year, the increases are fully justified. The liberalisation of pensionary benefits of Government employees, particularly the Defence Services personnel, is expected to add Rs. 374 crores to the pension bill in the current year. Financial reliefs granted to certain public sector enterprises are expected to cost additional Rs. 417 crores by way of subsidy, write off of loans etc. Interest charges are likely to be Rs. 800 crores higher than the original Budget provision. Taking into account the other variations, the total non-Plan expenditure during the current year is estimated to be Rs. 1,971 crores higher than the original Budget provision of Rs. 39,265 crores.

63. Central assistance for State and U.T. Plans is expected to be Rs. 1,127 crores higher mainly due to larger advance Plan assistance to States affected by drought. Budgetary support for Central Plan is estimated to be Rs. 121 crores higher—this being the net effect of increases in sectors like agriculture, rural development, fertilizers, agricultural financial institutions, subsidy for setting up industries in backward areas, etc. offset by savings in certain other sectors.

64. Taking the Plan and non-Plan together, there is an increase of Rs. 3,219 crores. As a result of a series of measures undertaken by Government during the year, economy consciousness has been created and expenditure contained particularly in low priority areas.

65. Gross Tax Revenue is estimated to yield Rs. 1,028 crores more than the Budget Estimates mainly under Income and Corporation taxes and Customs duties. The share of States in taxes will be higher by Rs. 392 crores. Non-tax Receipts will be higher by Rs. 2,201 crores. Of this, non-tax revenue receipts are expected to fetch Rs. 765 crores more and capital receipts Rs. 1,436 crores more. Rs. 700 crores of the increase in capital receipts will be from market loans.

66. Taking the variations in expenditure and receipts into account, the current year is expected to end with an overall deficit of Rs. 6080 crores. Notwithstanding the severe strain the events of the year have cast on the Budget, this is close to the original estimate of Rs. 5,688 crores.

Budget Estimates for 1988-89

67. The Hon'ble Members will agree that Budget Estimates for the year 1988-89 are being presented in a rather difficult environment. We have to ensure that despite pressures on the Budget, there is no cut-back in public investments, as that would have an adverse effect on economic activity and employment. Accordingly, in framing the Budget for next year, highest priority has been given to maintaining the tempo of Plan investment.

68. The Central Plan for 1988-89 has been fixed at Rs. 28,715 crores against the approved outlay of Rs. 24,622 crores in the current year, a step up of 16.6 per cent. Even compared to the revised Central Plan outlay of Rs. 25,701 crores, the next year's outlay represents a step up of 11.7 per cent. Central Plan for the next year will be financed to the extent of Rs. 16,000 crores from budgetary resources and Rs. 12,715 crores from Internal and Extra Budgetary Resources of public enterprises. With the proposed outlay for 1988-89, we would have achieved in four years more than 86 per cent of the Seventh Plan outlay in real terms.

69. In addition, Central Budget for the next year provides Rs. 9,714 crores for assistance for State and UT Plans. The total Plan expenditure in the Budget for the next year is thus, Rs. 25,714 crores compared to Rs. 24,925 crores in the Revised Estimates for the current year.

70. I am glad to inform the House that the total transfers from Centre to States in 1987-88, including their share in taxes were Rs. 24,870 crores. In 1988-89 such transfers are estimated at Rs. 26,348 crores, an increase of Rs. 1,478 crores.

71. Several States have represented that their liquidity position has been affected by the drought and have requested for some relaxation in the Ways and Means limits. The Hon'ble Members will be happy to know that Reserve Bank of India is raising from tomorrow the Ways and Means limits by 40 per cent over the limits prevailing prior to October, 1986. These were stepped up by 30 per cent and 20 per cent for different periods of the year in October, 1986.

72. As mentioned earlier it has been decided to increase the outlays of the Departments of Agriculture and Cooperation and Water Resources by 40 per cent above the current year's outlay. I also propose to provide Rs. 671 crores for fertilizer projects in 1988-89. During the current year, four new fertilizer plants, two each in public and private sectors, are likely to go into production. Fertilizer production is expected to attain a level of 7.1 million tonnes this year, an increase of nearly 40 per cent over the output at the commencement of the Seventh Plan.

73. The major anti-poverty programmes, namely, Integrated Rural Development Programme (IRDP), National Rural Employment Programme (NREP) and Rural Landless Employment Guarantee Programme (RLEGP) will continue to be the main instruments for generating employment and increasing

the earning opportunities for those below the poverty-line. Thus far, about 254 lakh families have been assisted with a total investment of Rs. 8,413 crores under IRDP. Forty per cent of these beneficiaries belong to Scheduled Castes and Scheduled Tribes. Under NREP and RLEGP, 7,006 lakh man-days were generated in 1986-87 which was substantially higher than the target of 5,115 lakh man-days. The target is likely to be exceeded this year also.

74. These programmes have proved highly successful in generating employment in our rural areas. Suggestions have been received for expansion of these programmes as well as for their consolidation. The merger of some important programmes like the National Rural Employment Programme, Accelerated Rural Water Supply Programme, Rural Landless Employment Guarantee Programme and Desert Development Programme, and various other Anti-poverty Programmes have also been suggested so that available resources can be more effectively deployed to meet the twin objectives of employment and creation of assets to meet village needs. There is also need to provide flexibility at the operational level. In the light of these suggestions, it is proposed to undertake a thorough review of the employment programmes in the coming year to examine the possibility of having a comprehensive programme.

75. Rural water supply continues to receive high priority. The technology mission for drinking water in villages and related water management is being pursued vigorously. In 1988-89, I propose to provide Rs. 2,200 crores for the Department of Rural Development, inclusive of Rs. 430 crores for rural water supply and sanitation. As Hon'ble Members are aware, the outlay on water supply is in addition to the Minimum Needs Programme outlay in the State Sector.

76. Welfare programmes for the tribal people have to be based on respect and understanding of their culture and tradition, and appreciation of their social, psychological and economic problems. The main instrument for the development of tribal people and tribal areas is the Tribal sub-Plan. As the Hon'ble Members know, the Tribal sub-Plans are financed by the State Governments. Special Central Assistance, Centrally Sponsored Programmes and financial institutions. The Special Central Assistance for Tribal sub-Plan 1988-89 is Rs. 185 crores. For Scheduled Castes, Special Component Plans are being formulated with the primary objective of providing occupational mobility and economic strength. In the current year, over 20 lakh Scheduled Caste families are likely to be benefited by these programmes. An amount of Rs. 180 crores has been provided as Special Central Additive to Special Component Plan for 1988-89.

77. Our human resources are the most important resource of all. The quality of manpower developed today will be decisive in determining the pace and direction of economic and social progress in the future. In 1986, a new Education Policy was introduced after extensive discussion in Parliament and outside. In order to give a good start to the new Policy, last year, while presenting the Budget

the Prime Minister raised the allocation for education sharply to Rs. 800 crores from Rs. 352 crores in 1986-87. The actual expenditure is likely to be of the order of Rs. 700 crores. Next year's Plan makes an allocation of Rs. 800 crores. Together with the non-Plan provision, the total allocation for the Department of Education in 1988-89 will be Rs. 1,550 crores against the Revised Estimate of Rs. 1,185 crores for 1987-88.

78. Improvement in the health status of the population is an essential component of the human resource development. To achieve this, special emphasis is being laid on establishing primary health facilities, particularly in rural areas, launching control programmes for major communicable and non-communicable diseases, augmenting facilities for medical and para-medical education and training and providing family welfare, maternity and child health, immunization and related services. Under National Leprosy Eradication Programme, multi-drug treatment has been extended to nearly 2.2 million cases out of the estimated 4 million cases. The Universal Immunization Programme is being extended to 120 districts, besides 182 districts already covered. Health Contingency Plans have been prepared for drought affected States. I propose an outlay of Rs. 228 crores for medical and public health programmes and Rs. 600 crores for family welfare programmes for 1988-89.

79. Government have initiated a number of measures to ameliorate the conditions of working women. These include programmes for raising skills and economic development, supportive services for working women and shelter and rehabilitation for women in adverse circumstances. For children, a national wide programme of Integrated Child Development Services has been in operation. An important objective of these ICDS Programmes is to reduce childhood mortality, morbidity and malnutrition. I am happy to inform the Hon'ble Members that 1,738 Integrated Child Development Services Projects have been sanctioned for the most backward rural areas, tribal areas and urban slums in the country. During the remaining period of the Seventh Five Year Plan, we will be covering most of the tribal blocks with more than 30 per cent Scheduled Tribe population and also the slums in big cities. For the next year, I propose an outlay of Rs. 235 crores for the Department of Women and Child Development.

We are proud of our youth. We are sure that our heritage and our country's future are safe in their strong hands. Adequate provision has also been made for youth and sports activities in the coming year with an increase of 13 per cent over the current year.

80. Energy, Transport and Communications constitute the basic infrastructure of the economy. A total allocation of Rs. 16,588 crores is being provided for these sectors. This outlay represents an increase of about 25 per cent over the current year's level, and accounts for about 58 per cent of the total Plan outlay for 1988-89.

81. Electricity generation has been increasing at an annual rate of 9 to 10 per cent during the Seventh Plan. Though hydro-generation was adversely affected by drought this year, thermal generation registered an improvement of 16 per cent during the first nine months of the current year compared to the corresponding period of last year. The plant load factor of the thermal plants has improved further and is expected to touch 55 per cent, the highest in the last 10 years. I am providing for an outlay of Rs. 3,963 crores for the Power sector, that is, an increase of over 32 per cent over the current year's outlay.

82. Coal is the primary and the most abundant source of conventional energy in our country. I am stepping up the provision for this sector by 30 per cent, to a level of Rs. 1,733 crores for 1988-89. The production of coal during the current year is expected to reach 182 million tonnes as against the last year's level of 166 million tonnes.

83. As Hon'ble Members are aware, our Petroleum and Natural Gas sector has taken great strides during this decade. The rebound in international oil prices has underlined the urgency for finding and exploiting hydro-carbon resources. Significant discoveries during the year in Krishna-Godavari Off-shore Region and the Bhuvanagiri area of the Cauvery Basin constitute promising rewards to our heavy investments in oil exploration. The year also saw the completion of the first section from Hazira to Bijaipur of the HBJ Pipeline covering 642 kilometres. To maintain the tempo of exploration and production of crude oil and natural gas, I propose an outlay of Rs. 3,395 crores for the Petroleum sector.

84. In the field of communications I must share with the House a sense of pride in the work of the Centre for Development of Telematics. By developing a state-of-art electronic switching system, C-DoT has demonstrated what we can achieve through proper organisation and marshalling of our scientific talents. I am allocating Rs. 1,873 crores for 1988-89 for the Department of Telecommunications—an increase of 44 per cent over the outlay for the current year.

85. Government recognises the development of our scientific and technological resources as a necessary pre-requisite for the economic development of the nation. With this in view, I propose to increase the outlay of the Scientific Departments by about 20 per cent over the current year's level. We can take justifiable pride in the many achievements of our scientists and technologists. While there have been many notable developments during the year, I would like to make a special mention of one of these. On August 26, 1987, the Prime Minister had informed the Hon'ble Members that India was the first applicant to be allotted a mine site in the Central India Ocean by the Preparatory Commission for the International Sea-bed Authority. This is a significant step forward in development of our scientific potential. The mine site of 1,50,000 sq. kms. contains a rich deposit of polymetallic nodules.

86. Many other initiatives are envisaged in the different sectors of the economy. However, I do not

propose to take the valuable time of the House with a detailed review of all the Plan programmes. The full details are available in the Budget documents.

87. The allocation for Defence is Rs. 13,000 crores against Rs. 12,000 crores in the current year. Our armed forces, in the face of unwarranted provocations, have done a tremendous job of protecting our borders. Our jawans are the nation's strength. We shall continue to provide them the requisite support in their efforts. Food and fertilizer subsidies are placed at Rs. 5,300 crores against Rs. 4,410 crores in the current year. Interest charges next year are estimated as Rs. 14,100 crores against Rs. 11,450 crores in the current year. The allocation of export promotion and market development is Rs. 1,091 crores. The other increases relate to grants payable to States for revision of pay scales of university and college teachers, grants and loans to foreign Governments, strengthening of police forces and payment of Rs. 100 crores to Oil Industry Development Board. A lump sum provision of Rs. 800 crores has been made for additional D.A. instalments that may become payable to Government employees next year. I would like to assure the Hon'ble Members that I have kept the non-Plan expenditure to the barest minimum. Non-Plan expenditure in 1988-89 will thus be Rs. 47,896 crores against Rs. 41,236 crores in the Revised Estimates for the current year.

88. Coming to receipts, Gross Tax Revenue at existing rates of taxation is estimated at Rs. 41,985 crores. After payment of Rs. 10,682 crores to States and local bodies as their share of taxes, the net tax revenue to the Centre next year is estimated at Rs. 31,303 crores. Receipts from market loans are placed at Rs. 7,000 crores, that is, the same level as in the current year. External assistance, net of repayments, is placed at Rs. 3,734 crores, against Rs. 3,184 crores in the current year. Taking into account the variations in other receipts and expenditure, Budget deficit for the next year at existing rates of taxation is estimated at Rs. 8,120 crores.

PART B

89. I shall now turn to my revenue proposals. Every Budget has to raise some resources for financing expenditure, and I shall not be failing in my duty to do so. However, I do believe that it is equally, if not more, important to use fiscal policy for achieving our wider economic and social goals while, at the same time, providing relief where it is due. I am sure, the Hon'ble Members will find a strong link between the proposals that I am about to make, and some of the people-oriented initiatives that I have referred to in Part A of my speech.

90. This House is aware of the fact that in view of the exigencies of the situation, in order to meet the formidable after-effects of the drought of 1987-88, Government took a decision to levy a surcharge of 5% on income-tax for persons with taxable income above Rs. 50,000, a surcharge of 10% on wealth tax for the assessment year 1988-89 and a 5% surcharge by way of auxiliary duty of customs on imported goods excluding essential commodities like fertilizers, power

equipment, life-saving drugs and medical equipment, etc. This timely action helped the country and the Central and State Governments to meet the requirements of a very difficult situation created by the drought. This surcharge did not touch essential commodities.

91. In view of the continuing pernicious effects of the drought and the natural calamities, I propose to continue with these surcharges for one more year. In addition, it is now proposed to levy a surcharge by way of Special Excise Duty at the rate of 1/20th of the Basic Duty of Excise. The incidence of this surcharge will generally be small; for example, it will be only one quarter of one percent i.e. 0.25%, where the basic duty is 5% ad valorem and one percentage point where the basic duty is 20%.

92. Essential commodities and other priority items which are presently exempt from excise duty will continue to remain exempt. I am also exempting from this surcharge, certain other essential goods of common consumption, namely, sugar, matches, cotton fabrics, vanaspati, refined vegetable oil, tea, coffee and kerosene.

Direct Taxes

93. Hon'ble Members will recall that, in August, 1986, a Discussion Paper on Direct Tax Laws was presented in Parliament. After further discussions and consultations among experts and the public, the Government had introduced the Direct Tax Laws (Amendment) Bill, 1987, which was passed during the last Session. Since then, many representations have been received from experts, concerned Associations, Chambers of Commerce and other tax-payers regarding some provisions in the Act. The following, inter alia, are the main points made in these representations :—

- (1) The proposed system of assessment of partnership firms is too harsh particularly on partnership firms with small income, as such firms, subject to certain deductions, will henceforth be taxed at the maximum marginal rate. Certain other clarifications have also been sought in regard to some other provisions relating to taxation of firms.
- (2) The levy of additional tax at a flat rate of 30 per cent would be very unfair in cases of genuine doubt regarding taxability of certain receipts and that the levy of additional tax should itself be appealable.
- (3) The provisions relating to charitable trusts, voluntary agencies and institutions carrying on scientific research, etc. may result in unintended hardship, particularly as regards the treatment of contributions to the corpus of such institutions.
- (4) The new Act provides for unfettered discretion regarding reopening of assessments merely on a change of opinion.

94. There are many positive features in the Act, which will help the tax-payers by simplifying the law.

but there is also scope for reconsideration keeping in view the representations against some of its provisions. In a democracy, Government should always keep itself abreast of public opinion and be flexible enough to respond to reasonable suggestions. Government will bring a further amendment bill in the Budget Session which will take care of genuine grievances. After the Bill is introduced, Government will be happy to consider any further suggestions that the Hon'ble Members may have to offer.

95. A reasonable degree of stability in the Direct Tax regime is desirable for inspiring confidence and encouraging savings and investment. I do not, therefore, propose any change in the rate structure for personal and corporate taxes.

96. There is, however, a case for reducing, to some extent, the brunt of the burden borne by the fixed income groups. I, therefore, propose to raise the rate of standard deduction from 30 per cent to 33-1/3rd per cent of salary income and the ceiling from Rs. 10,000/- to Rs. 12,000/-. This measure will benefit about a million tax-payers.

97. Hon'ble Members will recall that Estate Duty was abolished from March, 1985. This was done mainly because the Estate Duty law was complicated and led to procedural harassment to large numbers of tax-payers at a time of great distress, with negligible gain in terms of revenue. However, there is a strong case on grounds of social justice for taxing the transfer of wealth through inheritance especially where the volume of wealth involved is large. This matter has been under consideration of Government for some time. Government have decided to levy a tax on the transfer of wealth which will be applicable to all wealth-tax assesses. The tax will be levied in respect of assets subject to wealth tax. The method for valuation of assets would be the same as for the wealth tax. It will also be administered by the wealth tax officer. The rate of the wealth transfer tax would be 5 times the applicable wealth tax rates. This new tax will avoid the rigidities and procedural delays which characterised the operation of the old Estate Duty Act. As I have mentioned, it will be applicable only to wealth tax assesses and will not affect ordinary tax-payers. Separate legislation in this regard will be introduced in this Session.

98. The thrust of my other proposals in regard to Direct Taxes is to strengthen incentives for export promotion and foreign exchange earnings, to encourage savings and to stimulate the capital market.

99. To encourage exports, I propose to enhance the existing tax concession under Section 80 HHC for export profits so as to exempt 100 per cent of export profits from income-tax. It is also proposed to extend the benefit to supporting manufacturers exporting through Trading or Export Houses. A five-year tax holiday presently available for units in Free Trade Zones is also being extended to 100 per cent Export Oriented Units. Replantation and rejuvenation subsidies for rubber, coffee and cardamom plantations are also proposed to be exempted from income-tax.

100. To promote long-term financing available for construction and purchase of houses, I propose to enhance the existing concession available under Section 80L in respect of interest and dividend income received from companies providing such finance. At present, such income is included under the general exemption limit of Rs. 7,000. It is proposed to make such income also eligible under the separate limit of Rs. 3,000 for UTI under Section 80L.

101. As an anti-evasion measure, I propose to provide for assessment of income of persons engaged in certain trades, like liquor and forest contracts, at a reasonably fixed percentage of the amount payable by them while purchasing the goods. The tax will be collected at source.

102. I also propose to tax under the head "capital gains", income from transfer of a capital asset by a holding company to its wholly owned subsidiary company or vice versa, in every case where the capital asset is taken over as stock-in-trade at the time of transfer.

103. Hon'ble Members will recall that in Part A of my speech, I have already referred to certain changes being made in the income-tax payable by LIC as well as certain fiscal measures to promote the equity market. There are certain other minor proposals regarding Direct Taxes in the Finance Bill.

104. The total effect of these proposals will be a revenue loss of Rs. 201 crores, which will be off-set by my proposal to continue with the levy of surcharge on income-tax and wealth-tax which will mean a gain of Rs. 270 crores. Thus, the net increase in revenue will be Rs. 69 crores.

Indirect Taxes

105. Sir, I will now move on to the proposals relating to indirect taxes. It has been my endeavour to see that the basic thrust provided in the field of indirect taxes in the Budget last year is carried forward. I have proposals for providing stimuli to cover agriculture and farming sectors, rural employment, exports, health and medical care, housing and construction activities, technology upgradation and selected industries such as cement, textiles, electronics, paper and plastics. There are also some important reliefs for the common man.

Agricultural and other allied sectors

106. In Part A of my speech, I have announced several measures for the benefit of the farmers, including reduction in interest rates and reduction in cost of inputs, such as fertilizers. I now propose a number of fiscal reliefs for promotion of agriculture and agro-based activities.

107. Monobloc pumpsets and submersible pumpsets are important for irrigation. I am exempting electric motors used in these pumpsets from excise duty.

108. To bring down the cost for farmers, I propose to fully exempt from excise duty a large number of pesticide intermediates. I am also proposing to

reduce customs duty in respect of a number of pesticides and pesticide intermediates from the existing levels of 105 per cent and 147 per cent to 70 per cent and 60 per cent ad valorem. These measures will reduce the cost of indigenous production and the end-prices.

109. With a view to promoting modernisation in the agricultural, horticultural, poultry and bee-keeping sectors, I am providing for full exemption from excise duty in respect of machinery for these sectors such as sprinkler systems, fodder mixers, germination appliances, egg candlers, etc.

110. Cold storages are of great importance for the marketing of agricultural produce. I propose to reduce the excise duty on parts and accessories going into the installation of cold storage plants from 40 per cent to 15 per cent ad valorem.

111. As the House is aware, the Government has taken up an ambitious programme of increasing milk production through genetic improvement of cattle and buffaloes. Certain critical equipments, hormones and drugs required for this programme are accordingly being exempted from customs duty in excess of 25 per cent ad valorem.

Food Processing and Packaging

112. Growth of food processing and packaging industry can be of immense help in increasing the value-added of agricultural produce and raising incomes of farmers. In continuation of certain measures for growth of this industry, announced by the Prime Minister last year, it is proposed to further reduce the customs duty in respect of 34 specified items of food processing and packaging machinery from 55 per cent to 35 per cent ad valorem. I also propose to reduce the excise duty on preparations from vegetables, fruits, nuts or other parts of plants like jams, fruit juices, etc. from 10 per cent to 5 per cent ad valorem. Such preparations from vegetables and fruits like jams, jellies, fruit juices, sauces, ketchup and pickles, if manufactured in rural areas by registered cooperative societies, Khadi & Village Industries Commission and State Khadi & Village Industries Boards are proposed to be exempted from excise duty altogether.

113. I also propose to reduce the excise duty on aluminium foil from 25 per cent to 15 per cent ad valorem. This will help in hygienic and scientific packaging of processed food, drugs, condiments, etc.

Rural Employment

114. Off-farm self-employment provides a major route for enhancing income and earnings in the rural areas. Individually, a micro-entrepreneur with low staying power is vulnerable to adverse market forces. His success lies in cooperative ventures. Hence, I am providing for a special scheme for generation of self-employment in the rural areas. Under the proposed scheme, specified products, namely, radios, cassette players and recorders in combination with radios, tape recorders, voltage stabilizers, footwear of a value not

exceedings Rs. 75 per pair and a few other items will be fully exempt from excise duty, if they are manufactured in rural areas by registered cooperative societies, including self-employed women's cooperatives or cooperative societies under the Scheme of Development of Women and Children in Rural Areas or the Khadi and Village Industries Commission or the State Khadi and Village Industries Boards.

115. As Hon'ble Members are aware, there are a large number of self-employed persons working as carpenters, fitters, electricians, plumbers, etc. To lend further strength to their toiling hands and with the twin objectives of increasing their productivity and earnings, I propose to reduce the excise duty in respect of some hand tools like files, screwdrivers, pliers, etc. from 20 per cent to 10 per cent ad valorem.

116. To promote better accounting and to relieve the traders, city-based shop keepers, small businessmen, wholesalers and small factory owners from the drudgery of book-keeping at the end of the day, I propose to reduce excise duty from 20 per cent to 10 per cent on small electronic cash registers of assessable value of Rs. 10,000 or below.

Consumer Articles

117. I am conscious of the fact that common consumers have been affected by some price increase. I am anxious to give them some relief within the constraints in which I am operating.

118. I propose to increase the upper value limit from Rs. 25,000/- to Rs. 30,000/- for the purpose of extending the concessional rate of excise duty of 15 per cent ad valorem in respect of a wide variety of commonly used toilet soaps. I am also proposing to fully exempt from excise duty laundry and carbolic soaps manufactured in rural areas by cooperatives and khadi and village industries sector.

119. So far, electric bulbs upto 60 watts have been exempted from excise duty. With a view to facilitating a brighter luminance in houses, streets, work places, etc., I propose to reduce the excise duty in respect of electric bulbs exceeding 60 watts from Rs. 1.50 per bulb to Re. 1.00 per bulb.

120. As a measure of providing a little more happiness and education among children, I propose to completely exempt from excise duty toys, like toy scooters, toy pedal cars, dolls, toy musical instruments, scale models, recreational models, etc. and inexpensive pencil sharpeners.

121. With a view to reducing domestic drudgery, I propose to fully exempt from excise duty certain domestic electrical appliances from frying pans to saucepans. I am also similarly exempting electric kettles, water-boilers, toasters and automatic irons. I am also totally exempting stainless steel utensils from excise duty.

122. As a further component of anti-smuggling measures and to cultivate a greater sense of time-consciousness and to instil a spirit of greater punctuality among the school-going children, college

students, office-goers, the public generally and, if I may venture to say so, politicians like us also, I propose to reduce the excise duty on wall clocks and quartz clocks and parts thereof from 15 per cent to 5 per cent ad valorem. I shall be announcing some relief for indigenous watch industry later in my speech.

123. In respect of glassware, I propose to reduce the excise duty in respect of a number of items of tableware of common use like jugs, cups, plates, bowls, etc. manufactured by automatic process from 40 per cent to 25 per cent ad valorem and those manufactured by the semi-automatic or mouth-blown processes, to 20 per cent ad valorem.

124. I also propose to exempt from excise duty all children's films and all films selected for the Indian panorama section for International Film Festivals.

125. There can be no better auspicious occasion than the Government's Annual Budget to exempt sindoor, kajal, alta and mahavar—the age-old symbols of glorious and devout womanhood—from taxation and, accordingly, I hereby do so by proposing to fully exempt these from excise duty.

Health and Medicare

126. Our goal is to provide cheap and efficient medicare to all our people. Towards achieving this objective, availability of essential drugs at lower prices has to be ensured. I, therefore, intend to align the excise tariff, as far as possible, with the new Drug (Prices Control) Order, 1987. I propose to provide total exemption from excise duties in respect of formulations and bulk drugs which are specified in Category I of the Drug (Prices Control) Order. Intermediates for these drugs will also be fully exempt from excise duty. The House would recall that the drugs specified in Category I are required for the National Health Programmes like T.B., Leprosy, Malaria, Filaria Eradication programmes and programmes for the control of blindness and trachoma and prevention of dehydration.

127. A concessional excise duty of 10 per cent ad valorem is being prescribed for single ingredient formulations based on drugs specified in Category II of the Drug (Prices Control) Order. I also propose to continue the existing excise duty exemptions in respect of specified cardiac drugs and anti-TB, anti-malaria, anti-leprosy and anti-diabetic drugs. Two anti-cancer drugs and an important life-saving drug, are proposed to be added to the list of exempted drugs. However, I propose to withdraw the existing exemption from customs duty in respect of specified formulations for which adequate indigenous capacity has been built up. It is hoped that these fiscal reliefs will encourage domestic production and help better availability of these vital drugs.

128. I propose to prescribe a nominal excise levy of 5 per cent on bulk drugs except those covered by Category I of Drugs (Prices Control) Order. This will enable the manufacturers to avail of MODVAT credit in respect of all dutiable inputs including drug

intermediates. I also propose to reduce the import duty on 235 specified drug intermediates from 115 per cent to 90 per cent ad valorem.

129. In the related field of medical equipment, the procedure for customs duty-free import of hospital equipments, apparatus, appliances including spare parts and accessories by Government and Government-controlled hospitals is being simplified. Similarly, the procedure for import of specified sophisticated medical equipment at a concessional duty of 40 per cent ad valorem is also being streamlined. In respect of such imports by Non-Resident Indians, financed out of their own foreign exchange resources, the duty will be even lower at 20 per cent. Import of such equipment when financed by Government to Government assistance will be exempt from customs duty.

130. I propose to extend the concessional duty to spare parts of such specified equipments also at 40 per cent ad valorem. The list of medical equipments attracting concessional customs duty at 40 per cent ad valorem is being enlarged by addition of 83 dental, ophthalmological, cardiological, gynaecological, general surgical and other medical equipments. Components of these equipments will also be charged duty at 40 per cent as against the existing levels ranging from 80 per cent to 130 per cent ad valorem in order to encourage domestic manufacture of these equipments.

131. I also propose to reduce the excise duty on these indigenously manufactured equipments from 15 per cent to 5 per cent ad valorem. The excise duty on X-ray films is also proposed to be reduced from 15 per cent to 5 per cent ad valorem. Excise duty on aluminium extrusions and square and round tubes used in the manufacture of artificial limbs is being exempted altogether.

132. I hope that our dedicated doctors throughout the country will now be able to modernise their hospitals and clinics a little faster and patients will get better care and treatment thereby.

Housing

133. As I mentioned earlier, in order to encourage growth of housing it is necessary to reduce the cost of house building material. Hence, I propose to provide a general reduction in excise duty on cement from Rs. 225 to Rs. 205 per tonne. The existing differential in excise duty rates for certain categories of cement units will also continue. The levy ratios for certain categories of cement units are also being reduced.

134. In order to protect the environment and help divert demand from wood to metals, excise duty on doors, windows and their frames and thresholds for doors; made of aluminium is proposed to be reduced from 20 per cent to 15 per cent ad valorem. Similarly, excise duty on corrugated sheets of aluminium is being reduced from 25 per cent to 15 per cent ad valorem. I also propose to reduce the excise duty on steel doors, windows and their frames and

thresholds for doors from 15 per cent to 5 per cent ad valorem.

135. It is time that we think innovatively and use unconventional materials for housing which would be cheap and functional. The excise duty on blocks, slabs, lintels, etc. constituting structural intermediates and components of pre-fabricated buildings is being reduced from 12 per cent to 5 per cent ad valorem. Similarly, fly ash bricks will pay a lower duty of 5 per cent ad valorem, and lympo, a cement substitute, will bear a zero rate of duty.

136. To reduce fire hazards, we should promote the use of fire extinguishers. With this end in view, I propose to exempt fire-extinguishers from excise duty.

Exports

137. To thrive in the highly competitive international market, our natural advantages and production efforts have to be supplemented by adequate fiscal and other measures. In this context, I propose to take some further measures to promote exports.

138. Concessional rates of customs duty have been provided in the past in respect of specified items of machinery for identified export thrust sectors. Eight more machines for the garments and hosiery sector, twenty-three machines for the leather industry, four more machines for the gem and jewellery industry and three more items of textile machinery will now attract a concessional rate of 35 per cent ad valorem. Specified items of machinery for the tea, bicycle, silk and woollen industries are being provided with a concessional customs duty of 35 per cent ad valorem.

139. Ivory and Ivory powder are being totally exempted from customs duty. This will help reduce poaching in our jungles as well as provide adequate raw material for ivory handicraft industry, which is export-oriented.

140. The value-limit of duty-free import of commercial samples is being enhanced from Rs. 1,000 to Rs. 5,000 in a year; and for duty-free import of prototypes of engineering goods, from Rs. 1,000 to Rs. 10,000.

141. Full rebate of excise duty will now be available for tea exported directly from factories. The procedure for claiming rebate of excise duty on export of unblended tea by merchant-exporters is being simplified. Green tea is being exempted from excise duty altogether.

Capital Goods

142. In the modern industrial world, obsolescence takes place at a fast rate. Unless one upgrades the technology continuously, one is apt to be left out in the race. Following Prime Minister's guidelines given in last year's Budget speech, I had announced in August 1987, a technology upgradation scheme, under which fiscal relief was provided in respect of import of specified items of capital equipments

required for manufacture of machinery covered by the scheme at 35 per cent ad valorem. To promote domestic production of such machinery, the customs duty on selected raw materials needed for their production is being reduced to 55 per cent from the existing level ranging from around 100 per cent to 180 per cent. These include specified insulation materials, copper conductors, and special electrical steel sheets for power generation and electrical equipment and clad steel plates for manufacture of selected industrial machinery specified in the technology upgradation scheme. The customs duty on boiler and pressure vessel quality steel plates, turbine blade flats and stainless steel plates required for manufacture of machinery is also being reduced from 60 per cent to 55 per cent.

Scientific equipment and spares

143. There have been persistent demands from the scientific community for further fiscal concessions in regard to consumables required for research and spares of imported equipment. Keeping in view the importance of scientific research, the existing duty concession schemes are being liberalised. The certification procedures, which have been acting as hurdles in the clearance of these goods, are being simplified.

144. Some specified scientific instruments and apparatus would bear excise duty of 5 per cent ad valorem instead of the current rate of 15 per cent.

Textiles

145. The textile industry has a unique place in the industrial map of India. It provides jobs to millions of our people. It is a major export earner, and is directly linked to agriculture. Of late, the industry has suffered from widespread sickness and haphazard growth. Availability and prices of raw cotton and cotton yarn have been subject to considerable instability. Handloom weavers are suffering because of yarn prices. Powerlooms have their problems too. While production of synthetic yarn, which is used for blended fabrics preferred for their durability by the common man, has expanded, prices of such yarn have been very high. Smuggling has been another problem which, despite Government's strong action, has had some adverse effects on the economy.

146. In order to overcome these problems, in 1985, Government had announced a new Textile Policy. Its primary objective was to increase production of cloth of acceptable quality at reasonable prices. In line with this policy, a number of measures have already been taken by the Government. These have yielded results as reflected in the increase in production and availability of cloth. I now propose to provide some fiscal support to the endeavours of the Ministry of Textiles in reviving this industry so that, once again, it can regain its rightful place in our economy. My proposals, which follow are based on a comprehensive review of the duty structure relating to the various segments of the industry with a view to lowering prices, increasing the demand for fabrics and increasing the base of production.

147. In 1985, a scheme was evolved for making available duty-free polyester staple fibre to the handloom sector for manufacture of designated fabrics under a scheme approved by the Government. I now propose to reduce the excise duty on polyester filament yarn for manufacturing handloom fabrics under a scheme for supply management and distribution of fabrics, to be announced by the Ministry of Textiles. Similarly, viscose filament yarn will bear a concessional rate of 50 per cent of the existing duty, when the yarn is supplied to registered handloom cooperative societies or any approved organisation for the development of handlooms.

148. I also propose to exempt handloom woollen fabrics processed by approved independent processors from excise duty. Raw wool imported by certain specified handloom agencies is being exempted from customs duty. The import duty on acetate filament yarn is being reduced from 60 per cent to 45 per cent.

149. In order to reduce prices of cotton yarn, it is proposed to reduce the excise duty on cotton yarn of counts not exceeding 35 by 10 per cent of the existing rates. The excise duty on cotton yarn above 35 counts is being reduced by 3 paise per count. This will mean a reduction of upto a maximum of 28.5 per cent, depending on the count of yarn. Hank yarn for handlooms is already fully exempt. To provide further relief to handloom weavers, as I mentioned, the subsidy on janta cloth is being increased by 75 paise per square metre from Rs. 2 to Rs. 2.75.

150. Considering the fact that viscose staple fibre would help substituting for cotton, I propose to reduce the excise duty on viscose staple fibre cleared for blending with cotton from the existing level of Rs. 7 per kg. to Rs. 5 per kg. Simultaneously, I propose to increase the duty on viscose staple fibre used for other purposes to Rs. 8 per kg. to divert more VSF for cotton blending.

151. The National Textile Corporation is already manufacturing cheap fabrics under a special scheme, for which polyester staple fibre is being supplied free of excise duty. I propose to provide that polyester filament yarn will be available at a concessional duty rate of Rs. 10 per kg. to the National Textile Corporation for manufacturing fabrics under a duty credit scheme. The details will be announced separately.

152. In line with the Textile Policy, in order to facilitate absorption of increased domestic production, I propose to reduce fiscal levies on man-made fibres and yarn. This would also help revitalise the powerloom sector which is facing problems of under-utilisation of capacity and consequent problems of unemployment. The duty on polyester staple fibre is being reduced from Rs. 25 to Rs. 15 per kg., and on polyester filament yarn from Rs. 83.75 to Rs. 53.75 per kg. At the same time, in order to ensure greater availability and to put pressure on the domestic producers to pass on the reduction in excise duties fully to the consumers, import duties on these items are also being reduced by about 25 percentage points.

153. The excise duty on nylon filament yarn is being reduced from Rs. 70 to Rs. 40 per kg. and that on acrylic fibre from Rs. 10 to Rs. 8 per kg.

Customs duty on these items is also being suitably reduced.

154. It is also proposed to reduce the excise duty on nylon filament yarn for industrial purposes such as for manufacture of tyres for cycles and industrial filter fabrics, from Rs. 70 to Rs. 8.13 per kg. Nylon filament yarn of specified deniers used for fishing nets will pay an even lower concessional duty of Rs. 4.55 per kg.

155. I also propose to reduce the excise duty on certain specified textile machinery required for modernisation of the mills from 15 per cent to 5 per cent ad valorem. The customs duty on certain specified machinery for the garment, hosiery and woollen industries is being reduced to 35 per cent, as indicated earlier.

156. Hon'ble Members will agree that these comprehensive fiscal measures, supported by other measures taken by the Ministry of Textiles, should give a boost to the textile industry and help protect jobs of lakhs of workers. These should also improve the working of the mills of the National Textile Corporation. I fully expect and shall insist upon the entire relief being passed on in the form of lower prices.

157. At this point, I would also like to ask manufacturers in all industries, where I have granted excise concessions, to pass on the excise relief to consumers in the form of lower prices. Administrative Ministries concerned are being requested to keep a close watch on the price behaviour of these commodities. I shall not hesitate to withdraw the concession, wherever there is evidence of manufacturers taking undue advantage of these concessions.

Electronics

158. We have been using the fiscal mechanism for some time to give a boost to the entire electronics sector. As a result of Government policy, substantial growth has taken place in this sector, giving employment to lakhs of young men and women. At present, concessional rates of customs duty of 60 per cent or 70 per cent ad valorem are available in respect of specified items of machinery for the electronics industry. These concessions have been reviewed. With a view to providing a stimulus and keeping in view the latest advances in technology, I propose to extend a uniform concessional duty of 60 per cent ad valorem in respect of 280 items of machinery for the electronics sector.

159. Customs duty on moulds, tools and dies required by the electronics industry is being reduced further from 60 per cent to 30 per cent ad valorem. The coverage of the graded structure of duties for raw materials, piece parts and components for the industry is being enlarged. Polycrystalline silicon will now bear a lower duty of 35 per cent instead of the existing 80 per cent.

160. Machinery and instruments required for the manufacture of Rural Automatic Exchanges based on indigenous technology will attract a lower rate

of duty of 30 per cent. A uniform rate of 100 per cent is being provided in respect of a large number of equipments for telecommunication transmission, satellite communication, cable, dig. data communication terminals, television transmission, studio and sound broadcasting. Non-electronic components of these equipments will bear a lower duty of 80 per cent. With a view to encouraging production of high-tech items like Large-Scale Integrated circuits, micro-processors and other micro-electronics items, import of 22 items of machinery will be allowed at 15 per cent ad valorem.

161. At present, computer's, computer systems and peripherals attract varying rates of duty ranging from zero to 147.5 per cent. As a rationalisation measures, a uniform rate of duty of 80 per cent ad valorem plus countervailing duty is being provided in respect of all computers, computer systems, computer peripherals and spare parts thereof. Software will continue to attract the existing rates of customs duty at 60 per cent ad valorem. As an export incentive, accompanying computer software and start-up spares imported under the policy on computer software export, software development and training will be allowed at the rate applicable to the hardware. Computerized Numerically Controlled systems and their parts at present attract a customs duty of 80 per cent. This is being lowered to 55 per cent ad valorem. Excise duty on Computerised Numerically Controlled systems is being reduced to 5 per cent ad valorem.

162. Colour TV sets of screen size exceeding 36 cms. and of assessable value exceeding Rs. 5,000 per set will now attract an excise duty of Rs. 2,000 instead of Rs. 1,750. However, such sets of value not exceeding Rs. 5000 will continue to attract a duty of Rs. 1500 per set as at present. Excise duty on audio magnetic tapes is being enhanced to Rs. 4 per square metre. Blank audio cassettes are being exempted from duty. Excise duty on computer software is being reduced from 25 per cent to 10 per cent ad valorem.

163. Certain other industries also require a boost for their further development. My proposals now cover a number of such industries.

Plastics

164. The House would recall that the customs duties on various plastic materials, such as LDPE, HDPE, PVC and polypropylene were lowered in September, 1987, in the wake of the steep hike in the international prices of these materials. International prices have since gone up even higher and there is need for further reduction in customs duties. I, therefore, propose to reduce the basic customs duty on LDPE from Rs. 3,000 to Rs. 2,000 per tonne and on HDPE from 30 per cent to 20 per cent ad valorem.

165. The auxiliary duty of customs on PVC is proposed to be converted from ad valorem to specific, and in the case of suspension grade PVC is being reduced to Rs. 2,000 per tonne and in the case of paste grade to Rs. 4,000 per tonne. In the case of polypropylene, auxiliary duty is being reduced from 45 per cent to 30 per cent ad valorem.

Automotive Sector

166. In the automotive sector, I propose to extend the concessional rate of 55 per cent customs duty in respect of parts for certain additional components to be manufactured by auto ancillaries for supply to fuel-efficient motor vehicles. Parts of specified as well as additional components of fuel-efficient two-wheelers and light commercial vehicles will now attract a lower rate of customs duty of 40 per cent ad valorem as against the current rate of 55 per cent ad valorem. Concessional rate of customs duty of 55 per cent ad valorem in respect of components required for the manufacture of fuel-efficient cars upto 1,000 cc under phased manufacturing programme is proposed to be made available for a further period from 1-3-1988 to 31-3-1990. Fuel-efficient motor cars of engine capacity exceeding 1000 cc manufactured under approved phased manufacturing programme will, however, now attract excise duty at the rate of 30 per cent ad valorem instead of the existing 25 per cent.

167. I propose to reduce the excise duty from Rs. 1,000 to Rs. 500 per body in respect of bodies of such three-wheeler auto-rickshaws, which are used by the general public in major cities.

Vegetable oils

168. In order to cut down on imports of vegetable oils, the Government had taken fiscal measures in the previous years so as to encourage domestic production of edible oils. These measures have had encouraging results. As a follow-up of the measures taken in the last two years, I propose to provide total exemption from excise duty in respect of refined safflower oil. Rebate for the use of solvent-extracted cotton seed oil in the manufacture of vanaspati is being increased from Rs. 3250 to Rs. 4000 per tonne. Rebate for the use of indigenous palm oil in the manufacture of vanaspati is also being made available at the rate of Rs. 3250 per tonne. Solvent-extracted sunflower and safflower oils will, henceforth, qualify for rebate at the rate of Rs. 3250 per tonne, if used in the manufacture of vanaspati. I am also proposing an increase in the rate of rebate from Rs. 320 to Rs. 640 per tonne for the use of rice bran oil in the manufacture of soaps.

Paper and Paper Board

169. I propose to reduce the excise duty on paper and paper board manufactured by small paper mills by Rs. 100 per tonne in each of the existing slabs. Paper and paper board manufactured by mills using agricultural residues such as cercal straw, bagasse, grasses and jute waste, etc. already attract a lower rate of excise duty of 10 per cent ad valorem plus Rs. 800 per tonne. I propose to reduce this duty further by Rs. 300 per tonne. Concession of 50 per cent of the excise duty available to certain new paper mills upto 31-3-1988 is being continued till 31-3-1990.

170. Specified items of machinery for manufacture of newsprint are being provided with a concessional rate of customs duty of 25 per cent ad valorem.

171. I also propose to provide for import of machinery for binding and multi-colour sheet-fed off-set printing machine by registered newspaper establishments at concessional rates of customs duty.

Rolling Bearing Industry

172. In respect of 21 items of machinery for the rolling bearing industry, a concessional duty of customs at 35 per cent ad valorem is being provided.

Watches

173. With a view to giving a further boost to domestic watch industry, I intend to reduce customs duty from 55 per cent to 35 per cent ad valorem in respect of certain horological machinery and testing instruments. The list of horological raw materials attracting concessional customs duty of 25 per cent ad valorem is being enlarged. In addition, my detailed proposals provide for a sound package for certain specified parts.

Glass and glassware

174. I propose to restore the concessional rate of excise duty of 30 per cent ad valorem in respect of glass and glassware manufactured by the semi-automatic sector.

Energy conservation

175. In our industrial processes, many of us have remained rather unresponsive to the need for energy conservation and energy recycling. The concept of energy conservation is still in its infancy in the country and we have to provide some incentive in that direction. Accordingly, 15 specified energy-saving equipments are being exempted from customs duty in excess of 40 per cent ad valorem.

Hotels

176. To promote tourism in the country, certain additional equipments required by hotels are being extended a concessional rate of customs duty of 90 per cent.

Rationalisation Measures

177. My proposals on the indirect taxes include certain rationalisation measures.

- (a) Industry has found the MODVAT system beneficial. The procedural problems faced in the initial stages have, by and large, been sorted out. I propose to rationalize rates of excise duty in respect of a few commodities, including paints based on synthetic polymers, trailers, furniture, phthalic anhydride and coated textiles as a part of MODVAT corrections.
- (b) The scheme of excise duty concessions applicable to small scale industry relating to air-conditioning and refrigerating appliances and parts thereof is being slightly modified to enable full utilisation of the MODVAT credit.

- (c) I propose to align the excise tariff relating to ferrous and non-ferrous metals and articles thereof with the corresponding chapters of the Harmonised System which would help reduce classification disputes. Tariff rates of excise duty in respect of items relating to iron and steel and copper are being revised. The effective rates of excise duty would by and large be maintained. A uniform rate of excise duty of Rs. 550 per tonne is being prescribed in respect of unmachined forgings and forged products of steel. The basic customs duty on ships, vessels and other floating structures imported for breaking up is being reduced from Rs. 1035 to Rs. 750 per Light Displacement Tonnage.
- (d) Certain proposals for rationalising and rounding off of rates of excise duty in respect of Petroleum products are being made. These proposals have no significant revenue implications.
- (e) The scheme of excise duty concession to manufacturers of tread rubber in the small scale sector is being revised as an anti-evasion measure.
- (f) As an anti-evasion measure, I am also proposing to enhance the basic customs duty in respect of certain compound alcoholic preparations of a kind used for the manufacture of beverages to Rs. 80 per litre or 270%, whichever is higher.
- (g) There have been some reports regarding under-invoicing in respect of imports of galvanised steel sheets, tin plates and cold rolled steel sheets. In order to deal with this problem, the basic customs duty in respect of these goods is being converted from ad valorem-cum-specific rates into specific rates.
- (h) Specific rates of excise duty in respect of air-conditioners upto 7.5 tonnes capacity are being revised. Specific rates are also being prescribed in respect of air-conditioners exceeding 7.5 tonnes but not exceeding 15 tonnes.
- (i) As an anti-evasion measure, excise duty on paste grade PVC is proposed to be increased from 40% to 60% ad valorem. The duty paid on the resin would be available as MODVAT credit. Effective rates of duty on coated textiles are being suitably revised.
- (j) In order to provide protection to the indigenous industry, I am proposing to enhance the basic customs duty in respect of Sodium Formaldehyde Sulphoxylate from 70% to 110% and Sodium Ferrocyanide from 70% to 100% and iron powder from 40% to 70%. The basic customs duty in respect of palm nuts and kernels is also proposed to be raised from 60% to 200% ad valorem.

178. Legislative changes and other changes of minor significance: Apart from the above proposals, certain amendments have also been proposed in the Finance Bill effecting changes in the excise and customs tariffs. These amendments are basically enabling provisions without any major revenue significance. Besides, there are a few minor proposals for continuing, amending or rescinding existing notifications including one for giving retrospective effect to an amending notification. To save the precious time of the House, I do not wish to dwell on them. I am also providing for amendment of some of the provisions of the Customs Act, 1962, details of which are in the Finance bill. A few amendments to the Central Sales Tax Act, 1956, are also proposed, so as to align the definitions of certain goods of special importance with reference to the Central Excise Tariff Act, 1985.

179. Copies of notifications giving effect to the changes in the customs and excise duties effective from 1st March, 1988 will be laid on the Table of the House in due course.

180. Anti-smuggling drive : Our anti-smuggling efforts yielded a seizure of Rs. 250 crores of contraband goods in 1987 which is the highest ever. I have instructed the concerned authorities to relentlessly continue the drive against smuggling, tax evasion and black money. I also seek the active cooperation of the State Governments, as it is with their assistance that we can succeed in this task. I hope and trust that the State Governments will also mount active steps against hoarding, black-marketing, smuggling and sale of smuggled goods.

181. Revenue effect : Details of all the pluses and minuses in respect individual items covered in my proposals are in the Explanatory Memorandum to the Finance Bill. In the aggregate, my proposals in respect of Customs and Central Excise duties outlined above are likely to yield additional revenue of Rs. 515.75 crores from Customs duties and Rs. 749.17 crores from Excise duties. The concessions and reliefs aggregate to Rs. 209.44 crores on the Customs side and Rs. 509.79 crores on the Excise side. The net additional revenue from Customs duties would, thus, be Rs. 306.31 crores and that from Excise duties Rs. 239.38 crores. In Excise duties, the Centre's share would be Rs. 117.23 crores and that of States, Rs. 122.15 crores. Out of the total net additional yield of Rs. 545.69 crores, the Centre's share would be Rs. 423.54 crores and that of the States, Rs. 122.15 crores.

182. Taking into account the additional yield from the modifications proposed in direct and indirect taxes and the revision announced a few days ago in postal tariffs, the year-end deficit for the next year is estimated at Rs. 7484 crores. Government reiterates its determination to closely monitor expenditure, maximise collection of revenues and contain the budgetary deficit.

183. Mr. Speaker, Sir, in framing the Budget proposals, my guiding principle has been the need to boost agriculture, help the poor and generate more employment, investment and growth. India's achievements since Independence are the result of the untiring efforts of all our people. Every section

of our people has contributed to build the country's economy. No single section or region or group can claim exclusive credit for it. The nation's Parliament as the supreme forum of our democracy has also made an invaluable contribution. In all humility, may I take this opportunity to request through you, Sir, all the Hon'ble Members of Parliament, to make this year's debate on the budget a participatory and constructive endeavour to evolve a nationally accepted strategy to achieve our goals.

184. Let us be proud of what all of us together have been able to do and if there are inadequacies or deficiencies, let us overcome them collectively. Let us all join in the exciting task of India's economic development and do so by making it a common fraternal partnership of the entire Indian people.

As our Prime Minister Shri Rajiv Gandhi said a couple of months ago :

"Our socialism is our own. It is not a foreign transplant. It is not cast in someone else's ideological mould. It is rooted in our own history, our culture, our realities. Gandhiji enjoined us to work for the Daridra Naryan, to wipe every tear from every eye. This constitutes the moral imperative of our socialism."

185. This is also the message that this Budget seeks to convey. Sir, I now commend this budget to the House.

K. S. SASTRI, Addl. Secy.